हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 फरवरी, 1986

प्रथम बैठक

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 26 फरवरी, 1986

	पृश्ट संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(7) 1
नियम 45के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(7) 23

बिल्ज (इंट्रोटयूस्ड–सदन की अनुमति से) –	
(i) दि पंजाब विलेज कामन लैण्ड्ज (रैगुले ान) हरियाणा अमैन्डमैंट बिल 1986	(7) 25
(ii) दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैट बिल, 1986	(7) 25
(iii) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज (सैकिण्ड अमैन्डमैंट) बिल, 1986	(7) 26
(iv) दि हरियाणा अर्बन (कन्ट्रीोल आफ रैन्अ एन्ड एक्कि ान अमैडन्डमैट बिल, 1986	(7) 26
(v) दि हरियाणा हाउसिग बोर्ड (अमैडमैट) बिल, 1986	(7) 27
(vi) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैटमैट एन्ड वैलीडे ान) बिल, 1986	(7) 28
(vii) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिण्ड अमैडमैट) बिल, 1986	(7) 28
वर्श 1986–87 के बजट पर सामान्य चर्चा	(7) 29
अनैक चर	(7) 75

हरियाणा विधान सभा

बुधवार 26, फरवरी 1986

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान इसभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9–30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब क्वे चंज होगे।

Declaration of Kurukshetra as industrially backward area

*** 1099 Ch. Sahab Singh Saini:** Will the Minister for Industreis be pleased to state—

(a) Whether ther is any proposal under consideration of the Government to declare Kurushetra as a industrially backward area; and

(b) If so, the steps, if any, taken in this respect together with the time by which the said proposal is likely to mature?

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया):

(क) हां।

(ख) मामले को भारत सरकार के साथ उठाने बारें आव यक आंकड़े एकत्रित किए जा रहे है क्योंकि किसी भी क्षेत्र को औद्योगिक पिछड़ा घोशित करने के लिए भारत सरकार ही सक्षम है, अतः इस मामले में कितन समय लगेगा इसका पूर्वानुमान नही लगाया जा सकता।

चौधरी साहब सिंह सैनः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सवाल का जवाब दिया है कि इस बारें में आव यक आंकड़े एकत्रित किये जा रहे है। मै आपके द्वारा मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि आंकड़े कब से एकत्रित करने भुरू किए है ओर एकत्रित करने में कितना समय लगेगा? अध्यक्ष महोदय, आपकों पता है कि कुरूक्षेत्र में देवीदासपुरा के पास तीन हजार एकड़ जमीन हुड्डा ने इंडस्ट्रीयल एरिया के लिए एक्वायर कीथी और वहां प्लाट परे तौर परनही बिक रहे है क्योंकि उन प्लाट्स का रेट बहुत महंगा है।

श्रीमती शकुन्तला भगवाडियाः अध्यक्ष महोदय, 11.2.1985 को मख्य मंत्री महोदय कुरूक्षेत्र गए थे उस समय उन्होने लोगों को यह आ वान दिया था कि कुरूक्षेत्र को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया घोशित करने के लिए हम भारत सरकार को केस प्रस्तुत करेगे अब हमारे कुरूक्षेत्र में में जो जिला स्तर के महा प्रबन्धक है, और सांख्यक अधिकारी है वे आंकड़े एकत्रित कर रहे है। इस बारें में यह बताना बहुत मु कल है कि कितने समय में यह आंकड़े एकत्रित हो जायेगे।

चौधरी फूल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि राज्य में और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जिनको ओद्योगिक दृश्टि से पिछड़ा हुआ घोशित किया गया है? 1983 में अम्बाला तहसली को औद्योगिक दृश्टि से पिछड़ा हुआ घोशित करने के लिए इस सदन में एक प्रस्ताव आया था और डिस्कस हुआ था और यह आ वासन दिया गया था कि सरकार सैन्ट्रल गवर्नमैट के साथ इस मामले को टेक–अप करेगी। मै मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि इस बारें में क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़ियाः अध्यक्ष महोदय, सेठ राम दास धमीजा का अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया घोशित करने क लिए एक रैजोल्यू ान आया था और दिये गये आ वासन के अनुसार हमने उस बारें में भारत सरकार को केस भेज रखा है। जब भी इस बोरं में मंजूरी आएगी हम उस पर कार्यवाही भुरू कर देगे।

श्री कंवल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपक द्वारा मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा सरकार होटल इंडस्ट्री मानती है और जो सुविधाए भारत सरकार इनकों देती है क्या हरियाणा सरकार भी उनको वैसी सुविधाएं दने की दि ाा में कोई कार्यवाही करना चाहती है?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़ियाः अध्यक्ष महोदय, इस बारें में मुझे ज्ञान नही है। लेकिन काटेज इंडस्ट्री को इंडस्ट्रा मानते है और जो सुविधाएं काटेज इंडस्ट्री के व्यक्ति चाहते है उनके बारें में हमारा विभाग उनको सहयोग देता है।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, हर सै ान में यह बात आती है कि फलां जिले को या तहसील का इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया करार दिया जाए। हमारे हरियाणा प्रदे ा के 12 जिले है, इन सभी जिलों को सर्वे करवा लियाजाए कि कौन कौन सा जिला तहसील या ब्लाक इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया करार दिया जा सकता है मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हरियाणा के सभी जिलों का इस बारें में सर्वे करवाने के लिए भारत सरकार को लिखेगी?

श्रीमती शकुन्तला भगवाडियाः अध्यक्ष महोदय, हम हरियाणा प्रदे ा में इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए और कई जगहों को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया घोशित करवाने के लिए हमे ाा प्रयत्न ाील रहते है। इस बात का इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों जब मुख्य मंत्री जी विदे ा गए थे, उस समय वहां पर लोगों से यह कह कर आए थे कि आप हरियाणा के अन्दर इंडस्ट्री लगाये आपकों हम इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहन देगे। भारत सरकार से हमारा प्रयत्न भी जारी है कि हरियाणा में काई ऐसा जिला न रहे जहां पर इंडस्ट्रीज न लगें। लेकिन किसी

भी जगह को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया घोशित करने के लिए भारत सरकार ही सक्षम है।

चौधरी साहब सिंह सैनीः अध्यक्ष महोदय, मैने पहले भी पूछा था कि इस बारें में आंकड़े एकत्रित करने में कितना समय लेगो, उसका मंत्री महोदया ने कोई जवाब नही दिया। मै फिर गुजारि ा करनाचाहूंगा कि कुरूक्षेत्र ऐसा स्थान ळै जो जी0 टी0 रोड पर स्थित है इस जी0 टी0 रोड पर अमृतसर से दिल्ली तक इंडस्ट्रीज डिवैल्पड है लेकिन कुरूक्षेत्र में इंडस्ट्रीज नही है, उसका कारण यह है कि वहा प्लाट्स बहुत महंगे है और ईडस्ट्रीयलिस्ट्स को भी कोई इनसैटिव नही है मै आपके द्वारा मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं क क्या इस बारें में भारत सरकार को लिखा गया है, अगर लिखा गया है तो कब लिखा गया? इस बारें में आंकड़े तो स्टेट के जिले से ही एकत्रित करने है वे एकत्रित करने में कितना समय लगेगा? मै यह आ वासन चाहता हूं कि कितना जल्दी से जल्दी कुरूक्षेत्र इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया करार दे दिया जाएगा?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़ियाः अध्यक्ष महोदय हमने उद्योग विभाग के अधिकारियों को आंकड़े एकत्रित करने के लिए आदे ा दे रखे है और वे इस बारें में कार्यवाही कर रहे है। मैने पहले भी कहा है कि इस बारें में यह नही बताया जा सकता कि कितना समय लगेगा। यह मुख्य मंत्री जी का आ वासन है इसलिए ज्योंही आंकड़े एकत्रित हो जाएंगे उसके बाद हम प्रयास करेगे

और अपने अधिकारियों को कहेगे कि जितना जल्दी हो सके इस केस को राज्य सरकार के पास भिजवाए जब भी आकड़े राज्य सरकार के पा आ जाएंगे हम भारत सरकार को लिखेगे।

श्री कंवल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने मेरे सवाल का जवाब दिया है कि हम काटेज इंडस्ट्री मानते है लेकिन मैने होटल इंडस्ट्री के बारें में पूछा था कि हरियाणा सरकार होटल इंडस्ट्री को इंडस्ट्री मानती है या नहीं मै आपके द्वारा मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि भारत सरकार इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरियाज में होटल इंडस्ट्री लगाने के लिये जो लोन और सबसिडी की सुविधाएं देती है, क्या वे सुविधाए हरियाणा सरकार भी उनको देती है? कया वे सुविधाएं हरियाणा सरकार को भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः अध्यक्ष महोदय, इस बारें में मुझ ज्ञान नही है कि हरियाणा सरकार होटल इंइस्ट्री को इंडस्ट्री मानती है या नही।

चौधरी कुन्दन लालः स्पीकर साहब, जींद को भारत सरकार ने औद्योगिक दृश्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोशित किया हुआ है लेकिन मेरा हल्का सफीदों सब डिविजन है, वह औद्योगिक दृश्टि से पिछड़ा हुआ घोशित नही किया हुआ। मै आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सफीदों सबडिविजन को औद्योगिक दृश्टि से पिछड़ा हुआ घोशित न करने के क्या कारण

है औ उसको कब तक औद्योगिक दृश्टि से पिछड़ा हुआ करार दे दिया जाएगा?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय किसी जगह को औद्योगिक दृश्टि से पिछड़ा हुआ करार देने के लिए भारत सरकार ने नार्म्ज तय किये हुए हैं तीन कैटगीरज है, ए बी, सी। (ए) कैटेगरी में 25 परसैन्ट सबसिडी ओर 15 लाख रूपए अनुदान दिया जाता है और (सी) कैटगरी में 10 परसैन्ट सबसिडी और 10 लाख रूपए अनुदान दिया जात है। यह सुविधा पहले जींद मे ंनही थी लेकिन अब प्रौपर जींद, कलायत, सफीदों और नरवाना ब्लाक तक सारा एरिया कैटेगरी (सी) में औद्योगिक दृश्अि से पिछड़ा हुआ घोशित कर दिया गया हैं

चौधरी अजमत खां: स्पीकर साहब, मेवात की इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया करार दिया हुआ है, यह सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी है। वहां पर नूंह और हथीन में इंडस्ट्रीज लगाने के लिये जमीन भी एक्वायर हो चुकी है लेकिन वह जमीन पांच साल से वैसे ही पड़ी हुई है। वहां पर कोई इंडस्ट्री नही लगी है। मै मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर इंडस्ट्रीज लगाने का काम जल्दी भ्रुरू किया जाएगा?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया: अध्यक्ष महोदय पुनहाना फिरोजपुर झिरका, ताउडफ मे ंपहले ही काम भ्रुरू है। मुझ इस बारें में याहद है कि वहां पर आई र ट्रैक्अर वालें ने 25–30

इंडस्ट्रीय भौड्ज अपने बनाए हुए है। माननीय सदस्य वहां पर लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए हमारे पास लाएं, हम उनकी पूरी तरह से इनसैटिव देंगे और उनको पूरा सहयोग देगे।

Double Link Road

***1107 Sh. Fateh Chad Vij**: Will the Minister for public works (B & R) be pleased to state the names of villages, constituency wise/circle wise which have been provided double link roads so far in the state and the names of the villages which are likely to be connected with double link roads during the year 1986-87?

श्री अध्यक्षः इस सवाल का जवाब देने के लिए मंत्री महोदय ने एक्सटै ान मांगी है जोकि मैने दे दी है। उनसे प्राप्त पत्र इस प्रकार है–

"D.O.No. 29.8.86 लो0 नि0–4 (3)

लोक निर्माण (भवन व सड़के) मंत्री

हरियाणा सरकार

चण्डीगढ़

21 फरवरी, 1986

विशयः तारांकित विधान सभा प्र न नं0 1107

प्रिय सरदार साहिब,

विधान सभा तारांकित प्र न नं0 1107 जोकि दिनांक 26.2.86 की सूची में श्री फतेह चन्द विज, सदस्य हरियाणा विधान सभा के नाम दर्ज, के विशय में यह कहना है कि उपरोक्त प्र न का उत्तर अभी तैयार नही हुआ है, क्योंकि अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना एकत्रित की जानी है। इसलिए इसमें और समय लगेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्र न का उत्तर देने के लिये दो मास का समय और दिया जाये।

आपका

हस्ता0

(अमर सिंह)

श्री तारा सिंह,

अध्यक्ष

हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1102

यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या बहिन भाान्ति देवी, सदन में उपस्थित नही थी।

Branch Primary Schools in Narnaul Sub-Division

***1080 Sh. Nihal Singh:** Will the Minister of state for Education be pleased to state—

(a) Whether there are any branch primary schools in Narnaul Sub-Division (Civil); and

(b) If so, the number there of together with the time by which the aforesaid schools are likely to be made full fledged in-dependent schools?

Minister of State for Education (Sh. JagdishNehra):

(a) Yes

(b) There are eleven Branch primary schools in Narnaul Sub-Division (Civil). Government is actively considering the feasibility of making them full-fledged primary schools.

चौधरी इन्द सिंह नैनः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से ि ाक्ष मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो ब्रांच प्राईमरी स्कूल है उनको खोलने का क्या क्राइटेरिया है? इसके लिए सरकार की क्या नीति है यानि इसमें कितने बच्चे होने चाहिए और ये ब्रांच प्राईमरी स्कूल मेन स्कूल से कितनी दूरी पर होने चाहिए? दूसरा सवाल यह कि ब्रांच प्राईमरी स्कूल को फुल–फलैज्ड प्राईमरी स्कूल बनाने का क्या क्राइटेरिया है?

श्री जगदीश नेहराः जो ब्रांच प्राइमरी स्कूल खोलत है उसमें पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक क्लासें लगती है और फुल प्राईमरी स्कूल सेपहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक क्लासे लगती है। जहां तक ब्रांच प्राईमरी स्कूल को फुल प्राईमरी स्कूल बनाने का क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि कम से कम 30 बच्चे होने चाहिए। दूसरे बच्चों की सुख्या के हिसाब से 2–3 या 4 कमरे होने चाहिए। यदि पंचायत की तरफ से या गांव वालें की तरफ से कमरे ि ाक्षा विभाग को दे दिए जाते है और बच्चे भी 30 हो तो उस ब्रांच प्राईमरी स्कूल को फुल प्राईमरी स्कूल बना देते है।

चौधरी फुल चन्दः क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेगे कि इस समय राज्य में कितने ब्रांच प्राईमरी स्कूलज् है और इन ब्रांच प्राईमरी स्कूलों को कब तक फुल प्राईमरी स्कूल बना दिया जायेगा?

श्री जगदीश नेहराः इस समय राज्य में ब्रांच प्राईमरी स्कूलों की संख्या 637 है जैसा कि मैने बताया है, यदि ि ाक्षा विभाग को उचित एकोमोडे ान गांव वालों की तरफ से मिल जाये ओर दूसरी भार्ते वे ब्रांच प्राईमरी स्कूल पूरी करते है तो उनको फुल प्राईमरी स्कूल बना दिया जाता है।

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर यह देखने में आया है कि इन ब्राच प्राईमरी स्कूलों में एक ही टीचर होता है

कई बार वह टीचर छुटटी ले लेता है या बीमार हो जाता है तो बच्चों की पढ़ाई नही हो पाती और उन का नुक्सान होता है। मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन ब्रांच प्राइमरी स्कूलों में एक टीचर की बजाये दो टीचर लगाने का प्रबन्ध करेगी या लीव अरेन्जमैट करेगी ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुक्सान न हो सके।

Change in educational pattern

*** 1093 Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister of state for education be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to change the exiting pattern of education in the state;

(b) Whether there is also any proposal under consideration of the Government to introduce technical and industrial education in the curriculum; and

(c) Whether there is also any proposal under consideration of the Government to send students for study tours to other states during the vacation period?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा):

(क) जी नही। परन्तु भारत सरकार नई राश्ट्रीय ि ाक्षा नीति को तैयार करने की प्रक्रिया में लगी हुई है।

(ख) राज्य में जमा 2 स्तर पर 41 वोके ानल संस्थाओं में वोके ानल ि ाक्षा दी जा रही है इन संस्थाओं में टैक्नीकल तथा कर्मियल ट्रेडज में प्रि ाक्षण देने की व्यवस्था है। फिलहाल और पाठयक्रम परिवर्तन सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नही है।

(ग) जी नही, परन्तु सम्बन्धित महाविद्यालय अपने स्तर पर अवका ा अवधि के दौरान विद्यार्थियों को अन्य राज्यों में अध्ययन दौरों पर भेजने का प्रबन्ध करते है।

सेठ राम दास धमीजाः स्पीकर साहब, इन्होने मेरे सवाल के पहले भाग उत्तर में कहा है 'नो'। इस बारें में मैने पूछा था कि क्या सरकार राज्य में विद्यमान ि ाक्षा पैट्रन को परिवर्तन कर रही है। जो जवाब इन्होने दिया है वह ठीक नही लगता है क्योकि जो पालिसी ि ाक्षा की इस समय चल रही है, वह अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। हमने अब तक बहुत कुछ बनाया है लेकिन हमारे ने ालन करैक्टर में कमी हुई है। यदि ि ाक्षा पालिसी को बदल दिया जाये ओर आज के जमाने के हिसाब से इसमें परिवर्तन कर दिया जाये तो यह बहुत अच्छा होगा क्योंकि इससे राश्ट्र के चरित्र में बढ़ौतरी हो सकेगी। मेरे पूछने का मकसद सिर्फ यही है कि क्या सरकार मौजूदा ि ाक्षा पालिसी को बदलने का कोई विचार रखती है।

श्री जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, 'नो' में इनके पहले भाग का जवाब इस लिए दिया गया है कि हरियाणा सरकार अपनी

नई ि ाक्षा नीति की पोलिसी कोर्ठ नही बना रही। इन दिनो केन्द्र सरकार नई राश्टीय ि ाक्षा नीति तैयार कर रही है। इस सारे में हरियाणा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लैवल पर, ब्लाक लैवल पर और राज्य लैवल पर चिार किया। इसके साथ ही साथ तमाम राजनैतिक पार्टियों के साथ भी विचार विम र्ा किया गया। फिर सरकार ने सारी डिस्क ान के बाद केन्द्रीय सरकार को अपनी राय नई राश्ट्रीय ि ाक्षा नीति के बारें में बना कर भेजी है। जो नई पालिसी केन्द्रीय सरकार बनायेगी हरियाणा सरकार उस राश्ट्रीय ि ाक्षा नीति को सबसे पहले एडौप्त करेगी।

सेठ राम धमीजाः मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस समय राज्य में आई0 टी0 आई0 बहुत कम है जबकि इनकी अधिक जरूरत है। क्या सरकार वोके ानल इन्स्टीच्यू ांज की बजाये आई0 टी0 आई0 अधिक खोलेगी ताकि नौजवानों को कोसिज करने के बाद कुछ रोजगार भी मिल सके?

श्री जगदीश नेहराः आई0 टी0 आई0 के बारे में तो मै इस समय कुछ नही बता सकता क्योंकि इनका इस सवाल से सम्बन्ध नही हैं लेकिन जो हमने वोके ालन इन्स्टीच्यू ान्ज खोले हुए है उनमें कोई र ा नही है। ये इन्स्टीच्यू ान्ज राज्य में इस समय 41 है इन 41 इन्स्टीच्यू ान्ज में पिछले साल सिर्फ 5187 बच्चे थे। इनमें और बच्चे भी आ सकते थे। सरकार ने 7वी पंचवर्शीय योजना में और भी वोके ानल इन्स्टीच्यू ान्ज खोलने

का प्रावधान किया है। यदि इन इन्स्टीच्यू ान्ज में अधिक र ा हुआ तो सरकार ये इन्स्टीच्यू ान्ज और अधिक खोल देगी।

सेठ राम दास धमीजाः तीसरी बात मै यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से विधान सभा की कमेटियां एक दूसरे प्रदे ाो में जाती है उसी प्रकार बच्चों को भी दूसरे प्रदे ाों में ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे देख सके कि वहां पर क्या हो रहा है और दूसरे प्रदे ा के बच्चे यहां आ कर देख सके कि यहां पर क्या हो रहा है मै इस बारें मे ंसरकारसे जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसी कोई नीति बनोन पर विचार करेगी कि यहां बच्चे दूसरे प्रदे ाों में जा सके और वहां के बच्चे यहां पर आ सके?

श्री जगदीश नेहराः सरकार की तरफ से टूर का कोई इन्तजाम नही है। सभी सदस्य स्कूलों और कालेजों में पढ़े है। सभी को पता है कि अवका ज्ञ के दिनों में स्कूल/कालेज के बच्चे अपने खर्चे पर दौरे पर जाते रहत है। मै इन्हें बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से कोई प्रावधान इस बारें मे नही है।

श्री भले रामः मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 41 इन्स्टीच्यू ान्ज इन्होने बताए है उनमें कौन कौन सी ट्रैड है? दूसरे आई0 टी0 आई0 में और इन इन्स्टीच्यू ान्ज में क्या फर्क है?

श्री जगदीश नेहराः आई0 टी0 आई0 में तो डिप्लोमा कोर्स होता है। इसमें हम ट्रेड की बेसिक नालेज देते है।

वोके ान इन्स्टीच्यू ान्ज में जो हम ट्रेड दे रहे है वह इस प्राकर है–

Boiler attndant, Office secreataryship, Furniture maker and designer, Lineman, Receptionist, Banking Assitant, Mechanical and technical machinery, Bakery and confectionery, Accountancy and audition, Two & Three wheeler repari, Designer & Master cutter, Heat treatment Agriculture mechanic, Stock Keeper Moter vehicl body builder photography, Tanneries an crop production.

श्री अमीर चन्द मक्कड़: अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन 41 वोके ानल इन्स्टीच्यू ान्ज को इन्होने जिकर किया है और जो ट्रैड यहां बताई गई है क्या इनमें पूरा सामान है? यदि पूरा सामान बच्चों के सीखेन के लिये नही है तो वह कब तक मुहैया कर दिया जायेगा?

श्री जगीदश नेहरा: ये वोके ानल इन्स्टीच्यू ान 1983–84 में खोले थे तब इनके लिये सरकार ने एक करोड़ रूपया दिया था। बाद में फिर 1 करोड़ 10 लाख रूपया और दिया हैं इस साल फिर इस काम के लिए 2 करोड़ 20 लाख रूपये दे रहे है। मै माननीय सदस्य को बतना चाहूंगा कि इन इन्स्टीच्यू ान्ज में बेसिक इन्फास्ट्रकचर का पूरा सामान मौजूद है।

श्री कंवल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो इन्होने 10+2 का सिस्टम लागू किया है इसकी वजह से प्री–यूनिवर्सिटी क्लास बन्द कर दी गई? साथ ही मै यह

भी जानना चाहता हूं कि जो हमारे 10+2 सिस्टम वाले इंस्टीच्यू ान्ज है उनमें जितने बच्चे ऐडमि ज्ञन चाहेगे क्या उन सबाकेाां वहां पढ़ाने का इन्तजाम है?

श्री जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, इन्होने जो सवाल किया है वह दुरूस्त है जो बच्चे इस साल जमा एक में गए वह अगले साल जमा दो में जाएंगे और उनके बाद पार्ट वन में जाएंगे। पहले सिस्टम 10+1+3 का था लेकिन अब सिस्टम 10+2+3 का हो जाएगा। तो जिस हिसाब से बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे प्री–यूनिवर्सिटी क्लास खत्म हौती जाएगी।

श्री कंवल सिंहः क्या सभी बच्चे को पढ़ाने के लिये आपके पास सुविधा है।

श्री जगदीश नेहराः सारी सुविधाएं है। अध्यक्ष महोदय, जैसे पिछली बार सवाल आया था और मैन बताया था कि प्राइवेट और गवर्नमैंट 250 कालेजिज है जिनमें यह सुविधा है। इसी तरह से जितने सीनियर सैकेडरी स्कूल्ज है जोकि भाायद 113 करीब है, उन सबमें यह सुविधा है। इसी तरह से 60 हाई स्कूलों में जो इंटीरियरऔर रूरल एरियाज में है उनमें भी यह सिस्टम लागू किया गया हैं इसलिए यह कहा जा सकता है कि इसमामले में हम पूरी तरह सक्षम है और किसी तरह की कोई दिक्कत नही है।

चौधरी कुन्दन लालः माननीय अध्यक्ष जी, मै मंत्री जी से यह जाननचा चाहूंगा कि जितन लड़के दाखिले के लिए आते है

क्या उन सबाकों दाखिला मिल जात है? अगर नही मिलता तो उनके लिए सरकार कोई इन्तजाम करेगी?

श्री अध्यक्षः क्या आपके नोटिस में कोई लड़का है जिसकों दाखिला नही मिला?

चौधरी कुन्दन लालः जी है।

श्री जगीदश नेहराः अध्यक्ष महोदय, जिनको दाखिला मिलना चाहिए उनको हर जगह दाखिले की सुविधा है। जहां ज्यादा र ा है वहां कुछ रिस्ट्रक ान लगाई गई है। ये जगह हे नारनौल, फरीदाबाद, गुडगांवा और रोहतक। यह रिस्ट्रिक ान वहा लगाई है। जहां साईस की क्लासिज है और स्पोटिग हाई स्कूल में 10+2 सिस्टम लागू हैं हर जगह बच्चों को दाखिले की सुविधा है। किसी को दाखिले के लिए इन्कार नही किया जा सकता।

श्री एस0 सी0 चौधरीः अध्यक्ष महोदय, अभी अभी मंत्री जी ने फरमाया कि कुछ स्टे ान्ज पर दाखिले के लिए रिस्ट्रिक ान लगाई गई है। मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां ि ाक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों की लाइने लगती हों वहां किसी तरह की रिस्ट्रिक ान लगाने की बजाए क्यों न फरदर एकमोडे ान वगैरा का अरेन्जमैंट करके उन्हे दाखिला दिया जाए?

श्री जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, रिस्ट्रिक ान केवल मार्क्स की परसैन्टेज की है साईस क्लासिज में दाखिले के लिए इसे 45 की बजाए 50 परसेन्ट कर दिया है। इससे यह तो हो

सकता है कि कही 50 परसैन्ट वाले 400 बच्चों को ले लिया हो और दूसरे बच्चों को न लिया गया हो। जहां तक फरीदाबाद का संबंध है, वहां दिक्कत यह है कि वहां दिल्ली के बच्चे अधिक आते है। हरियाणा के बच्चों को इन्कार करने की कोई बात नही है। हो सकता है दिल्ली के थर्ड क्लास में पास बच्चो या यू0 पी0 से आने वाले लोअर परसैन्टेज वाले बच्चों को वहा दाखिला न मिला हो।

श्री ए0 सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, मै माफी चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यू0 पी0 से फरीदाबाद में किसी बच्चे के आने का स्कोप नही है क्योंकि वह एक साईड मे पड़ता हैं दूसरे जिन बच्चों को वहां ऐडमि ान रिफ्यूज किया गया, कुछ बच्चों को छोड़ करके सभी प्योर हरियाणवी थे। वे वहां एकमोडेट नही हो पाए सिर्फ इस वजह से क्योंकि सरकार ने उनके दाखिले क लिए जरूरी प्रावधान नही किया। यह तो फरीदाबाद की खु ाकिस्मती है कि जिन बच्चों को ऐडमि ान रिफ्यूज किया गया उनमे से आधे से ज्यादा बच्चों को डी0 ए0 वी0 मैनेजमैट ने ऐकमोडेट किया लेकिन फिर भी यह फैक्ट है कि सैकड़ों बच्चें ि ाक्षा से महरूम रहे। जो साल गुजर गया उसमे ंजो हुआ उसकों तो मै उखेड़ना नही चाहता नलेकिन आगे की पे ाबन्दी के लिए मै जानना चाहता हूं कि क्या दाखिले पर रिस्ट्रिक ान लगाने की बाजए सरकार ऐसे कदम उठाएगी कि बच्चे दाखिले में महरूम न हो?

श्री जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद मे ंऐकमोडे ान अधिक करने के लिए जो गवर्नमैंट कालेज था वहां हमने अलग लड़कियों का विग बनाया। डी0 ए0 वी0 कालेज जो खुला है वहां भी मै गया था। उन्होने भी अपना एक स्तर बनाया है। इसके अलावा, वहां 10+2 की ि ाक्षा देने वाला एक बुवायज सीनियर सैकेडरी स्कूल है और एक गर्लज सीनियर सैकैडरी स्कूल है। साथ ही बल्लभगढ़ है। तिगाम में 10 किलोमीटर की दूरी पर एक और कालेज हैं। ऐसी बात नही है कि किसी को दाखिले के लिए रिफ्यूज किया गया हो लेकिन फिर भी सरकार कोि ा ा करेगी कि हरियाणा के किसी बच्चे को असुविधा न हो।

बहिन शांति देवीः क्या मंत्री जी बताएंगे कि वोके ानल स्कूलेां में जो ट्रेड्ज रखे गए है, उनकों सरकार अपनी तरफ से दे देती है या ये स्कूलों के मांगने पर दिए जाते है?

श्री जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि भ्ारू में यानी 1983–84 में केवल 24 स्कूल खोले गए थे। एक स्कूल भाहर में होता था और एक गांव में होता था उनकों सरकार ने इस ढंग से ऐडजस्ट किया था जिससे सुविधा हो। इसमें मांगने की कोई बात नही। बहिन जी जहां के बारें में कहेगी कि वहा ऐसा स्कूल खोलना जरूरी है और बच्चे भी वहां दाखिला हो सकते है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है।

बहिन शांति देवीः अध्यक्ष महोदय, वोके ानज स्कूलों 10+2 के स्कूलेां और आई0 टी0 आइज0 वगैरा में जो बच्चां को दाखिले के लिए नि चत डेट दी जाती है उसमें बहुत सी ऐप्लीके ान्ज आ जाती है लेकिन लिया बहुम कम बच्चों को जाता है जितने नि चत होते है, 15 या 20 बच्चे, वे ले लिये जाते है ओर बाकी के बच्चे बच जाते है। उसके बाद कुछ बच्चे आते नही। उन जगहों को दुबारा ऐडव्टाईजमैट करके भरा जाता है। जिन बच्चों ने पहले फार्म भरे थे वे रह जाते है और नए बच्चे दाखिल हो जाते है। होना चाहिए कि जिस परसैटेज तक के च्चे पहले दाखिल हुए थे उससे नीची परसैटेज वाले उन बच्चों को दाखिला मिलना चहिए जिन्होने पले ऐप्लाई किया था। उनको वेटिग लिस्ट में रख लेना चाहिएं। लेकिन दो दो, तीन तीन बार ऐडवर्टाइजमैंट करके दूसरे बच्चों को दाखिला दिया जात है और वे रह जाते है। करनाल में तो ऐसा देखने में आया है। क्या सरकार इस बात का कोई उपाय करेगी?

श्री जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, बहिन जी ने दो तीन बातें कही है इन्होने 10+2 प्रणाली वाले स्कूल की बात है, जैसा मैने पहले बताय, उसमें साईस क्लासिज के अलावा कोई दिक्कत वाली बात नही है। वोके ानल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिग इंस्टिच्यू ान्ज के लिए भी इसी तरह का प्रावधान है कि जो अधिक नम्बर वाले लड़के है उनका नम्बर पहले आएगा और दूसरे लड़कों के नम्बर बाद में आएगा। जितनी सीटे होती है उनको

इसी हिसाब से भरा जाता है। मान लो हमने 80 बच्चे लेने है तो हम नम्बरों के हिसार से ऊपर वाले 80 बच्चों को ले लेगे। इनके लिए बार–बार इन्टरव्यू होगा ऐसी बात नही है।

चौधरी हुक्म सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपकी मार्फत मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नौर्मज के अनुसार एक फुलफ्लैज्ड आई0 टी0 आई0 खोलने में कितने पैसे लगते है और उसमें कुल कितने बच्चों को दाखिला मिलता है?

श्री जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, मै माफी चाहूंगा क्योंकि आई0 टी0 आईज0 वाला विभाग मेरे पास नही है।

सेठ राम दास धमीजाः अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है पौलिटैक्निक्स में लगभग 75 परसैट से ऊपर के नम्बरों वाले और आई0 टी0 आइज0 में 65 परसैट से ऊपर के नम्बरों वाले बच्चों को दाखिला मिलता है। इसमें कोई बेइन्साफी नही है क्योंकि मैरिट पर बच्चे लिए जाते है लेकिन इससे बहुत सारे बच्चे दाखिले से वंचित रह जाते है। क्या सरकार बच्चों की संख्या को देखते हुए इन इस्टिच्यू ान्ज में और सीटें बढ़ाने की कोि ा ा करेगी?

श्री जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, इसे लिए भी मै माफी चाहूंगा क्योंकि जैसे मैन पहले अर्ज किया यह महकमा मेरे पास नही है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जहां दाखिले का ताल्लुक है वह मैरिट के हिसाब से होता है। अगर

सीटे किसी कालेज में पांच सौ है और दाखिल होने वाले सात सौ है तो मैरिट के हिसाब से पांच सौ ही आयेगे, उनहे ही दाखिल किया जायेगा लेकिन जरूरत को सामने रखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रख कर अगर ऐस कोई साधन हुआ ओर इन्तजाम कर सके तो हम सीटे बढ़ाने की जरूर कोि ा ा करेगे।

Construction of bye-pass on G.T. road in district Faridbad

***1131 Sh. A.C. Chaudhry:** Will the Minister for Public Works (B & R) be pleased to state

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a by-pass in district Faridabad;

(b) Whether there is also any proposal under consideration of the Government to construct lanes/roads by the side of G.T. Road in district Faridabad; and

(c) If the reply to parts (a) & (b) above, be in the affirmative, the time by which these proposals are likely to materialise?

Publick Worksk Minister (Sh. Amar Singh):

(a) No.

(b) No.

(c) Question does not arise.

श्री ए0 सी0 चौधरी: स्पीकर साहब, मै आपसे माफी चाहता हूं परन्तु मै मंत्री जी का ध्यान, पिछले सै ान में जो बात

हुई है, उसकी ओर आकर्शित करना चाहूंगा। स्पीकर साहब, पिछले सै ान में जब मुख्य मंत्री साहब स्टेट में हुए एक्सीडेट्स केसिज में गई जानों का ब्यौरा दे रहे थे, उस वक्त मैने एक स्पैसिफिक क्वै चन पूछा था कि फरीदा बाद जी0 टी0 रोड के दोनों तरफ बसा हुआ है और ने ालन हाई वे होने के कारण वहां एक्सीडैन्टस होते है जिससे लोगों की कीमती जाने जाती है उस टाईम मुख्य मंत्री जी ने कैटेगरिकली ए यारेन्स दी थी कि वहां के बारे में साइड लेन के विशय में चिार कर रहे है ओर उस टाईम पर साथ ही इसबाई पास का भी इ ू आया था। उस समय यही कहा गया था कि बाईपास भी विचारधीन है। अब मंत्री महोदय ने सी0 एम0 साहब की बात को सुपरसीड करके दोनो बातें के बारें में 'नो' कह दिया है। मै इनसे 'नो' कहने का कारण जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्षः इन्होने विचार करके ही 'नो' कहा है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने जो फरमाया है वह हकीकत है लेकिन मै उन्हें बताना चाहूंगा कि हमने बाकायदा एस्टीमेट बना कर भारत सरकार को भेजा था कि फरीदाबाद, दिल्ली–आगरा रोड पर है और उसके बीच ने ानल हाई वे गुजरती है इसलिए इसके साथ सर्विज रोड बनाया जाये। स्पीकर साहब, जब भी ने ानल हाई वे की एक्सपैन् ान होती है तो उसकी बाकायदा भारत सरकार मंजूरी लेनी होती है। भारत सरकार ने इस बात की मंजूरी नही दी कि इसके साथ सर्विस रोड

बनाया जाये या बाई पास बनाया जाये क्योंकि यह पहले ही फोर लेन है। उसके अलावा जैसे कि मुख्य मंत्री जी ने अ योरेन्स दी थी उस बारें में हमने हुड्डा को से बात की थी क्योंकि यह सड़क सैक्टर 5, 6, 11, 15ए0 और 16ए0 से गुजरती हैं हमने हुड्डा को सन् 1984 में लिखकर भेजा था और बार बारे उनसे मीटिग भी करते रहे है लेकिन उन्होने इस बारें में कोई अ योरेन्स नही दी और न ही हमारे पास पैसा जमा कराया। इस वजह से यह बात पैडिग पड़ी हुई है। जो बाई या एडिम ानल रोड बनाने का सवाल है उसके बारें में भारत सरकार मंजूरी नही दी।

श्री ए0 सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने बड़े वाजह लफ्जों में बताया कि दस लाख 59 हजार रूपये का एस्टीमेंट बना कर हुड्डा को भेजा लेकिन अभी तक उन्होने पैसे जमा नही करवाए हैं उन्होने उेस पैडिग रहने की बात कही। जब आपने यह बात कही थी कि एस्टीमेट बना कर भेजा है तो मुझ बड़ी खु ाी थी लेकिन सब कुछ करने के बाद आखिर में सारी बातों पर इन्होने पानी फेर दिया कि इस बारें में कुछ नही हो सकता।

श्री अध्यक्षः इनके ऊपर भी तो कोई अथौरिटी है, इसलिए नही बता सकते।

श्री एस0 सी0 चौधरीः जनाब, मै वही बात तो अर्ज कर रहा हूं कि जो ऊपर है उस ऊपर वाले की तरफ भी निगाह रखनी

पड़ेगी। लेकिन फरीदाबाद के इन्डस्ट्री वर्कर्ज ऊपर वाले की बजाए नीचे वाले की तरफ भी निगाह रखे हुए है कि उनके जाने बख्भाी जाये। स्पीकर साहब, मै एक सपैसिफिक क्वै चन कर रहा हूं कि हुड्डा ने जब भी कोई कालोनी बसायी है है चाहे उसने इन्डस्ट्री के प्लाट काटे है या रिहाय ाी प्लाट काटे है, बाकायदा सड़कों के लिए पैसे लिए है और लेते है उनके पास तो रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है उसमे ंबाई पास और सर्विज लेन दोनों भाामिल है। इसमें पार्टली अजरौन्छा मोड़ से पुराने बस अड्डे तक सर्विस लेन दोनो भाामिल है। इसमें पार्टली अजरौन्दा मोड़ से पुराने बस–अड्डे तक सर्विस लेन बनायी जा चुकी है। पुराने बस–अड्डे से दिल्ली बार्डर एरिया तक बाकी है। लम्बी चौड़ी जगह छोड़ी हुई है। जगह छोड़ी हुई है और पैसा भी लिया हुआ है। उसमें सिर्फ एक राजा जी की कोठी अड़चन है जेा उस रोड को नही बनने दे रही हालात को मै समझता हूं क्योंकि हुड्डा पी0 डब्ल्य0 मिनिस्टर के अन्डर नही हैं इसलिए मै रिक्वैस्ट करूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय इस बात रोश्नी डाले और हमारी दरख्वास्त को मानते हुए वहां साइड लेन जरूर अनाउन्स करें क्यों लाखें वरगर्ज उसी रास्ते पर चलते है। ओर रोजना दुर्घटनाए हाती रहती हैं ऐसा होने से हस्पताल पर भी लोड़ पड़ता है, दवाईयों का भी खर्च होता है और बड़े भारी मैन डेज भी जाया होता है और ह्यूमन लाईफ को भी खतरा रहता हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जहां तक हुड्डा का सवाल है उसके बारें श्री एस0 पी0 चौधरी जी ने ठीक बात कही है जब भी हुड्डा कोई कालोनी बनाता है तो उसका पैसा चर्जा करता है। चाहे इन्स्ट्रीयल प्लाटस काटे, चाहे दूसरे प्लाट्स काटे। हुड्डा सड़क, सीररेज और दूसरे सारे इन्तजाम करके देता है यानी उस एरिये को पूरा डिवैल्प करके देता है। जहां तक इस बात का संबंध है। कि उस रोड़ के बनने में किसी राजा साहब की कोठी की वजह से अड़चन है, यह बात इन्होने आज ही हाउस में की है। हम इस बात को भी दिखवा लेगे कि किस आदमी के मकान की वजह से रोड़ नही बन रही। मकान बहुत पुराना बना हुआ है, बडा है या किसी प्रकार का है। उसके बदले में कोई जगह दे सकते है या एक्वायर कर सकते है। इन सब बातेां को विश्लेशण करके हम कोशिश करेगे कि जो लोगों की जायज तफलीफ है उसे हम जल्द से जल्द दूर करें।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, फरीदाबाद में कंजक्शन को ध्यान में रखते हुए क्या मिनिस्टर महोदय वहां पर फोर लेन की बताए 6 लेन का रास्ता बनाने के बारें में विचार करेगे?

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, अब यह फोर लेन दिल्ली से पलवल तक जाता है अब आगे यू0 पी0 बोर्डर तक बन रहा हैं होडल तक फोर लेन बनेगी, ऐसा भारत सरकार ने चाहा है, अैर उसे लिए एस्टीमैट बना कर भेजा हैं जहां तक 6 लेन का सवाल

है उसके बारें में भारत सरकार को हम लिख कर भेजगे, अगर भारत सरकार इजाजत देगी तो हम बना देगे।

श्री अमर सिंह मक्कड़: स्पीकर साहब, मै आपकी मार्फत जानना चाहूंगा कि जैसा इन्होने फरीदाबाद का जिक्रकिया कि वहां फोर लेन है बाई पास की जरूरत नही है। जिन भाहरां में जी0टी0 रोड पर फोर लेन भी नही है और एक्सटेन्शन भी होती है, क्या वहां पर बाई पास बनाने की कोई तजवीज है जैसे हांसी भाहर है?

श्री अमर सिंह: हांसी भाहर के बारें में आनरेबल मैम्बर ने पहले भी सवाल पूछा था कि वहां पर कोई बाई पास बनाने की तजवीज है? वहां पर बाई पास बनाने की कोई तजवीज नही लेकिन फोर लेन बनाने की तजवीज है, कालीदेवी मन्दिर से लेकर हांस तक जो रोड़ गुजरती है उेस फोर लेन बनाने की तजवीज है। सारी फार्मेलिटीज पूरी कराने के बाद हम इस सड़क को पूरा करेंगे।

तारांकित प्रश्न सं0 1062

यह प्रश्न पूछा नही गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राम राम बिलास भार्मा, हाउस में उपस्थित नही थे।

Residential Colonies in Industrial Cities

***1110 Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Minister of State for Labou and Employment be pleased to state—

(a) The names of industrial cities in the state where residential colones have been constructed for the employees working in the industries in those cities; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to transfer the houses to the employees where they are residing; if so, the time by which the said proposal is likely to materialiese?

स्थानीय राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन):

(क) अम्बाला भाहर, जगाधरी, यमुनानगर, पानीपत, रोहतक, हिसार, सोनीपत तथा भिवानी।

(ख) हां, यह मामलता सक्रियता के साथ राज्य सरकार के विचारधीन हैं यद्यपि, कोई समय की सीमा निर्धारित नही की जा सकती।

श्री एस0 सी0 चौधरी: स्पीकर साहब, इन्डस्ट्रीयज वरकर्ज के मकानों के सिलसिले में यह बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। स्पीकर साहब, फरीदाबाद में सब से बड़ा इन्डस्ट्रीयल कम्पलैक्स है। वहां पर लाखों वरकर्ज बड़ी कीमती जगहों पर झुग्गिया डाल कर न सिर्फ कब्जा किये हुए है बल्कि सारे इलाके को एक भौबी रूप दे रह हैं इसलिए मै मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या फरीदाबाद मे भी वरकर्ज के लिए कोई कालोनी बनाने के बारें में सरकार सोचेगी और अगर सोचेगी तो कब तक इसे करेगी?

श्री ओम प्रकाश महाजनः अध्यक्ष महोदय, यह जो मैन आठ भाहरों के नाम लिए है। यह उन औद्योगिक नगरों के नाम है जिन में से कालोनिया बसायी गई है। ये कालोनीज गरीब मजदूरों को रहात पहुंचाने के लिए सस्ते किराए पर सन् 1957 से 1959 तक बनायी गई थी जब हरियाणा पंजाब ज्वायंट था। ये कुल 986 मकान बनाये हुए हैं इनकी ज्यादा से ज्यादा तादाद किसी नगर में दो सौ की है ंरोहतक और हिसार में दो–दो सौ है और दूसरी जगहों पर कही 126, कही 60 और कही 146 है। अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इन मकानों में जो लोग आबाद है उनहे ही दे दिये जाये। इन मकानों को कई मजदूर लोग छोड़ भी गये लेकिन उनकी जगह पर उने रिश्तेदार बैठ गये है लेबर डिपार्टमैंट इन से किराया वसूल करता है जो दस और चौदह रूपये के बीच में है। असली आदमी जिनके नाम मकान अलाट हुए थे वे छोड़ कर चले गए। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उन्हें ही ये मकान दे दिये जाये जो वहां पर बैइे हुए हैं मकानों की हम मौजूदा कीमत लगवा रहे हैं कीमत आने के बाद और पैसे की वसूली के बाद हम फरीदाबाद में कोई कालोनी बना सकेंगे।

श्री ए0 सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, मेरा सवाल तो यह था कि फरीदाबाद में भी ऐसी कालोनी बनाने के लिय कंसीडर करेगे या नही। एनी हाउ, मै एक और सवाल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। जब फरीदाबाद बना था तो वहां पर हर बडी

इंडस्ट्री ने उनकों इतने मंहगे भाव पर बेचा है कि उससे उनकी कैपिटल ही रिकवर हो गयी है। आज भी कुछ बड़ी फैक्ट्रीज के पास प्लाट्स पड़े हुए है। एक तो मै यह जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? दूसरे जिनके पास अभी तक भी मजदूरों की कालोनीज बनाने के लिए प्लाट्स मौजूद है, क्या सरकार उनको यह कहेगी कि यह मजदूरों के लिए मकान बनाकर उनको रहने की सुविधा दे?

श्री ओम प्रकाश महाजनः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैने निवेदन किया है कि हमने 7–8 कालोनिया ही बनाई है लेकिन हाऊसिंग बोर्ड ने कोई मकान या कालोनी नही बनाई है ंकिसी दूसरे डिपार्टमैंट ने बनाई हों तो मुझे पता नही है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, श्री ए0 सी0 चौधरी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि वहां पर लेबर की प्रोब्लम यह है कि उनके रहने के लिए मकान नही है। यह दिक्कत वहां पर मकान न होने की वजह से है। जहां तक हरियाणा स्टेट का ताल्लुक है, हमने फरीदाबाद कम्पलैक्स की तरफ से 2,000 के लगभग घर बना कर लोगों को दिये है और हम आगे भी कोि ा ा कर रहे है। कि फरीदाबाद में यह सहूलियत और लोगों को दें। आपको पता ही है कि फरीदाबाद एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है। अकेले फरीदाबाद में लेबर तकरीबन सवा लाख के करीब है। उनके रहने के लिए हमने फरीदाबाद कम्पलैक्स से भी कहा है कि वह गरीब लोगों को मकान बनाकर दे। जहां तक

औद्योगिक इकाइयां लगाने वाले उद्योगपतियों का ताल्लुक है, हम उनकों भी यह कहते है कि वे अपनी लेबर के लिये मकान बनाकर दे। जैसे चौधीर साहब ने कहा है कि कुछ उद्योगपतियों ने जमीन बहुत मंहगे भाव परबेच दी है, यह उनकी बात ठीक है। पहले वे लोग जमीन बहुंत ही सस्ते भाव पर लेते थे, थोडी सी जगह में इंडस्ट्री लगा ली और बाकी की जमीन बेच दी। आज की सकरान ने यह फैसला किया हुआ है कि जब भी कोई इंइस्ट्रिलिस्ट इंडस्ट्री लगाने के लए एप्लाई करता है तो उसके लिये एक टैक्नीकल कमेटी बनी हुई है, वह कमेटी यह देखती है कि कितनी जमीन उस इंडस्ट्री के लिये चाहिए। जितनी जमीन वह कमेटी रिकोमैड करती है, उतनी जमीन हम उनको देत है। इसके साथ ही हम उनसे यह भी कहते है कि लेबर के लिये कालोनी बनाने` लिये भी जमीन चाहिये, तो हम देने के लिये तैयार है। बड़े उद्योगपति तो बना सकते है लेकिन छोटे उद्योगपति यह नही बना सकते। लेकिन हमारी सरकार की यह कोि ा ा रहती है कि गरीब आदमियों को रहने के लिये मकान मिलने चाहिये। फरीदाबाद में भी गवर्नमैंट यह कोि ा ा करेगी कि गरीब आदमियों को रहने के लिये मकान मिलै।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने यह फरमाया है कि सरकार कोि ा ा कर रही है कि कई कारखानेदार, जो लाइसैंस लिये हुए है, वे अपनी लेबर के लिये मकान बनाये। स्पीकर साहब, इन्टरने ालन लेबर आर्गेनाईजे ान

या जितनी भी दूसरी लेबर आर्गेनाईजे ान है, उनकी तरफ से भारत सरकार को और भारत सरकार से प्रान्तीय सरकों को यह हिदायते है कि वे अपनी लबर के लिये मकान की सुविधा दे। स्पीकर साहब, आज तक कोई कारखानेदार कारखाना लगाता है तो स्टेट गवर्नमैट उनको ंलाइसैस देती है या केन्द्रीय सरकार से यह लाइसैस लेता है। अगर कोई हरियाणा प्रांत के अन्दर इंडस्ट्री लगाता है ता हरियाणा प्रांत का यह फर्ज है कि वह नौर्म्ज के मुताबिक काम करवाए। यह मिल की बिल्डिग के साथ–साथ कालोनी भी बनाये। मेरा ख्याल यह है कि कालोनी बनाने के लिये 50 परसेन्ट तो केन्द्रीय सरकार पैसा देती हे, 25 परसैंट पेसा प्रान्तीय सरकारदेती है ओर 25 परसैंट मिल–मालिक को खुद लगाना पड़ता है। हमारी सरकारके पास मजदूरों की तरफ से ऐसी ि ाकायते भी आती है लेकिन सब कोि ा ाों, ि ाकायतों और सरकार के हुक्म के बावजूद कितने ही मिल–मालिक ऐसे है जो मजदूरों के रहने के लिये कालोनीज नही बनाते है ंअगर किसी ने बनायी भी है तो भी इस बारें में वहां से ि ाकायते आती रहती है कि ने तो वहां पर कम्युनिटी लैट्रीन्ज है, न बाथरूप है, न खेलकूद के लिय मैदान है और न ही दूसरे जरूरी साधन है। इस सबा बातों को ध्यान में रखत`हुए क्या गवर्नमैट कोई कमेटी बनाने पर विचार करेगी जो इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए इन सब चीजों को पूरा करवाने की कोि ा ा करे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक लाइसैस देने का सवाल है भारत सरकार उ़द्योग लगाने के लिये लाइसैस देती है। स्टेट के हाथ में कोई छोटा–मोटा उद्योग लगाने के लिये लाइसैस देने की पावर्ज हों, तो मै कह नही सकता। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने की बात है, उनके लिए भारत सरकार लाइसैस देती है। भारत सरकार ने नार्म्ज के मुताबिक हमारी स्टेट में जो भी फैक्ट्रीज लगी है, वह ठीक ही लगी है। उनमे ंकोई वायले ान नही है। जहां तक चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी का यह कहना है कि 50 परसैंट ग्रान्ट भारत सरकार देती है, ठीक नही। पहले देते थे लेकिन आब यह स्कीम नही हैं यह स्कीम जो ज्वायंट पंजाब के समय 1952 से लेकर 1959 तक रही है। पहले सारा पैसा भारत सरकार देती थी बाद में आधा पैसा सबसिडी के तौर पर खुद देती थी और आधा पैसा स्टेट से वसूल करती थी। जैसे कि महाजन साहब ने बताया है कि 986 मकान हमने बनाये है, हमने यह मकान आधी सबसिडी भारत सरकार से लेकर ही बनोय हुए है। हम इस बात का ध्यान जरूर रखते है कि जो नौर्म्ज भारत सरकार ने तय किये हुए है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स उसी के मुताबिक इंडस्ट्रीज लगाये, उनमे ंकोई कोताही नही कर सकते। यह बात भी ठीक है कि लेबर के लिये मकान बनने चायिे। जैसे मैने पहले कहा है कि हम पूरी कोि ा ा कर रहे है कि लेबर के लिये पूरी सुविधाये मिले, उनके बच्चों के लिये ि ाक्षा का प्रबन्ध हो, उनके खेलने के लिय मैदान का प्रबन हो और उनके लिये अस्पताल भी हो।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने बजा फरमाया है कि जो झुग्गी झोंपड़ियों में या दूसरी ऐसी जगहों पर बसे हुए है जिससे वहां की खूबसूरती खराब होती हो, सरकार उनको दूसरी जगहों पर बसाने के लिये कोि ा ा कर रही है। फरीदाबाद कम्पलैक्स के जरिये या हुड्डा के जरिये काफी मकान बनाकर दिये भी गये है। और सरकार आगे भी कोि ा ा कर रही है कि और मकान दे। लेकिन सीमित साधनों को ध्यान मे ंरात ेहुए मै मुख्य मंत्री जी से एक गुजरि ा करूंगा कि झुग्गी झोपडियों में हरेन वाले लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात का इच्छुक है अज़ैर वह इस बात के लिये तैयार है कि उनकों प्लाटस दे दिये जाये ताकि वह अपने रहने के लिये छोटे छोटे मकान बना सकें। अगर सरकार उनको मकान बनाकर देती है तेा दूसरी स्कीमों में धन की रूकावट आयेगी। काम्पलैक्स में पहाड़ी एरिया के पास जगह भी अवेलेबल है, तो क्या सरकार कोई सर्वे वगैरा करवा कर, उनकों प्लाटस देगी ताकि वे लोगा कोआप्रेटिव बेसिज पर या किसी दूसरी तरह से वहां पर मकान बनाकर रह सकें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जी का बहुत अच्छी सुझाव है लेकिन मुि कल यह है कि जब हम किसी झुग्गी–झोंपड़ी वाले को यह कहते है कि हम तुम्हें किसी दूसरी जगह प्लाट्स दे देते है, तो वह वहां से उठने के लिये तैयार नही होते और कहते है कि साहब यह जगह तो हमारे काम से बहुत दूर है। मै महेन्द्र प्रताप जी के ही जिम्मे लगाता हूं

कि वे सोसाइटी बनाये या कुछ और करें, ये खुद देख ले, सारे झुग्गी–झोंपडी वालों को किसी दूसरी जगह पर जाने के लिये राजी कर ले। सरकार के पास से उनकों जगह मिल सकती है। अगर किसी ग्राम पंचायत के पास कोई जगह है तो सरकार उससे लेकर भी वह जगह उनकों देने की कोि ा ा कर सकती हैं लेकिन वे लोग तो यह कहत ह कि हम दूर नही जायेगें क्योंकि हमें काम परन जाने में मुि कल पड़ती है। भाहर से 5 मील दूर भी नही रहेगे। अगर वे इन सारी बातों को मानने के लिय तैयार हो जाये ता हम इनके सुझाव को अमली जामा पहना देगे।

Taking ouver if liquor trade

***1081 Sh. Nihal Singh:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to take over the liquor trade in the state on the pattern of Delhi and Chandigarh?

Excise and Taxation Minister (Ch. Kartar Sing Chhokar): No sir,

श्री कंवल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि उन्होने दिल्ली और चण्डीगढ़ के पैट्रन को स्टडी करवाया है और मंत्री महोदय ने जो 'नो' कहा है यह 'नो' कहने का क्या कारण है?

चौधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, दिल्ली और चण्डीगढ़ के पैटर्न का अध्ययन तो नही करचाया लकिन वाकफियत

जरूर हासिल की हैं चण्डीगढ़ में इनके पास केवल तीन वैड्ज है वे भी इन्होने औक ान में ली है लेकिन दिल्ली में सारी वैड्ज सरकार के पास है। स्पीकर साहब, दिल्ली भाहर की कम्पैक्ट आबादी है, हमारी स्टेट की तरह नही हैं हमारे यहां गांव है और उस पैटर्न पर करना हमारे लिए फिजिबल नही है और हम सरकारी कर्मचारियों को भाराब के धंधे में नही लगाना चाहते।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, जो भाराब के ठेकेदार है जोकि बोली पर ठेका लेते है मेरे ख्याल में वे लाखों और करोडों रूपया कमाते है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि सरकार को इस काम को अपने हाथ में लेने में क्या हर्ज है? हजारों सैलजमैन लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे पढत्र–लिखे नौजवान जो बेकार फिर रहेहै उनकों काम मिलेगा। वे पढ़–लिखे नौजवान वहां बैठकर कोई भाराब तो पियेगे नही।

चौधरी कटार सिंह छोकरः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैने बताया है कि हमारा जो प्रेजेन्ट सिस्टम है उसमें जो वैन्डर्ज है वे प्राईवेट लोग है ओर वे पैसा भी ज्यादा देते है। वे क्राईम को रोकने में ऐफर्ट्स और मदद करते है। इतनी दूरी दराज के इलाकों में हमारे लिए सुपरविजन करना फिजिबल नही है। फिलहाल आज के हालात में हमारें लिए वह पैटर्न ठीक नही है।

Generation of electricity

***1094 Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state, the steps being

taken to generate more electriciety to meet the increased demand resulting from increasing populaton and industries in the state?

Irrigation and power Minister (Ch. Shamsher Singh Surewala): Strenuous efforts are being made to improve the generation and supply of power of different sectors of consument in the state.

These include:

(a) Improvement in the functioning of the Faridabad and Panipat Thermal Power Station.

(b) Renovation and modernization of Faridabad and Panipat Thermal Power Station;

(c) Getting better coal supply;

(d) Carrying out periodic preventive maintenance; and

(e) Early commissioning of the projects in hand.

In aaddition to the above, efforts are also being made to obtain for Haryana its righful share of power from the power generation stations located ourside the state.

सेठ राज दास धमीजा: स्पीकर साहब, मंत्री जी का बड़ा तसल्लीबख्भा जवाब है। लेकिन अम्बाला का नाम नही है जहां सात हजार इंडस्ट्रीज है और बिजली की कमी के कारण वे इंडस्ट्रीज खत्म होने जा रही है। क्या मंत्री महोदय कोई खास तवज्जोह

देकर अम्बाला तहसील में बिजली का नया यूनिट लगाने की कृपा करेगे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, अम्बाला में जिन इंडस्ट्रीज का जिक्र धमीजा साहब कर रहे है वहां पर लोगों ने नैजीडैंि ायल हाऊसिग में छोटी छोटी मोटरे लगाकर छोटी–छोटी इंडस्ट्रीज लगा रखी है यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि जब इन लोगों ने मोटरें लगाकर इंडस्ट्रीज भाुरू की तो बिजली बौर्ड को ऐक्सटैं ान आफ लोड के लिए ऐप्लाई नही किया। जो मकान में आलरेड़ी फिटिग है उसकेां ही अपने आए ऐक्सटैंड करकके हायर पावर की मोटरें लगा ली। इस तरह से हजारों घरों मैं इंटस्ट्रीज चल रही है लेकिनइसकी इंफरमे ान बिजली बोर्ड के पास नही है हालांकि बिजली बोर्ड ने इनकों कहां कि जो अपना लोड ऐक्स्टैंड करवाना चाहर्त हैं वे इतनी पीरियड तक अगर ऐप्लाई कर देगे तो उन पर कोई जुर्माना नही होगा। बिजली बोर्डर के पास इस तरह की इंफरमे ान न होने के कारण यह दिक्कत है कि जो ट्रांसफर लगे हुएहै वे ट्रांसफर ऐक्सटैड नही हो सकते। मै चाहूंगा कि धमीजा साहब इप मामले में बोर्ड की मदद रकें। जहां तब बिजली की सप्लाई बढ़ाने का संबंध है इस संबंध में मैने पहले भी हाउस को बताया है मि मुख्य मंत्री महोदय ने यूनियन ऐनर्जी मिनिस्टर श्री साठे को यहा बुलाया और उन्हे पूरह रियाणा की स्थिति बताई। इस मामले में उनहोने हरियाणा की बहुत मदद की और उसके

बाद हरियाणा को पन्द्रह–बीस यूनिट रोज बिजली मिल रही है। पिछले दिनों से जो बिजली मिल रही है उसी फिग्गर्ज मै हाउस को बताना चाहता हूं। 25 फरवीर को 1 करोड़, 36 लाख यूनिट, 24 फरवरी को 1 करोड़, 31 लाख यूनिअ, 23 फरवरी को 1 करोड़ 30 लाख यूनिट, 22 फरवरी को 1 करोड़ 20 लाख यूनिट, 21 फरवरी को 1 करोड़ 24 लाख यूनिट और पहली फरवरी को 1 करोड़ 26 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध थी। स्पीकर साहब, बीच में दो तीन बिदल बिजली कम उपलब्ध थी। स्पीकर साहब, बिजली की उपलब्धि अब इतनी बढ़ गई है कि 17 फरवरी से हरियाणा के अन्दर बिजली पर कोई कट नही है ंपूरी स्टेट में उौमेस्टिक बिजली पर रूरल और अर्बन एरियाज में कोई कट नही है। 24 घंटे बिजली दे रहे है ंइंडस्ट्रीज का`दस घण्टे बिजली दे रहे और ऐग्रीकलचर को भील बिजली खूर मिल रही हैं स्पीकर साहब, अम्बाला को भी पहले से ज्यादा बिजली मिल रही है। स्पीकर साहब, जहां तक अम्बाला में और यूनिट लगाने का प्र न है इस बारें में मै सदन को बतानाचाहता हूं कि यमुनानगर में दो यूनिट 210–210 मैगावाट के लगाने जा रहे है। उनके लिए आलरेडी काम भाुरू हो गया हैं जमीन ऐक्वायर कर रहे है। रेलवे साइडिग और दूसरी बात करने लग रहे है जब साठे साहब यहां आए थे तो उन्होने ऐलान किया था कि सातवी पंचवर्शीय योजना मे बाहरी सहायता से भारत सरकार यमुनानगर मं चार यूनिट 210–210 मैगावट के स्थापित करवाएगी। मै समझता हूं कि चाहे अम्बाला हो,

चाहे कोई दूसरी जगह हो, कही भी बिजली की कोई कमी नही रहेगी।

Sh. A.C. Chaudhry: In the las para of the reply, Hon'ble Minister has stated—

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (7) 23

"In addition to above, efforts are also being made to obtain

for Haryana its rightful share of power from the power genertion station located outside the state".

स्पीकर साहब, हमें इस बात को सुनत हुए चार साल हो गए है कि नाथपा झाखड़ी प्रोजैक्ट में हमारा भोयर है लकिन हिमाचल वाले कैटेगोरिकलजी कहते है कि हरियाणा को कोई भोयर नही है और हम एक यूनिट बिजली नही देगे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि इस प्रौजेक्ट में हमारा कितना हिस्सा है और क्या हम अपने हिस्से को लेने में सफल होगे या नही?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब नाथपा झाखड़ी प्रौजैक्ट के बारें में जो फैसला हुआ था उसके बारें ूमें हाउस में सब का ेपता है। मै उस बारे ंमें हाउस का समय नही लूंगा। स्पीकर साहब, उस प्रोजैक्ट की टेक्नोक्लीयरैस तो गवर्नमैंट आफ इंडिया ने दी थी लकिन फाइनै ि रूल क्लीयरैंस न तो

गवर्नमैट आफ इंउिया ने और न प्लानिग कमि ान ने की थी। स्पीकरसाहब, हरियाणा ओर हिमाचल का जो ऐग्रीमैट हुआ था उसके बारें में गवर्नमैट आफ इंडिया ने कहा कि यह प्रोजैक्ट उसके मुताबिक नही लगेगा। यह प्रौजेक्ट चूंकि हिमाचल में इसलिए इसको एन0एच0पी0सी0 लगाएगी ओर इनका कुछ परसैन्ट भोयर होगा। इसका कारण यह था कि दोनों स्टेट्स के पास इस प्रोजैक्ट के लिए धन उपलबध नही था। इसकी कौस्ट एक हजार करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गई थी। गवर्नमैट आफ इंडिया ने कहा कि एन0एच0पी0सी0 इसकों लगाएगी और गवर्नमैट आफ इंडिया फण्डिग का इन्तजाम करेगी। उस वक्त हरियाणा ने एक प्वायंट रेज किया था कि हम इस बात पर इस प्रोजैक्ट को छोड़ने को तैयार है कि कम से कम 35–40 परसैन्ट पावर हमारा प्रायर राइट होगा ओर यह एग्रीमैट के मुताबिक हैं उस वक्त सी0 ई0 ए0 और मिनिस्टर आफ ऐनर्जी ने आ वासन दिलाया कि हरियाण के क्लेम को एकमोडेट करेगे। स्पीकर साहब, अब तक लिखकर और जबानी यही पोजी ान है अभी प्रोजैक्ट भाुरू नही हुआ हैं हमें पूरा वि वास है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने और उनके अधिकारियों ने हमारी नीड को देखते हुए और एग्रीमैंट को देखते हुए जो वायदा किया है उसके मुताबिक जो भी बिजली उपलबध होगी उसका 35–40 परसैन्ट भोयर खरीदने का हामरा प्रायर राइट होगा। हरियाणा स्टेट की जो नीड होगी उकसे मुताबिक नाथपा झाखड़ी से बिजली हमें मिलेगी।

Mr. Speaker: Questio Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर खे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Drinking water faclity for Jswhar Colonly in N.I.T. Faridabad

***1132 Sh. A.C. Chaudhry:** Will the Minister of state for local Government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide drinking water facility to Jawaher Colony in Faridabad N.I.T. constituency under water supply scheme; if so, the steps so far taken or proposed to be taken to provide such a facility there?

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन): हां। जवाहर कालोनी मे आन्तिरक वितरण सिस्टम के लिये एक योजना तैयार की गइ है। इस योजना को कार्यनिव्त करना रा ि। की उपलब्धियायों पर निर्भर है जिसका प्रबन्ध किया जा रहा है।

Export of Murah Breed buffaloes

***1063 Sh. Ram Bilas Sharma:** Will the Minister of state for Animal Husbandry be pleased to state—

(a) The total number of Murrah buffaloes exported from Haryana state during 1985-86 (to date); and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to further improve the breed of the buffaloes as referred to im part (a) above?

पशुपालन राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह):

(क) 33165

(ख) जी हां।

श्री ए0 सी0 चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैने एक काल अटैन्शन मोशन दिया था जोकि फरीदाबाद के पानी से संबधित था लेकिन मेरे सामने उसके कोई और ही तथ्य लाये गये हैं जिस पानी का रोना रोया गया था वह हयूमन कंजप्शन के लिये बहुत ही हानिकारक है। उस काल अटैन्शन मोशन के बारें में मै जानना चाहता हूं कि उसका क्या बना?

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, अभी वह काल अटैन्शन मोशन मेरे पास नही पहुंचा है। जब मेरे पास पहुंचंगा, तब मै देख लूंगा।

श्री ए0 सी0 चौधरी: स्पीकर साहब, मैने सुबह साढ़े आठ बजे आपके सचिवालय में पहुंचा दिया था।

बिल्ज (इंट्रोड्यूस्ट)

सदन की अनुमति से

(i) दि पंजाब विलेज कामन लैण्ड्ज रेगुलेशन हरियाणा अमैडमैंट बिल, 1989

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब दि पंजाब विलेज कामन लैन्डज (रेगुले ान) हरियाणा अमैडमैट बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिए हाउस से परमि ान लेगे।

Development Minister (Ch. Rajinder Singh): Sir, I beg to move—

That leave be granted to introduce the Punjab Village Common Lnds (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1986

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे ा हुआ कि–

दि पंजाब विलज कामन लैन्डज (रैगुले न) हरियाणा अमैटमैट बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि पंजाब विलज कामन लैन्डज (रैगुले न) हरियाणा अमैटमैट बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब बिल इंट्रोड्यूस करेगे।

Development Minister (Ch. Rajinder Singh): Sir, I introduce the Bill.

(ii) दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैट बिल, 1986

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब दि हरियाणा रूरल डिवैल्मैंट बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिए हाउस से परमि ान लेगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana Rural Development BIll, 1986.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे ा हुआ कि–

दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैट बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब बिल इंट्रोड्यूस करेगे।

Irrigation and power Minister (Ch. Shamsher Singh Surewala): Sir, I intorduce the Bill.

(iii) दि हरियाणा कोआप्रटिव सोसाइटीज (सैकिड अमैडमैट) बिल, 1986

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज (सैकिण्ड अमैडमैंट) बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिये हाउस से परमि ान लेगे।

Irrigation and power Minister (Ch. Shamsher Singh Surejewala): Sir, I beg to move-

That leave to granted to introduce the Haryana Co-operative societies (Secound Amendment) Bill, 1986.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे ा हुआ कि–

दि हरियाणा कोआप्रटिव सोसाइटीज (सैकिड अमैटमैट) बिल, 1986 को इंटोड्यूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न यह है कि–

दि हरियाणा कोआप्रटिव सोसाइटीज (सैकिड अमैटमैट) बिल, 1986 को इंटोड्यूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब बिल इंट्रोड्यूस करेगे।

Irrigation and power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I introduce the Bill.

(iv) दि हरियाणा अर्बन (कंट्रोल आफ रैन्ट एंड एक्विशन) अमैडमैड बिल, 1986

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब दि हरियाणा अर्बन (कंट्रोल आफ रैन्ट एंड एविक ान) अमैडमैट बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिये हाउस से परमि ान लेगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana Urban (Control of Rent and Evicition) Amendment Bill, 1986

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे ा हुआ कि–

दि हरियाणा अर्बन (कंट्रोल आफ रैन्ट एंड एविक ान) अमैडमैट बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिये हाउस से परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि–

दि हरियाणा अर्बन (कंट्रोल आफ रैन्ट एंड एविक ान) अमैडमैट बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिये हाउस से परमि ान दी जाऐ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब बिल इंट्रोड्यूस करेगे।

Irrigation and power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I introduce the Bill.

(v) दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैडमैट) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैडमैट) बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिये हाउस से परमि ान लेगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 1986

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे ा हुआ कि–

दि हरियाणा अर्बन (कंट्रोल आफ रैन्ट एंड एविक ान) अमैडमैट बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिये हाउस से परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि–

दि हरियाणा अर्बन (कंट्रोल आफ रैन्ट एंड एविक ान) अमैडमैट बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिये हाउस से परमि ान दी जाऐ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब बिल इंट्रोड्यूस करेगे।

Irrigation and power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I introduce the Bill.

(vi) दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैडमैट एंड वेलीडे ान) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैडमैट) बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिये हाउस से परमि ान लेगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana Municipal (Amendment & Validation) Bill, 1986

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे ा हुआ कि–

दि हरियाणा अर्बन (कंट्रोल आफ रैन्ट एंड एविक ान) अमैडमैट बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिये हाउस से परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि–

दि हरियाणा अर्बन (कंट्रोल आफ रैन्ट एंड एविक ान) अमैडमैट बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिये हाउस से परमि ान दी जाऐ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब बिल इंट्रोड्यूस करेगे।

Irrigation and power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I introduce the Bill.

(VII) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिण्ड अमैटमैट) बिल, 1986

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिण्ड अमैटमैट) बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिये हाउस से परमि ान लेगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1986.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे ा हुआ कि–

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिण्ड अमैटमैट) बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिये हाउस से परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिण्ड अमैटमैट) बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करने के लिये हाउस से परमि ान दी जाऐ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब बिल इंट्रोड्यूस करेगे।

Irrigation and power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I introduce the Bill.

वर्श 1986–87 के बजट पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्र्ज, अब वर्श 1986–87 के बजट पर जनरल डिस्क ान होगी। श्री इन्द सिंह नैन बोलेगे।

चौधरी इन्द्र सिह नैन (बरवाला): आदरणी अध्यक्ष महोदय, कल जो आदरणीय वित्त मंत्री महोदय, श्री सागर गुप्ता जी ने वर्श 1986–87 का बजट इस अगस्त हाउस में प्रस्तुत किया है, मै उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आदरणीय अध्यक्ष महादेय, गुप्ता जी न`जो बजट पे ा किया है उसके बारें में अब डिस्क ान भ्ारू हुई है। आपने सबसे पहले उस पर बोलने के लिये मुझ जो समय दिया है, उसके लिये मै आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट स्पीच की कापी को मैन वित्त मंत्री महोदय के साथ–साथ पढ़ा और फिर उसे बादएक बार ाम को भी पढा। पढने के बादमै जिस निश्कर्श पर पहुंचा हूं उसकी व्याख्या मै कुछ इंगलि ा पक्तियों में करूंगा–

Speaker, Sir, it is a balanced budget. It can be termed as a common man's budget. It is a progressive, pro-poor and por-farmer budget. It is based on facts and realities, Sir. It is a tax free budget as no tax has been proposed in this budget. It is a document prepared by an experienced and matured politician who is also a trade union leader and

happens to be the Finance Minister of Haryana. I congratulate the Finance Minister for his hard work, ability and far sightedness.

स्पीकर साहब, पिछले सालों में कुछ एकोर्ड या समझौते हुए, हमारे युवा डाईनोमिक और इन्सपायरिग प्रधान मंत्री जी ने दे ा की बाग डोर सम्भाली। उसके बाद उन्होने दे ा में बहुत सी अच्छी प्रणालियां अच्छे तरीके अपनाने का प्रयत्न किया। प्रधान मंत्री जी ने भ्रश्ट और क्रप्ट लोगों पर रेड़ भी करवाए और कुछ लोग अरैस्ट भी करवाए। आज इसका कुछ रिजल्ट निकल रहा हैं प्रधान मंत्री जी यह चाहते है कि दे ा के अन्दर स्वच्द प्र ाासन हो। हमी सरकार पहले ही उनकी नीतियों पर चल रही है। इसलिये मै आनी सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह भी क्लीन एडमिनिस्ट्रे ान देने की तरफ ध्यान दे। स्पीकर साहब, 24 जुलाई 1985 को हरियाणा और पंजाब के बोरं एक एकोर्ड हुआ जिसकों राजीव लौगोवाल समझौता कहते है। स्पीकर साहब, गवर्नर एडरैस परबोलते हुए मैने इस बारें में काफी कहा था, अब मै इतनी बात कहना चाहता हूं कि हमारे पडौसी प्रांत में वातावरण बहुत खराब है, आग लगी हुई, इनोसैन्ट आदमी मारे जा रहे है। स्पीकर साहब, मुझे बड़ी खु ाी है ओर गर्व भी है कि जब पड़ोस में आग लगी हुई हो तो हरियाणा सरकार ने अपने प्रांत में कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी कायम की हुइ है। यहां पर हर आदमी अपने को सेफ समझता है। यह छोटी बात नही है बल्कि बहुत बड़ी बात हैं इसके लिए मै हरियाणा सरकार को वि ोशकर मुख्य मंत्री जी को और

पुलिए डिपार्टमैंट को मुबारिकबाद देता हूं। आज सारे दे ा में हरियाणा की कानून व्यवस्था सब से बढ़िया है, सब से उत्तम है। स्पीकर साहब, हरियाणा का जन्म एक नवम्बर, 1966 को हुआ। उसके बाद हरयिाणा मे ंआल राउन्ड प्रोगैस हुई है। हरियाणा ने उसे बाद चहुमुखी प्रगकित की है। स्पीकर साहब, इसका कारण एक ही है। कि पहले जब ज्चायंट पंजाब था तो सारा पैसा आज के पंजाब के एरिया में लगता था। हामरे हरियाणा में बहुत कम पैसा लगता था। अब तो तरक्की हुइ है वह हामरी अपनी सरकार की वजह से हुई है। यह तरक्की हमारे मुख्य मंत्री जी की वजह से हुई हैं और आगे भी हरियाणा बहुत तरक्की कर रहा है। मै आ ाा करता हूंकि हरियणा प्रांत हिन्दूस्तान के नक ो पर कुछ दिनों में पहले नम्बर पर आ जाएगा। हरियाणा ने सामाजिक ओर आर्थिक तरक्की की हैं और आगे भी तरक्की करता जा रहा है।

स्पीकर साहब, छठी पंच वर्शीय योजना 31 मार्च, 1985 को समाप्त हो चुकी है। और एक अप्रैल 1985 से सातवी पंच वर्शीय योजना चालू हो चुकी है। स्पीकर साहब जो हमारी सातवी पंच वर्शीय योजना है। इसमें 2900 करोड़ रूपए खर्चे करने का प्रावधान है। स्पीकर साहब, मै कुछ आंकड़े दूंगा। सातवी पंच वर्शीय योजना में एक हजार करोड़ रूपए बिजली पर खर्च करने की स्कीम है क्योंकि बिजली आज के जमाने में बहुत जरूरी है। इसी तरह से सिचाई पर 585 करोड़ रूपय लागने का प्रावधान है ओर 200 करोड रूपए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर लगाने की स्कीम है।

यह मै सांतवी पंच वर्शीय योजना के विशय में बता रहा हूं। आगामी वर्श 1986–87 का जो आ रहौ, उकस जो हमार आउटले है।, जो हमारा प्लान है, उस पर 525 करोड रूपये के खर्च की व्यवस्था है। इस बारें में मै आकड़े देकर बताऊ ंगा कि कहा कहा हमने आने वाले वर्श में पैसा खर्च करना है। जैसे मैने पहले कहा कि सिचाई बहुत ही जरूरी है। सिंचाई पर 169 करोड़ रूपये खर्च होगे ओर 13 करोड़ रूपए ग्रामीण विकास पर खर्च होगे। ग्रामीण विकास हरियाणा में बहुत जरूरी है। क्योंकि हरियाणा कृशि प्रधान प्रदे ा है। हमारी 80 प्रति ात आबादी भारत के गांवों में रहती है। स्पीकर साहब, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि असली भारत गांवों में रहता है। स्पीकर साहब, आप भी देहात के रहने वाले है। अगर देहात की प्रगति होती है तो सारे दे ा की प्रगति होती है क्योंकि 80 प्रति ात आबादी भारत के गांवों में रहती है।

स्पीकर साहब, अब मै एस0 वाई0 एल0 का जिक्र करूंगा वैसे इस बोरं में जो रैजोल्यू ान आया था उस पर मैने बहुत डिटेल में कह दिया था। अब यहां पर इतनी बात कहता हूं कि यह नहर बननी बहुत जरूरी है। जब तक यह नहर नही बनेगी तब तक हरियाणा के लोग बहुत परे ाान रहेगे। किसानों के लिये पानी बहुत जरूरी होता है। मै तो किसान के परिवार से सम्बन्ध रखता हूं इसलिए मुझ पता है कि जब तक किसान के खेत में पानी नही आता है वह बहुत दुखी रहता है। हमने इस बारें में रैजोल्यू ान भी पास किया था। जब तक सैन्टर की सरकार इसकों बनाने का

काम अपने हाथ में नही लेगी, मुझे सन्देह है कि तब तक यह नहर नही बन सकेगी ओर समय भी बहुत निकल चुका है। हमारे हरियाणा मे एस0 वाई0 एल0 लहर का पानी लेने के लिए 93 किलोंमीटर लम्बी लहर बनी जिस पर 31 करोड़ रूपय लगा था लेकिन पंजाब 120 किलोमीटर लम्बी नहर बननी है जिस पर 270 करोड़ रूपए खर्च होगे। हम पंजाब को 110 करोड़ रूप्ए तो दे चुके है ओर 90 करोड़ रूप्ए ओ देने रहत है पैसे की तरफ से हरियाणा सरकार ने कोई कमी नही छोड़ी है लेकिन पंजाब की सरकार बिना किसी कारण के इस नहर को नही बनारही है। तो स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से यही कहता हूं कि यह नहर जल्दी बननी चाहिए।

स्पीकर साहब, अब मै बजट के बारें में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। हरियाणा सरकार ने जहां बजट में टैक्स नही लगाए वहां लोगों को काफी कनसै ान भी दिए गए है। मै उनके बारें मे ंजिक्र करना जरूरी समझूंगा क्येां हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पे ा किया है उसके अन्दर कोई टैक्स नही लगाया गया है। इस बजट में हमारी सरकार ने लोगों को काफी सुविधाएं दी है किसानों को राहत दी गई है। व्यापरियों को राहत दी गई है। हमारे वित्त मंत्री जी ने लोगों को बहुत सी नई स्कीमों दी है। मै उन स्कीम्ज का एक–एक कर के जिक्र करना चाहूंगा। जैसे गैल्टरी एवाड्र्ज दि एग है।, इंडस्ट्रीज को कनसै ानप दिया गया है एक्स–सर्विसमैन को कनसै ान दिए गए है। एक्स–सर्विसमेन की

भलाई के लिए नई स्कीमें चालू करने का भी सरकार का विचार है। जो कालेज टीचर्ज की पर्सनल परमो ान स्कीम है। इस बोरं में मै एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जो प्राइवेट कालेजजिज के टीचर्ज है वे बहुत दिनों से एजीटेटिड थे। उनकी मांग थी कि उनकी उनकी सैलरी बैक या ट्रेजरी की मारफत मिलनी चहिए। इस बारें मे हमारे मुख्य मंत्री जी ने 20 फरवरी को यहां हाउस के अन्दर यह घोशणा भी कर दी है ओर सरकार की नति बताई कि प्राइवेट कालेजिज का जो टीचिग ओर नान टीचिग स्टाफ है, उसके बैकों की मारफत तनख्वाह मिलेगी। यह बहुत ही अच्छी बात है। इस बात से प्राइवेट कालेजिज का टीजिग ओर नान–टीचिग स्टाफ बहुत खु ा हुआ है। इस बात के लिये मै सरकार को मुबारिकवाद देता हूं। हमारी सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है। इसके अलावा स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इन ाोरैस स्कीम भी चालू की हैं इसके अलावा हैल्थ केयर एंड मैडीकल अलान्स स्कीम भी सरकारी कर्मचारियों के लिए चालू की गई है। आप सभी जानते है ओर एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आदमी की हैल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है ओर जिस आदमी की हैल्थ ठीक नही है वह कुछ नही कसता। इसके अलावा डब्ल ड्यूटी के लिये स्पै ाल अलाउंस की स्कीम का इस बजट में प्रावधान किया गया है। यह बहुत ही अच्छी स्कीम है इससे फौरथ क्लास के कर्मचारियों को काफी सुविधाएं हो जाएंगी। इसके अलावा स्पीकर साहब, मै एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि

हरियाणा में ट्रैक्टर्ज पर टैक्स एज कम्पयेरड टू अदर स्टेट्स बहुत ज्याद है। मै इस बारें में सरकारे से अनुरोध रूंगा और सुझाव दूंगा कि दूसरी स्टेट्सय से कम्परैटिव स्टेटमैट जी जाए और ट्रैक्टर्ज पर जितन भी सेल्ज टैक्स कम हो सके वह कम करने का प्रयन्त करें। मेरा हमारे वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस बारें मे ंध्यान दे।

इसके अलावा स्पीकर साहब, अब मै अपने हल्के के बारें में कुछ बाते ंसदन में कहना चाहूंगा और अपने हल्के कके लोगों के बारें में कुछ बातें कहने का हमार कर्तव्य भी बनता है। मै इस बात को मानने वाला हूं कि हमारी सरकार के मुख्य मंत्री जी और दूसरो मन्त्रिगण ने पब्लिक जलसों में लोगों के जिन कामों को करने का आ वासन दिया है और जिन कामों को करने की हां की है उनको पूरा करें, उन आ वासनों को इम्पलीमै।अ करें यदि उन आ वासानों का इम्पलीमैट किया जाए तो यह बहुत बड़ी बात हजैं मै त इस बात में वि वास रखने वाला व्यक्ति हू कि जो बात कहनी हो वह कहनी चाहिए और जो बात कही जाती है वह पूरी क्ी करनी चाहिए। इससे सरकार की छवि सुधरती है मैन अपनी पार्टी मीटिग में भी यह बात कही थी आज तक लोगों को उनके कामों के बारें में जितन भी आ वासन दिए गए है और उनकों उनके काम करने की हां की गई है सरकार उन कामों को अगले साल यानी 1986–87 क जा साल आ रह है, उसमें पूरा करें इससे

लोगों में आस्था पैदा हो जाएगी कि सरकार जो कहती है वह करती भी है।

जैस मैने पहले कहा है कि सरकार ने लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे मुख्य मंत्री जी यूनियन एनर्जी मिनिस्टर श्री बसंत साठे जी को हरियाणा में लेकर आए थे। उन्होने हरियाणा में बिजली समस्या को काफी हद तक सुधार दिया है। बिजली इन्सान की जिन्दगी में बहुत ही जरूरी हो गई है। आज कल हर काम बिजली से चलता है। आज घर घर के अन्दर बिजली के मीटर लगे हुए हैं हर काम में बिजली की बहुत जरूरी पहड़ती है। मेरे हल्के में एक कस्बा उकलाना मंडी पड़ता है। वहां पर बिजली की बहुत कमी थी। मैने उस बारें में मुख्य मंत्री जी से कहा उनहोने वहां पर जनरेटर सैट खरीदने की इजाजत दे दी है, उससे वहां पर बिजली की समस्या हल हो जाएगी। आप देखते है गांवों के अन्दर भााम के वक्त बिजली नही होती। उससे लागों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैने पहले भी कहा था कि बम्बई में प्राइवेट सैक्टर में टाटा की बिजली है। वहां पर बिजली की कोई कमी नही होती। वहां पर बिजली की कमी क्यों नही होती उसका कारण सरकार को पता करना चाहिए। सरकार को इस बात का पता करना चाहए कि किस डिफैक्ट और कमी के कारण हमारे यहां बिजली की कमी है। जब तक हम उस कमी को ठीक नही करेगे तक तक बिजली की पूर्ति

नही हो सकेगी। मैने बिजली के बारें में पहले भी बहुत कहा था कि वह इन्सान की जिन्दगी में बहुत ही जरूरी है।

स्पीकर साहब, बजट स्पीच में और भी बहुत सी बाते कही गइ है ग्रामीण विाकस पर भारत सरकार की बहुत सी स्कीमें है। जैसे एन0 आर0 ई0, पी0 आर0 एल0 ई0 जी0 पी0, आई0 डी0 पी0 तथा और बहुत सी दूसरी स्कीमें है जो गांवों में चल रही है। इन स्कीमों का देहात के अन्दर होना बहुत जरूरी भी है। यदि गांवों की तरक्की होगी तो सारे प्रांत की तरक्की होगी।

जहां तक प ाु पाल विभाग की बात है। मै इस बारें में एक बात कहना चाहूंगा कि एक एक भैस 10–10 हजार रूपए की आती है। यदि वह बीमार हो जाए तो उसको हस्पताल मे ले जाना बहुत ही मु कल हो जात है। यदि कोई आदमी बीमार हो जाए ता उसको कार मे ंहस्पताल ले जाया जा सकता है लेकिन भैस को नही ले जाया जा कसता। इसलिये मै सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे ओर प ाुओं के लिये ज्यादा से ज्यादा हस्पताल खोले। हमारी सरकार बहुत से नए प ाु हस्पताल खोल रही है यह बहुत अच्छी बात है।

स्पीकर साहब, मै कायदे की बात कहूंगा कि कोआप्रेटिव मूवमैट बहुत ही जरूरी हैं महाराश्ट्र स्टेट में कोआप्रेटिव सैक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहए जिससे लोगों का बहुत भला हो सकता हैं लोगों में कोआप्रे ान की भावना पैदा हो सकती है,

लोग मिल जुल कर काम कर सकते है। हरियाण प्रदे ा के अन्दर कोआप्रेटिव सैक्टर में तीन भूगर मिल लगाए जा रही हैं क्योंकि 'हैफड' दो नए राइस भौलजै लगाने जा रही है क्योंकि 'हैफड' किसानो की मित्र है। मैने पहले भी कहा था कि जब भी पैडी की खरीद होती है या गेहूं की खरीद होती है तो सारी एजैसियां खरीदने से इन्कार कर देती है जो पैडी की लगगभ 84 परसैन्ट प्रक्योरमैंट हुई थी वह 'हैफड' ने की है। मै कोआप्रेटिव सैक्टर की बात कह रहा था। सरकार को कोआप्रेटिव सैक्टर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिएं

स्पीकर साहब, अब मै वन विकास के बारें में कहना चाहूंगा। जहां हरियाली होती है वहां सब कुछ होता है। वहां सब कुछ हेाता है। मेरे अपोजी ान के भाई आज यहां सदन मे ंनही बैठे है ंमै एक बात कहना चाहता हूं कि हम तो दरखत लगाते है और मेरे अपोजी ान के भाई उनको काटते है। उनका दरखत काटने का ही प्रोग्राम है क्योंकि पिछले महीने की 23 तारखी कै मारे अपोजी ान के भाईयों ने सारे प्रांत की कीकर काट डाली। हम दरखत लगाते है लेकिन काटत नही। मेरे अपोजी ान के भाई या तो दरखत काटते है या लोगो से चन्दा इक्ट्ठा करते है वे गांवों में चन्दा इकट्ठा करने का प्रोग्राम चला रहे है। स्पीकरसाहब, उनका यह कर्तव्य बनता है कि यहां सदन में आ कर अपने हल्के के लोगों की बात कहते ओर अपने कंस्ट्रकिटव सुझाव सरकार को देते ताकि सरकार उनको मानती। स्पीकर साहब,

रूलिग पार्टी और अपोजी ान दोन डैमोक्रेसी के पुर्जे है मै यह कह सकता हू कि मेरे अपोजी ान के भाई अपनी डियूटी में कोताही कर रहे है। अध्यक्ष महोदय जो आदमी अपनी डियूटी के कोताही करता है वह बहुत भारी गलती करता हैं

अब मै सड़कों के बारें में जिकर करना चाहुंगा। यहां की सड़कें सारे हिन्दूस्तानमें सबसे बढ़िया है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने भी राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर बोलते हुए कहा था कि जब कोई हरियाणा की सीमा मे ंदाखिल होात है तो उसे पता चला जाता है कि यह हरियाणा सूबा आ गया है क्योंकि यहां की सड़के बहुत अच्दी है जबकि दूसरे प्रदे ाों की सड़के इतनी खराब है कि लोगों के बस में बैठे बैठे बस की छत से सिर टकराते रहते है। हरियाणा रोडवेज लगातार पिछले तीन सालों से सारे दे ा मे प्रथम आ रही ही हैं हरियाणा सरकार लोगों की सुविधा के लिए और भी बसें खरीदने जा रही है आज के दिन सरकार ने जगह जगह पर बस स्टैण्ड बनाये हुए है ओर इनके अलावा और भी बस सटैण्ड बना रही है ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा हो सके। मै इस काम के लिए सरकार को मुबारिकबाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मै ि ाक्षा के बारें मे कहना चाहूंगा। मेरा तो यह विचारहै कि नै ालन करैक्टर एक अच्छी एजुके ान मसे बनता है टीच किसी दे ा के निर्माता होत है सरकार ि ाक्षा की तरफ काफी ध्यान दे रही हैं धमीजा साहब

नैतिकता की बात को बार बारे कहते है मै भी उनकी इस बात से सहमत हूं कि मौरल वैल्यूज की तरफ वि ो ा ध्यान दिया जाये और सरकार को बच्चों को मोरल वैल्यू की जानकारी के लिये कोई विशय स्कूलों और कालेजों में लगाना चाहिए ताकि यहां के बच्चों का पता चल सके कि मोरल वैल्यू क्या चीज होती है। इस तरफ सरकार को खास करके ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मै स्वास्थ्य की बात कहना चाहूंगा। सरकार ने आज जगह जगह पर हस्पताल खोले हुए हैं इस तरफ भी सरकार का काफी ध्यान है। इस बारें में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार को इस तरफ और ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मै टूरिज्म की बात कहना चाहूंगा। आज आप देखते है कि सरकार ने जगह जगह पर टूरिज्म काम्पलेक्सिज खोले हुए है। यहां से जब दिल्ली जाजत है तो रास्ते में आपकों काफी टूरिज्म कम्पलैक्सिज दिखाई देगे। इसी प्रकार से अब टूरिज्जम विभाग ने कैथल में भी एक काम्पलैक्स खोला है। इसकी वहां पर बहुत जरूरत थी। वह काम्पलैक्स बहुत कामयाब है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के तह बहुत काम किए है। यह एक राश्ट्रीय प्रोग्राम है। यह सारी सरकारों का प्रोग्राम है। इस पर हमारी सरकार ने काफी ध्यान

दिया है मै तो यह समझता हूं कि सरकार को इस तरफ और ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

यदि आप अपोजी ान के भाई सदन में मौजूद होत तो बहुत अच्दा होता क्योंकि बोलने का मजा भी तभी आता जब वे यहां होते । कुछ वे अपनी बात कहते ओर कुछ हम अपनी बात कहते। अब उनके यहां पर हाजिर न होने से सिर्फ एक तरफा बात ही रह गई है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्य से अपने हल्के की कुछ बातें कहना चाहूंगा। कुछ बातों के बारें में में तो मै पहले ही बता चुका हूं। कुछ काम भी हुए है ओर आगे होत भी रहेगे। आदरणीय मुख्य मंत्री जी उकलाना मण्डी में और बरवाला में 27. 10.1984 ओर 23.11.1985 को दोनों जगहो ंपर गए थे। मै हैफड की तरफ से उकलाना मण्डी में स्पिनिग मिल लगवाना चाहता था इसकी जमीनके लिय वहां पर दफा 4 और 6 के नोटिस जारी हो चुके थें उकलाना मण्डी में स्पिनिंग मिल लगाने के बारें मूं मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आप तो यहां पर यह मिल लगवानाचाहते है जबकि हमारा विचार तो यहा पर कपड़ा मिल लगाने का है। अब मै आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उकलाना मण्डी में जल्दी से जल्दी कपड़ा मिल लगाया जाये। यदि इसके लिये केन्द्रीय सरकार से लाईसैन्स की जरूरत हो तो वह भी ले लिया जाये। इसी प्रकार से बरवाला भी एक बहुत बड़ा कस्बा है। वहां की आबादी 30 हजार से ज्यादा है। वहां पर एक मैदा मिल को–आप्रेटिव सैक्टर में लगाने की बात मुख्य मंत्री जी ने मान ली

थी। लोगों की तरफ से यह मांग मैने उस समय रखी थी जब वे वहां पर गए थे। इसलिये इस बोरं में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बरवाला में मैदा मिल जल्दी से जल्दी लगायी जाये। यदि इसके लिए भी केन्द्रीय सरकार से लाइसन्स की आ यकता हो तो सह भी ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, यदि देहात में इंडस्टीज लग जाती है तो इससे काफी हद तक हामरी समस्याएं खत्म हो सकती है। जब तक देहात में इंडस्ट्रीज नही लग जाती तब तक देहात तरक्की नही कर सकता। जैसा मैने पहले कहा है हक जब मुख्य मंत्री जी 27.10.84 ओर 23.11.85 को उकलाना और बरवाला गए थे तो उस समय मैन मुख्य मंत्री जी के सामने लागों की तरफ से यह मांग रखी थी कि बरवाला की तहसी ल का दर्जा दिया जाये। इस मांग को सी0 एम0 साहन नके मान लियाथा। अब मै आपके माध्यम से सरकार से और मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अगर बरवाला को तहसी ल बना दिया जाता है तो उससे बरवाला, टोहाना, भट्टूकलां और रतिया हल्के के लोगों को काफी फायदा हा सकता है।

Mr. Speaker: Please wind up.

चौधरी इन्द्र सिंह नैनः अध्यक्ष महोदय, मै जल्दी ही समाप्त करने जा रहा हूं। अब मै एक बात अपोजी ान के भाईयों के बारें में कहना चाहूंगा। जो अपोजी ान आज के दिन हरियाणा में है वह अपना कंस्ट्रक्टिव रोल अदा नही कर रही। उनकी भी

उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि सरकार की है। वे भी पब्लिक के नुमाइन्दे है और हम भी पब्लिक के नुमाइन्दे हैं हम पर पब्लिक का बहुत भारी पैसा खर्च होता हैं आज हरियाणा पानी के लिये तरस रहा है। यदि वे वहांपर होते तो हमार साथ मिलकर रैज्यूल्य ून पास करते कि हरियाणा को पानी का अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए। जब रूलिग पाटी की तरफ से और अपोजी ज्ञन पार्टी की तरफ से यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार से पास जाता तो उससे कन्द्र सरकार पर बहुत प्रभाव पड़ता। वे लोगों के हमदद्र नही हैं उनको कोई प्रोग्राम भी नही हैं अढ़ाई साल तक उनका राज रहा। अध्यक्ष महोदय आपकों पता होगो कि विक्रम सम्वत 1956 में एक बार बहुत भारी कहत पड़ा था। लोग उसको छपना काल कहते हैं यही हाल अपोजी ान के भाईयों का हैं वे कुछ भी उचित काम नही करते। उनकों भी यदि छपा काल कहां जाये तो बहुत ज्यादा उचित बात होगी। अध्यक्ष महोदय, अन्त में वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मै उसका समर्थन करता हूं और आ ाा करता हूं कि हरियाण दिन दूगनी और राम चौगुनी तरक्की करेगा। आपने मुझ बोलने का समय दिया उसके लिये भी मै आपका एक बार फिर धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी हनुमान सिंह (टोहाना): आदरणीय महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पे ा किया है मै उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। सरकार ने यह बजट बड़ी सूझ–बूझ के

साथ पे ा किया है इस बजट में लोगों पर कोई नया टैक्स भी नही लगाया गया हैं (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, बजट में घाटा भी ज्यादा नही है। इस बजट का 75 प्रति ञत गांवों के विकास पर खर्च होना चाहिए। जैसे खेती बाडी, बिजली पानी और वाटर वर्कस आदि है, इन पर अधिक से अधिक पैसा खर्च होना चाहिएं मै बहुत लम्बी चौड़ी बात नही कहना चाहूंगा। मै आने हल्के को कुछेक समस्याओं और उनके समाधान के लिए सुझाव दूंगा। जैसे ट्रैक्टर, मैटाडोर, कार या दूसरी ऐसी गाड़ियां है, इन पर हमारी स्अेट में दूसरी स्टेट में दूसरी स्टेटों की बजाये दूसरी स्टेटों से लाना अधिक पसंद करते है क्यों कि लोगों को वहा परयहां की अपेक्षा कम टैक्स देना पड़ता हैं इस बोरं में मेरा सरकार को सुझाव है कि यहां पर इनके टैक्स कम किए जाएं ताकि इन गाड़ियों को लोग यही से खरीद सके। उपाध्यक्ष महोदय, अब मै दूसरी बात अपने हल्के की कहना चाहूंगा। वहां पर टोहाना, जाखल ओर रतिया के अन्दर एक नाले की खुदाई भाुरू हुई थी। इस पर सरकार को 50–60 लाख रूपया खर्च भी हो चुका है। रतिया के पास कुछ लोगों ने उस नाले की खुदाई को रोका हुआ हैं इस बारं में मेरा सरकार को सुझाव है कि यदि उस नाले की खुदाई न होने की वजह से बरसात के दिनों में लोगों को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, जब से दे ा आजाद हुआ है मेरे हल्के के अन्दर बहुत कम काम हुआ है अब सरकार ने कुछ ध्यान दिया है मै सरकार से यह प्रार्थना करूं कि वह टोहाना के इलाके की तरफ औरभी ज्यादा ध्यान दे। वहां सड़कों, बिजली, सिविल हस्पताल और वैटरिनरी हस्पताल आदिसभीचीजों की कमी है। भूना में केवल 10 वैड्ज का हस्पताल ळै। वहां पर कम से कम 30 बैड्ज का हस्पताल है वहां पर कम से कम 30 बैड्ज का हस्पातल होनाचाहिए। गवर्नर साहब के अभिभाशण में नए भूगर मिल हमारे इलाके में भी जल्दी से लगाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे एरिया के अन्दर बहुत सी हरिजन चौपालें बनने की पडत्री हैं मेरी सरकारसे प्रार्थना है कि उन्हें भी जल्दी पूरा करवाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, टोहान म्यूनिसिपल कमेटी की आमदनी बहुत कम है। मै सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसे ज्याद से ज्यादा मदद दी जाए ताकि वहा के लोगों का भला हो सके। डिप्टी स्पीकर साहब, एक सुझाव मै गवर्नमैंट को और देना चाहता हूं। आज हरियाणा मै मैटाडारे वाले सवारियों उठाते है। अगर सरकार मिन्नी बसों के परमिट अनएम्पलायाड लड़कों को दे दे तो एक तो अनएम्लायमैंट खत्म होगी और दूसरे पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलेगा। इन भाब्दों के साथ में वित्त मंत्री ओर हरियाण सरकार का हार्दिक धन्यवादे करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

बहिन शांति देवी (करनाल): उपाध्यक्ष महोदय, कल वित्त मत्री महोदय ने जो बजट पे ा किया वह सचममुच मे ंपहले

जितने बजट पे ा किये जो रहे हैं उनका अपवाद है। पहली बार इन्होने एसा बजट पे ा कियौ जिसमं न कोई नया टैक्स लगाया गया ओर न कोई टैक्स बढ़ाया गया और नही घाटै का बजट रखा गया। यदि एस0 वाई0 एल0 नहर का निर्माण केन्द्र सरकार अपने हाथ मे ले ले ओर खर्च वही कर ले तो तो 27 करोड़ के लगभग का जो घाटा है वह भ हट जाएगा। इससे यह संतुलित बजट तो वन ही जाता है। लेकिन मै कहती हूंकि यह एक तरफ से बचज का बजट है क्येांकि इस वश्र पिछले बजट का जो घाटा था वह भी खत्म कर दिया गयाहै नि चत ही बजट बनाना एक बड़ी कला है ओर हमारे वित्त मंत्री जी ने इस कला को पूरा सदुप्रयोग किया हैं इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं बजट बनाने में जो ध्यान रखनापड़ता है। वह यही है कि भूतकाल की वास्तविक आय और व्यय केा सामने रख कर भविश्य के लिए अनुमानित आय और व्यय का लेख जोखा रखा जाएं। उसमें खर्च अधिक है। तो घाटे का बजट बन जाता हैं यदि आय ज्यादा है ओर खर्च कम है तो बचत का बजट बन जाता है ओर यदि दोनों बराबर हजौ ता संतुलित बजट कह लीजिए यह एकसा बजट तैयार हुआ है जैसे एक परिवार का बजट तैयार होताळै। पढ़े लिखे परिवारों की गृहणियों और नौकरी पे ाा लोगों की गृहणियां इसी तरह से बजट बना कर रखती है। उनके बजट मे ंभेजन, मकान के किराये, मकान की मुरम्मत बच्चो की ि ाक्षा–दीक्षा, अमोद–प्रमोद चिकित्या ओर बचत आदि की व्यवस्था रखी जाती है ंप्रदे ा या दे ा का बजट भी इसी प्रकार से बनता है उसमें भी इसी तरह सके स्तम्भ रखे जाते

हैं हरियाणा के बजट में भी इसी तरह से स्तम्भ रखे गए है। भोजन की जगह कृशि है, इसके अलावा बिजली है, सिंचाई है, सहकारिता है, चिकित्सा है ओर ि ाक्षा है। बड़ी सूझबूझ से और समझदारी से खर्चे को बांटा गया है। समाज कल्याण और पर्यटन के लिये भी इसमें पैसा रखा गया हैं गरीबों की समस्यओां कासमाधान करने के लिए और उनकी भलाई के लिए बसी सूत्री कार्यक्रम के लिए भी रा ि ा निर्धारित की गई है। उद्योगों, सड़कों और आवास आदि को भी इसमे ंपूरी तरह से कवर किया गया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमार प्रदे ा कृशि प्रधान है। लगभग 80 प्रति ात लोग गांव में खेतीबाड़ी करते हैं इसलिए किसानों की मदद का ध्यान बड़ी सजगता से रखा गया है। हमारे यहां पहले से कई नियम और संस्थाएं चल रही है। जिनसे किसानों को पथ–प्रद र्ान मिलता है। जिससे वे खेतों में पैदावार बढ़ाते हैं ओर दे ाकी आर्थिक स्थिति में लाभ होता हैं किसानों के खेत खराब न हो ओर पैदावार ज्यादा हो इसके लिए मिट्टी, जल और अच्छे बीजों के परीक्ष्ज्ञण किए जाते है। सब्जी और अनाज के अच्दे बीज तैयार करके लोगों को दिए जात है। करनाल में आलू काफी बोया जाता है हैं यहां हम देखते है कि बहंत किस्म के आले है। उनलकी अनुसंधन का काम भी वहां होात हैं यह देखा जाता है कि कैसक कीडों से उनको बचाया जाए या कैसे बीमारी से उनकों बचाया जाए आलू अधिक हो, पक्क हे, कब उन्हे बाया जाए और कब उखाड़ा जाए इन सब बातों को भी प्रद र्ान

चलात रहता है। लहसुन, धान, गेहू ओर दूसीर उपजों के बारें में भी वहां गाइडैस दी जाती है। रेडियों पर भी लोगों को काफी कुछ बताया जाता है। आजकल तो टी0 वी0 के ऊपर भी बहुत कुछ दिखाया जाता है और प्रचार कियाजात है बीज कैस बाये, अगेता बाये, पीछे से बाये, कैसे खराब होने सक बचाएयें, कैसे कीट ना ाक औशध्यिों प्रयेा करें, यह सब दिखाया जाता है। ऐसी कितनी ही पत्र पत्रिकाएं है जो इस तरह की जानकारी लोगो को देती है। कई दफा किसानों के लड़कों और खेती करने वालों को ि ाविर लगा कर भी ये बातें सिखाई जाती है। हमारी गवर्नमैट इस मामले में बड़ी सजग है। कोई देवी विपति आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए तो भी हमारी सरकार किसानों को मदद देती है और राजस्व आदि माफ करती हैं बहुत बार तो अनुदानदेने का भी प्रावधान किया जाताहै ंपरिणमास्वरूप हमारे प्रदे ा में अनाज का उत्पादन लगातार बढ रहा है। हमारी जा अर्थ व्यवस्था अै और निवे ा की जा निधिण है वह सरकार की बुद्धिमता पर निर्भर करती है। पैदावार खेतों में होती है लकिन उसे मंडियों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया है। किसान के अनाज की बिक्री हो जाए उसको लाभ किले, इकसे लिए मार्किट कमेटियों बनाई गई है। वहां थोड़ी सी फीस देने पर उनके सामान की बिक्री का प्रबन्ध किया जाता है ओर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। यह भी किसानों की भलाई के लिये है। मार्किट कमटियों मे ंभी उनके विश्राम करने के लिए स्थानों का प्रबन किया गया है। वहां पर किसानों को आराम करने, पानी का प्रबन्ध तथा

प ुओं को खड़े करने का प्रबन्ध किया गया है। यह सब कार्य सरकार इस दृश्टि से करती है कि किसानों को सुविधा मिले। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदे ा में खेती की ओर लोगों का रूझान अधि ओर अच्छा रहे ओर लोगों को हानि न हो, लाभ हो ताकि लोग इस पे ो को खु ी–खु ी से अपनाये। इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिये। वैसे तो यह पे ाा कश्टप्रद है। तगड़े ओर मजबूत आदमी जो इस पे ो मे ंपरम्परा से लगे हुए है वही करसकते है या इस पे ो कोवे लोग करते है जो कोई औरकार्य नही कर सकते हैं लेकिन फिर भी दुख सुख पर कर दूसरों की सेवा की भावना की दुश्टि से खेती सभी पे ाो, धन्धों से उत्तम है। यह मानप कर वे इस धन्धे को करते रहत है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो कृशि वि वविद्यालय से जो जवान डिग्री ले कर निकलते है उनमें से खेती बहुंत कम करते है। दूसरे प्रायः आजकल नौजवानों का खेती की ओर कम ध्यान है, नौकरी के पीछे ज्यादा दौड़ते है।

उपाध्यक्ष महोदय, खेतीबाड़ी का संबंध सिंचाई से भी है। सिंचाई के लिए बिजली को भी आधार लिया जाता है। मेरे अपने इलाके में नहरों का पानी भी जाता है ंओर टयूबवैल्ज पर तो बहुत ही आधारित है। इसलिए सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि एक बून्द पानी खेती के काम मे ंआये। सरकार ने खेतों के खालों और नालों को पक्का बनवाया है। यह सब पानी को जाया होने से बचाने के लिए किया है। इसके अलावा बिजी की कमी को

दूर करने के लिए पानीपत और यमुनानगर में अधिक मैगावाट ये यूनिट लगाने का प्रबन्ध किया हैं पि चमी यमुना कैनाल पर मार्च, 1986 तक दो यूनिट आठ आठ मैगावाट के चालू करने का प्रावधान है। इस प्रकार इन यूनिटों को चालू होने के प चात् खेाती ओर इन्स्ट्रीज को और भी अधिक लाभ होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर अगस्त, 1986 तक हरियाणा मे एस0 वाई0 एल0 का पानी आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है ओर हरियाणा के लोगों को बहुत ही लाभ होगा। हमारे प्रदे ा के लोग प्रभुभक्त है, प्रभु के वि वास रखने वलो है, दूसरों की भलाई मे अपना भला मानते है, इस दृश्टि से प्रभु जरूर कृपा करेगे। हम ऐसा मानेगे तो भगवान के घर देर है अन्धेर नही हैं हम आ ाा रखे कि हम एस0 वाई0 एल0 का पानी जरूर मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कृशि का वास्ता प ाुपालन से भी है। हरियाणा प्रदे ा तो प ाुओं के लिए बडा म ाहूर रहा हैं हरियाणा के बारें में कहा जाता था कि दे ाों में दे ा हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। पिछले दिनों हमारे यहां प ाुओं में कमी तो जरूर आयी लेकिन अब सरकार ने बहुत अच्छा प्रबन्ध किया है। गाय अैर भैसे अच्छी अच्दी नस्ल की तैयार की जा रही हैं जो गाय और भैसे पहले थोड़ा दूध देती थी अब अधिक दूध देती है। उनको सारे प्रदे ा में वितरा करके ठीक तरह से काम किया जा रहा हैं हामरे प्रदे ज्ञ में प ाुओं की प्रद र्ान लगायी जाती हैं यहां पर अच्दी प ाुओं की प्रतियोगिता होती हौ जिसमें

अच्छे प ाुओं को ईनाम आदि देकर प्रोत्साहन दिया जाता है। प ा पालन के बारें में सरकार की ओर से वि ोश ध्यान दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में वनों के लिए लम्बा चौड़ा स्थान तो नही है। जहां पर जंगल लगाये जासके लेकिन नहरों के किानों और गांवों की फिरनी में जो भूमि उपलब्ध है वहां पर दरखत लगाये जा रहेह। स्कूलों, मेन सड़कों के किनारे पर भी वृक्ष लगाये जा रहे हैं वृक्षों की हरियाली से हरियाणा प्रदे ा बहुत ही अच्छा लगता है इस वर्श 22 हजार हैक्टेयर भूमि पर 38 लाख वृक्ष लगाये जायेग। लोगों को रोजगार मिलेगा, एनावायरनमैट में सुधार होगा और जो एनक्रोचमेंट होती है उसमें भी कमी होगी। आजकल थोड़ी थोडी भूमि पर भी लोग कब्जा करने के लिए तैयार हो जाते है बल्कि कर ही लेते हे। जब किसी आदमी का कब्जा करने के लिए तैयार हो जाते है बल्कि कर ही लेते है। जब किसी आदमी का कब्जा हो गया तो उसे हटाया या उखाड़ना सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। यदि सरकार अपनी ऐसी भूमि को वृक्षों के लिए प्रयोग में ले आये तो लाभ रहेगा। दूसरे सरकार को भी ऐसी मुसीबत से बचाव हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, करनाल में बहुत गन्दे गन्दे नाले है। जो फैल कर चौड़े होते जाते है जिनकी सफाई करना बहुत मु ाकल हैं उन नालों को पक्का करके उनके किनारों पर तीन तनी और चारी चारी की लाईन में सफेदे के वृक्ष लगाये जाये। ऐस करने से वे ऐसे कन्दुर

लगे अजैसे का मीर मै श्री नगर है। इस तरह से गोवों ओर भाहरों में किया जाये तो बहुत अच्छा लगेा। इसके लिए बड़े प्रयत्न, नग्न और उत्साह की जारूर है। पैसे का तो वनों के लिए पहले से ही प्रावधान है। अगर इस तरफ ध्यान दिया ाजये तो बहुत फायदा रहेगा। भाहरों मं नालों के आसपास की जमीन पर लोग कब्जा कर लेते हैं भाहरों में लोगों की रूचित है कि उने दरवाजे के आगे या साइड पर हरा भरहा हो। हमारे यहां हाउससिग बोर्ड या हुड्डा की जो कालानिया है वहो परि जितनी भी सड़के या जगह बची हुई है वहां पर पौधे लगाये जाये तो अचछा लगेगा। उन जगहों पर लोग तार लगा लेते है अगर वहां सरकार वृक्ष लगा दे तो उन्हें तार लगाने की जरूरत नही पड़ेगी और सरकार को एनक्रोचमेंट हटाने में जो दिक्कत है उससे भी सरकार बच जायेगी। वनों से मौसम भी ठीक रहता है और सुन्दर भी लगता हैं जहां ये लाभी हाते है वहां पर्यावरण की भी भाुद्धि होती है। वनों से लोगां को राजगार मिलता है, वर्श अधिक होती है, मानव मात्र को जीवन मिलता हहै इसलिए वनो ंकी तर जो ध्यान दिया जा रहा है इस पर और अधिक जोर दिया जाये तो अच्छा रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा में परिवहन विभाग सबसे सराहनीय कार्य कर रहा है। हमारे प्रदे ा में बसों क अड्डे सबस से बढ़िया है। यहां पर पुरस्कार भी मिले हैं हिसार के बस अड्डे को प्रथम पुरस्कार मिला हैं हम लोग भी अपने बस अड्डे

को अच्छा बनानक का प्रयत्न करें। कम्पीटि ान से प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती हैं इसलिए हम सब को अपने अपने हल्कों में कोि ा ा करनी चहिए कि बस अड्डो अच्छे हो।

इसके अलावा ि ाक्षा मानव जीवन क लिए हुत जरूरी है। इससे मनुश्य का जीवन और स्वभाव सरल हो जात हैं इसकेलिए सरकारभी प्रयत्न कर रही है। हर आदमी का पढ़ाई की तरफ रूचि लेनी चाहिए। वास्तविक ि ाक्षा ग्रहरण करना ही अच्छा लगता हैं ि ाक्षा भाारीरिक औरदिमागी तोर पर होनी चाहिए। जो ऐसी ि ाक्षा ग्रहण करता है वही सफल नागरिक बन सकताहैं आजकल जो ि ाक्षा प्रणाली चल रही है वक मैकाले प्रणाली चल रही है उनकी ि ाक्षा प्रणाली यह थी कि सरकार को क्लर्क और बाबू मिले औरआज भी यही प्रणाली चल रही ी। आज भी हम नौकरी प्राप्त करने की दृश्टि से ि ाक्षा प्राप्त करते है। ि ाक्षा से मनुश्य जीवन मे ंपरिवर्तन आना चाहिए। ि ाक्षासे आदमी का जीवन आद र्ा, सच्च और कर्त्तव्यनिश्ठ बनाना चाहिए लेकिन वह नही बन रहा है। जैसा कि अभी मैने कहा कि पढ़ाई एक तरह से पढ़ाई के लिए है। हिसार के वि ववविद्यालय से कितने लोग डिग्री प्राप्त करके निलकते है लेकिन उनमें से कौन खेतीबाड़ी करता है? इंजीनियरिग करके इंजीनियरिग कालेज कसे निकलते है लकिन उनमें से कितने लोग कारखाने खोलत है? मै समझती हूं कि इसका कुछ कारण हैं हामरी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जिसको अवसर प्राप्त हुआ है, जिसने डिग्री प्राप्त की है

उसके उस तरफ ध्यान देना चाहिए। जिस को अवसर प्राप्त हुआ है, जिसने डिग्री प्राप्त की है उसकेस उस तफ ख्याल करके प्रोत्साहन दे। उनको काम करने के लिए आगर प्रोत्साहन देगे तो वे जरूर काम करेगे। फिर आम आदमी की पूछ बढ़ेगी, उनके द्वारा की गयी खेती ओरअच्छी होगी औरउत्पादन भी अच्छाह होगौ। इसके अलावा काम भी बढ़िया होगा। इससे दे ा को भी अधिक फायदा होगा। हरियाणा में ि ाक्षा के लिये प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल, हाई स्कूल और कालेज खोलते जा रहे है ओर समय समय पर प्राइमरी से मिडल, मिडल से हाई, इसी तरह से अपग्रेड करके उनको बढ़ाते जा रहे हैं लड़कियें की ि ाक्षा की तरफ भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। यह एक बहुत ही अच्छी बात हैं लड़कियों की ि ाक्षा से एक साथ दो फायदे है। परिवार में लड़कियों के ि ाक्षित होने पर वातावरण अधिक सुधरता है, बदलता है और ठीक रहता है, दूसरे लड़कियों को सर्विस वगैरा किलने से भी फायदा हैं समाज में जो बुराईया है, जैसे रि वतखोरी है या दूसरी बातें है, इनकी तरह महिलाओं का ध्यान पुरूशों की निस्बत कम जाता है। अब वैसे तो कोई भेद भाव नही है, बुराई किसी ओर सै भी हो सकती है लेकिन फिर भी लड़कियों में उनकी प्रति ात कम है। मेरा कहना यह है कि महिलाओं की ि ाक्षा की ओर जा ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः बहिन जी, अब करनाल की समस्याओं की तरफ आ जाएं।

बहिन शांति देवीः बहुत अच्दा जी। उपाध्यक्ष महोदय, करनाल मे ंभी कुछसमय पहले प्राइवेट कालेजों में समस्या था। वहां पर भी लोग मुझेसे मिलने रहते थे। हमारी सरकार ने उस समस्या को खत्म कर दिया है। यह बहुत अच्दी बात की गयी क्योंकि ि ाक्षकों को सहयोग मिलना अच्छी बात है ताकि वे अपने कश्टों ओर अपनी असुविधाओं से नि चत होकर कुछ काम मेें लगे। ि ाक्षा का जो आज स्तर है, हम देखते है कि जिधर जाना चाहिये, उससे हम गिर ही रहे हे। इसकों कौन संवारेगा? यह किसी को पता ही नही है। ि ाक्षा, ि ाक्षक ओर ि ाक्षार्थी का संबंध होना लाजमी है। अगर ि ाक्षक ईमानदार है, परिश्रमी है, उत्सा ाील है, लग्न ाील है, तो ि ाक्षार्थी भी वैसा ही होगां वैसे ही हमारे अफसर बनेगे, डाक्टर बनेगे, एम0 एल0 ए0 बनेगे, मिनिस्ट बनेगे, ि ाक्षक बनेगे, नेता बनेगे और सब कुछ वही बनेगे। तब हमें उम्मीद है कि जैसा राजीव जी चहाते है,स्वच्छ प्र ाासन और सारे दे ा में स्वच्छता लोने का काम, वह भाायद पूरा हो सके। हमार मकसद यह है कि सच्चे और ईमानदार आदमी हमें मिले। अगर किसी वृक्ष पर ऐसे आदमी लगत`हो तो हम पेड़ से तोड़ लेते, अगर किसी खान में से निकलते हो तो हम वहां से निकाल लेते या किसी खेत में अगर उपजत हो तो हम वहां उपजा लेते लकिन अफसोसे कि ऐसा नही है। जब तक हम समाज को ऐसा नही बनायेगे तब तक काम नही चल सकता। हमें चाहिये कि हम खुद ऐसा बने और अपने बच्चों को ऐसा बनाये। इसके लिए ि ाक्षकों को भी प्रयत्न करना होगा, माता पिता को भी प्रयत्न

करना होगा और घ्ज्ञर से माहौल को अच्छा बनाने की तरफ भी हमकों ध्यान देना होगा। प्राचीन काल में हामरा दे ा इस चीज के लिये बहुत ही म ाहूर था। हम चाहत है कि हमारा समाज अच्छा बने जाये। ि ाक्षा भी हमारे प्रदे ा के लोगों का अधिकार हैं

इसके अलावा, हमं लोगों के स्वस्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिएं।रोगी तो प्रदे ाके ऊपर बोझ बन जाता है और वह दूसरे के पराधीन हो जाता है। इसलिये सरकार अस्पताल वगैरा का निर्माण कर रही है। करनाल में अस्पताल की बिल्डिग का अभी तक भी निर्माण नही हुआ है। इसके लिए मै बार बार, हर रोज जितनी बार भी बोलती हूं, कहती हूं विहां पर अस्पताल का निर्माण जरूर होना चाहिए। श्री ए0 सी0 चौधरी से मै एक बात कहना चाहती हूं कि जिस तरह से ग्रामफोन मे जब कोई खरबी आ जाती है अैर उसकी सूई एक जगह ही रूक जाती है तो वही भाब्द बार बार निकलता रहता है, उसी तरह सेमेरा भी वही हाल है। जब तक वहां पर अस्पताल बन कर तैयार1 नही होग, तब तक मै परे ाान रहूंगी ओर मेरा य नम्र निवेदन अपनी सरकार से चलता रहेगा। मै यह कहती हूंकि यह सुविधा सभी हल्कां में होनी चाहिए। दूसरी लगभग सब जगहों पर गांवों में भी और भाहरों में भी अस्पताल बन गये है। लेकिन करनाल में अभी नही बना है। इसे लिए मंत्री महोदया ने आ वासन तो दिलवाया है, मे इसके लिए मंत्री महोदया को धन्यवाद भी देती हूं।

इसके अलावा जन–स्वास्थ्य के लिये यानी जल–मल के बारें में भी कुछ कहना चाहती हूं। इसकी महत्ता भी काफी है। एक बात अव य है कि करनाल में भी सीवरेज सिस्टम लागू होना चाहिये। बहुत सी जगहो ंपर गलियों में ओर सड़कों में सीवरेज सिस्टम तो है लेकिन वहां पर लोगों ने अपनी मल निकास की पाईप को नही जुडवाया है। वे इस सुविधा का प्रयोग नही करते। जैसे माडल टाउन हमारे यहां एक पो ा बस्ती है। अमीर लोगों की बस्ती है। उसमें भी जहां पर सीवरेज लगी हुई है, वहां पर भी लोग कनैक ान नही लगवाते। सरकार को कोई ऐसा अनुमान बनाना चाहिए कि जिससे जहां जहां पर यह सीवरेज लगी हुइ है, वहांपर कनैक ान लोग ले ले। अगर इसके लिये कोई टाईम लिमिट भी रखनी पड़े तो बे ाक रख दें कि कम से कम इतने समय में लोग अपना खर्चा करके कनैक ान लगवा ले। जो उस टाईम लिमिट में कनैक ान न लगवाये उसे ऊपर फिर 400 या 500 रूपया लगा दें। इससे वहां पर लोग अपने आज सीवरेज कनैक ान लगवा लेगे। अगर सरकार ऐसा नही कर सकती तो सरकार अपनी तरफ से कोढ ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि वह अपने आप पैसा खर्च करके सबके कनैक ान लगा दे ओर उनसे भविश्य में पैसा वसूल करती जाये। इससे वहां पर मक्खी मच्छर और बीमारी कम हो जायेगी। करनाल वैसे ही बहुत बड़ा भाहर है उसमें काफी इलाको मे ंएक दूसरे के मुकाबले मे फर्क हैं पब्लिक हैल्थ वालों को यह चाहिये कि जिन इलाकों में सीवरेज नही है,

वहां पर सीवरेज डाले और जहां पर लोग यह कनैक ान नही ले रहे है, वहां पर लोगों को इसे लेने के लिये कहे।

इसके अलावा समाज कल्याण विभाग का काम भी ठीक है परन्तु वहां पर स्टाफ में कम से कम 2–4 आदमियों की बढ़ौतरी जरूर होनी चाहिये ताकि वहां से मनी–आर्डर्ज भेजने में दिक्कत न हो ओर पै ान पाने वालें को समय पर मनी आर्डर मिल जाए असहाय लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा है क्योंकि सरकार द्वारा अगर ऐसो असहाय लोगों की कोर्ठ सहायकता न हो तो यह कोई अच्छी बात नही हैं यह सुविधा हमारी कांग्रेस सरार ने ही चालू की हुई हैं एक बार बीच में हरियाणा में भाायद वि ाल हरियाणा पार्टी की सरकार या कोई दूसरी सरकार आयी तो उस वक्त यह पै ान बन्द कर दी गयी। उस समय मंत्री महोदय हमारे करनाल के ही थे। हमें दफ्तर वालों ने यह कहा कि यह योजना तो हमने खत्म ही कर दी हैं हमने यह पूछा किय क्यों खत्म कर दी गयी है तो हमें कोई जवाब नही मिला। हम फिर मंत्री महोदय के पास गये और उनसे पूछा तो वे कहने लगे कि यह योजना बन्द हो गयी, हमने पूछा क्यें तो कहने लगे कि लोग पैसा खा जाते थें तो इस योजना को हमारी कांग्रेस सरकार ने आकर फिर चालू किया। यह बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी सरकार गरीब आदमियों की मदद कर रही है। स्वतन्त्रता सेनानियों की भी हमने मदद की है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन भी गरीब लोगों की मदद की गयी। है एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत योजना बनाकर भी लोगों की बहुत

मदद की गयी हैं लोगों को इस बजट द्वारा काफी राहत दी गइ हैं यह खु ाी की बात है कि इसमें कोइ भी नया कर नही लगाया गया है। जैया कि आज अखबार में भी आया है, इस बजट में लोगों की मदद ही दी गयी हैं ट्रैक्टरों के ऊपर बिक्री कर में कमी, दालों और बर्तनो पर बिक्री कर में कमी गयी है। सरकारी सेवा से निवृत सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दी गयी है। बस की यात्रा करने वालें के लिये बीमा योजना बनाई गयी है। यह बहुत ही बढ़िया बात की गयी हैं ग्रामीण उत्थान के लिये जो स्कीम बनायी गयी है, यह बहुत ही अच्छी स्कीम है। इससे प्रत्येक गांव सुलक्षण बनन की कोि ा ा करेगा। सरकारी कर्मचारियों को जो आउटडोर फिक्सड मैडिकल अलाउंस की सुविधा दी गयी है, यह भी एक अच्छी बात है। इससे एक बुराई भी समाप्त होगी और जो लोग अभी तक इसका फायदा नही उठा पाते थे, उनकों भी लाभ होगा। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो डबल काम किया करते थे, उनको ंभी 30 रूपये प्रतिमास वि ोश भता दिया जायेगा। यह चाहे थोड़ा है, लेकिन एक अच्छी बात है। मै एक बात आपकी सेवा में और कहना चाहूंगी कि पिछले वर्श इसी जगह पर बजट अधिवे ान में बायों–गैसै बर्नर्ज को हर मुक्त किया गया था लेकिन मुझे यह पता चला है कि उससे संबंधित जा एप्लायैसिज है, उन पर टैक्स जब भी लगा रहा गया है इस बारें में मुझ लोगा ंने बताया है कि दूसरी स्टेट्स में ऐसा नही है। वहां पर सब माफ किया गया हैं मै सरकार से नम्र निवेदनल करूंगी कि इस पर नजरसानी की जाए। कुछ लोगों ने मुझे पहुंच की थी और मुझ

`पेपर भी दिए थे। वे मैने मंत्री महोदय को पे ा कर दिए है। मुझे आ ाा है कि इस बारें में वे इसी सै ान में अनाउंस करेगे। उपाध्यक्ष महोदय, इतना कहकर मै समाप्त करती हूं और जो बजट पे ा किया गया है, मै उसका समर्थन करती हूं।

श्री भले राम (बड़ौदा, अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, मरे से पहले बोलने वाले दो साथियों ने इस बजट की प्रं ाांसा की है और मै समझता हूं कि बजट का बुरा या अच्दा कहने से पहले हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पैसे का बंटवारा हुआ है वह न्यायासंगत है या नही है और हर हैड में जितनी जिसकी प्रायरिटी के हिसाब से जरूरत थी वह रखा गया है या नही। उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते है कि हमारा प्रदे ा ज्यादातर ऐग्रीकलचर पर निर्भर करता है। इस मद में जो पैसा कृशि के लए रखा गया है वह बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से पावर और दूसरे महकमों के लिए पैसे का बंटवारा ठीक ढंग से किया गया हहै इसलिए यह बजट बैलैन्सड बजट है और इस कारण इस बजट को प्रोएम्पलाइज, प्रो–फारमर और प्रो–उद्योगपति कहे तो गलत नही होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, जब हमारे प्रधान मंत्री ने ओथ ली थी तो उनहोने कहा था कि दे ा मं प्रोडक ान बढ़ेगी, दे ा तरक्की करें और उने आदे ा और निर्दे ा के मुताबिक चलते हुए हमारे प्रदे ा ने काफी तरक्की करेगा और दे ा में स्टैगने ान नही होगी। वे चाहते है कि हर प्रदे ा तरक्की करें। अगर हम पिछले आंकड़े उठाकर देखे तो पता चलता

है कि 1970–71 की कीमतों पर 4.1 प्रति ात वृद्धि से राज्य की आय 1562 करोड़ थी जो 1984–85 में कीमतों पर 10.3 प्रति ात वृद्धि से स्टेट की आय 4635 करोड़ हो गई क्यों कि सात परसैन्ट ज्याद है। इसी तरह से हामरी स्टेट की परकैपिटा इन्कम 1984–85 में 7.7 प्रति ात बढ़ी ओर इस समय वह 3296 रूपए के स्तर तक पहुंच गई हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए हम महसूस करते है कि हरियाणा दिन दुगुनी ओर राज चौगनी तरक्की कर रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब इसी तरह से 1985–86 को जो हमार ऐनुअल प्लान था वह 480 करोड़ रूपए का था लेकिन किसी कारणव ा हमें अपनी योजना के खर्चे में थोड़ी काट छांट करनी पड़ी। 1986–87 के लिए वार्शिक योजना 525 करोड़ रूपए नियम की गइ है। इसका मतलब यह है कि 45 करोड़ रूपया ज्याद रखा गया है। यह रूपया बिजली, पानी सौ ाल सर्विसिज और दूसरे ग्राम विकास के कार्यो पर खर्च किया जाएगा। 1985–86 में जितना रूपया इन कामों पर खर्च किया गया था उससे कही ज्यादा रूपया आने वाले वर्श में इन कामों पर खर्च किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, 169 करोड़ रूपया सिंचाई पर खर्च किया जाएगा ओर 163 करोड बिजली पर खर्च होगा। डिप्टी स्पीकरसाहब, छठी पंचवर्शीय योजना में राज्य सरकार का योजना खर्च 4576 रूप्ए का था जिसकों सातवी पंचवर्शीय योजना में बढ़ाकर 2900 करोड़ रूपया कर दिया गया है। इस तरह से जो रूपया बढ़ाया गया है उसमें से ज्यादा खर्चा सिचाई और बिजली पर किया जाएगा। 1000 हजार करोड़ रूपए से अधिक का परिव्यय बिजली पर ओर 585 करोड़ रूपए का

परिव्यय सिचाई पर किया जाएगा परिवहन पर 200 करोड़ रूपया सातवी पंचवर्शीय योजना पर खर्च होगा और सो ाल सर्विसिज पर 555 करोड़ रूपया खर्च किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, हगर हम इन आंकड़ों को कम्पयेर करें तो पता लगता है कि हर साल हमारा प्लान बढ़ता जा रहा हैं

प्लान में जितना रूपया रखा गया है उसमें से ज्यादा रूपया इरीगे ान पर खर्च होगा। डिप्टी स्पीकरसाहब, अगर हरियाणा का पूरा पानी मिल जाए ओर जितनी जमीन खु क पड़ी है। वह सैराब हो जाए तो हम पंजाब सें भी आगे बढ़ सकते है। यह खु ाी की बात है कि प्रधान मंत्री के ऐकार्ड में 15 अगस्त तक नहर बनाने का प्रावधान हैं यह नहर तेजी से बननी चाहिए। अभी तक खुदाई का काम केवल 70 किलोंमीटर ही हुअ हैं जहां तक लाइनिग का संबंध है। वह तो कवल एक या दो किलोंमीटर ही हुइ हैं डिप्टी स्पीकर साहब, इस नहर की तरफ ज्यादस से ज्यादा ध्यान दिया जाए ताकि हमारा प्रदे ा तरक्की कर सकें। यह अच्दी बात है कि इरीगे ान के लिए 130 करोड़ रूपए से भी ज्यादा रकम रखी गई है। इसमें एस0 वाई0 एल0 भी भाामिल है। इससे 1986–87 के लिए 77.65 लाख टन रखा गया है। यह पैदावार सिंचाई सुविधा ज्यादा देने के कारण है। डिप्टी स्पीकर साहब, आगामी वर्श के लिए खाद्य उत्पादन का लक्ष्य 77.65 लाख टन रखा गया हैं आ ाा यह है पैदावारइससे भी ज्यादा होगी। मेरी प्रार्थना यह है कि सिचाई की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

यह खु ी की बात है कि हरियाणा लैड रिक्लेमेशन एण्ड डिवेल्पमैंट कार्पोरे ान द्वारा नौ हजार हैक्टेयर कल्लर भूमि को सुधारने और 5600 हैक्टेयर ऊंची नीची भूमि को समतल बनाने की संभावना है। दो तरह की कल्लर भूमि होती हे। एक सफेद और दूसीर काली। सफेद कल्लर भूमि भूमि तो जिप्सम से सुधारी जाती है। और काली भूमि के सुधार के लिए मुडलाना में एका पाएलैट प्रोजैक्ट काम कर रहा है। और दूसरा सांपला में काम कर रहा है। जिस तरह से आदमी के भारीर में सीगी लगा कर आदमी का बन्दा खून चूस लिया जाता हैा वह स्वस्थ कर दिया जात है उसी तरह से कल्लर जमीन को सुधारा जाता है। जब हम सारी जमीन को ठीक कर लेगे तो हमारी पैदावार बहुत ज्यादाब बढ़ जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली की कई स्कीम्ज चालू हैं पानीपत और यमुनानगर में छोटी बड़ी कई स्कीम्ज पर काम हो रहा है लेकिन बिजली की रिक्वायरमैंट भी हर क्षेत्र में चाहे वह डौमैस्टिक है, चाहे इंडस्ट्रीज क्षेत्र है ओर चहे एग्रीक्लचर सैक्अर है, बढ़ती जा रही है। लोग नए–नए टयूबवैल्ज लगा रहे है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना हैं कि बिजली को प्राथमिकता देकर उसक उत्पादन बढ़ाया जाए। इस संबंध में मै एक बात और कहना चाहता हूं कि हरिजन ओर बैकवर्ड क्लासिज के लोगों ने टयूबवैल्ज आदि के लिए बैक्स से लोन लिया हुआ हैं सरकार की तरफ से हिदायत है जिन्होने लोन ले रखा है उनकों बिजली का कनैक ान देने में प्रयरिटी देनी चहिस। जिस हरिजन भाईयों ने चक्की के लिए या टयूबवैल्ज के लिए लोन लिया हुआ है उनके

केसिज में तो हो सकता है कि प्रायरिटी बेसिज पर कनैक ान मिल जाता हो लकिन जहां तक बैकवर्ड क्लासिज के लोगों का ताल्लुक है। उनकों कनैक ान नही मिलता। मेरी प्रार्थना है कि उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दें।

डिप्टी स्पीकर साहब, पहले गांव के लोगों में हाथ से काम करने की भावना थी। गांव में कोई जोहड खुदना हो, कोई सड़क बननी हो या नालियां बननी हों तो ढोल बजाकर एनाल कर दिया जात था और लोग खुद कार करते थे। अब सरकार ने उन गांवों को सुन्दर बनाने के लिए एक स्कीम भाुरू की हैं यह स्कीम उन गांवों के लिए बनाई गई है। जो गांव अपने विकास के काम में आगे बढ़ेगा, सराकार एसे गांव को ईनाम देगी। यह विकास चाहे सफाई में हो, चाहे फैमिली प्लानिग में हो और चाहे गांव में झगड़े कम होने के बारें में हो। जो गांव अपने आपकों माडल विलेज बना लगा, आद ा विलज बना लेगा और जो सब से अच्छा होगा उसकों एक लाख रूपए का इनाम दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में तीन गांवों का चुना जाएगा। जो पहले नम्बर पर आएगा उसकों एक लाख रूप्या, दूसरे नम्बर वाले को पचास हजार रूपया और तीसरे लम्बर पर आने वाले को पच्ची हजार रूपया दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर सहब, गांवों में विकास कार्यो को प्रोत्साहन देने का यह अच्छा तरीका है, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, यह अमाउंट बहुत कम हैं आपको पता है कि गांवों की हालत काफी खरबा होती है इसलिए इस अमाउंट को यदि और बढ़ा दिया जाए

तो अच्छी बात है। यह रा ि ा बढ़ाकर दो लाख के करीब पहले नं0 पर अपने पर गांव के लिए कर देनी चाहिए, दूसरे नम्बर पर आने वाले गांव को एक लाख व तीसरे नम्बर पर आने वाले को 50 हजार के करीब देना चाहिए ताकि गांवों को सुन्दर बनाने के लिए ओर प्रोत्साहन मिल सकें। ज्यादा इमदार से गांवों का ढांचा बदल सकता हैं

एक बात सरकार ने एम्पालईज के बोरं में जो की है वह ठीक हैं यह मांग हुत ही लम्बे अर्से से चली आ रही थी। कुछ लोग क्या करते थे कि डाक्टरों से जाली पर्चियो बनाकर और बिल बनवा कर नाजायज फायदा ठा रहे थे। हरियाणा में इस समय अढ़ाई लाख के लगभग एम्पलाईज होगे ओर इस मैडीकल फैसिलिटी का केवल 10 हजार लोग ही फायदा उठा रहे थें बाकी के कर्मचारी सरकार की सहूलियत से महरूर रह ाजत`थे। इसलिये सरकार ने अब यह फैसला किया है कि हरेक एम्पलाई को राहत देने` लिए 100 रूपये की रा ि ा फिक्स कर दी है। अब चाहे कोई बीमार हो या न हो,यह इस फैसलिटी का फायदा उठा सकेगो। यह तो सरकार ने ठीक किया लकिन एक बात मै यह अव य कहूंगा कि एक फैक्टर की ओर भी सरकार को ध्यान देनाचाहिये। कुछ लोग यंग एज के हिसाब से बीमार ही नही होती और कुछ बेचाए एज फैक्टर के ाकरण सालो भर खाट पर ही पड़े रहते है। गुप्त जी यहा पर बैठे है। मै उनसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि वे मरे इस

सुझाव पर अव य ध्यान दे ताकि जो इस तरह के लोग है वे सरकार से ज्यादा राहत पा सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, अगली बात मै सरकार की इस बात की सरहाना करूंगा कि उसने ि ाड्यूल्ड कास्ट्स की भलाई के लिये काफी कुछ किया है और बहुत सी स्कीम्ज भी बनायी हैं यह बहुत अच्दी बात हैं 29 करोड़ रूपये की स्पै ाल कम्पोनेन्ट स्कीम सरकार ने बनायी है ओर 12 करोड़ रूपये के लगभग इस साल खर्च करने जा रही है। मुर्गी पालन, भैस खरीदने ओर रेड़ा बग्गी लेने के लिये और दूसरी कई स्कीम्ज सरकार ने बनाई है जिन्हें हम आर्थिक विकास की स्कीम्ज कह सकते हैं इन से लोगो ंको काफी फायदा हेागा। इसके साथ साथ लोन और ट्रकों के परमिट वगैरहा देकर भी इस सरकार ने हरिजनों के लिए काफी सुविधाए प्रदान की है ऐजुके ान में भी हरिजन बच्चो को काफी सहूलियते दी गयी है जैसे बच्चों की फीस माफ करना, बच्चों को वर्दियों व स्कौलरि ाप देन इत्यादि यह भी बड़ा सराहनीय कदम है। इससे हम इन्कार नही कर सकते लकिन कुछ पुरानी स्कीम्ज है जिनमें जितना पैसा दिया जाना था उतना नही दिया गया है मिसाल के तौर पर जैसे स्टाइपैड के पुराने रेट्स है जो आज से 10–20 साल पहले थे, वही है। डिप्टी स्पीकरसाहब, आप को पता है कि चीजों की कीमते आजकल कितनी बढत्र गयी हैं लेकिन स्टाइपैड के रेट्स वही पुराने है। आज बच्चों के लिये किताबों और कपड़ों की कीमतों में 10–20 साल पहले से काफी अन्तर है।

अब यह चीजें मंहगी मिलती है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस पुराने रेट को रिवाईज किया जाए।

इसके साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मै कहना चाहता हूं कि पिछलली बार भारत सरकार ने फैसला लिया कि हरिजनों को ट्रकों के नै ालन परमिट्स दिय जाएंगे। इसके लिए पहले हरिजन कल्याण निगम हरिजनों को अपनी तरफ से 25 सीड मनी देती थी ओर उसके बाद बैकों से ट्रकों को परचेज के लिय लोन मिलता था लेकिन हरिजन कल्याण निगम अब सीड मनी का पैसा नही देती। और उसके बिना बैक भी लोन नही देतें। इसलिए जो हरिजन ट्रक खरीदना चाहेगा वह तभी खरीद सकेगा जब उसकों बैकों से लोन मिलेगा। जब तक हरिजन कल्याण निगम पैसा नही देगी तब तक बैकों से हरिजनां को पैसा नही मिलेगा। इसलिए पहले की तरु हरिजन कल्याण निगम को सीड मनी अपनी ओरसे हरिजनों को देनी चहिये। सरकार को इस तरफ खास तवज्जों देनी चाहिए।

इससे अगली बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार की हरिजनों के राईट्स को प्रोटैक्स करने की स्कीम है लेकिन वह स्कीम पूरी तरह से इम्पलीमैट हो तभी बात उचित है। डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ लाकूना सिलैक ान में है, यह ठीक नही है। उेस दूर किया जाना चाहिये। एस0 एस0 एस0 बोर्ड के अन्दर हरिजनों की रिक्रूटमैट के लिये जो फारमूला बनाया गया हैं उससे हरिजनों की परमो ान आगे के लिए ब्लौक हो जाती है। जैसे

100पोस्टे है उसमें यह हाता है कि हर पांचवी पोस्ट पर एक आदमी ि ाड्यूल्ड कास्ट का लिया जाएगा। फर्ज करें कि 100 आदमी सिलैक्ट करने है। इनमे कुल 20 पोस्टें रिजर्व होगी और 80 जनरल कैटैग्री काी होगी। इस हिसार से जिस हरिजन का नम्बर 81वां आता है या उसके बाद आता है, उसे आगे परमो ान के लिये बहुत नुक्सान हेात है। मेरे पास मिसाल है कि एक बार एस0 डी0 ओज0 की सिलैक ान हुई थी। उसमें जिस आदमी का नाम टेल पर था, वह फर्स्ट क्लास था तथा ि ाड्यूल्ड कास्ट था। वह तो आज भी वही का वही बैठा है लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग जिनका नाम उससे आगे था वे आज एक्सीएन बने बैठे है। उसकी परमो ान इस लिए नही हुइ क्यांकि उसका नाम टेल पर रखा गया था। इसलिए मेरी रिकवैस्ट है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और रोस्टर के अनुसार ही परमो ान दी जाए ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मै रोड्ज के लिये 107 करोड़ रूपये की रा ि ा रखी गयी है। और इस याजना में 1834 किलोंमीटर सड़कें बनायी जानी हैं इस वर्श के बजट में सड़कों के लिए 14.5 करोड़ रूप्या रखा गया है।, जिससे 247 किलों मीटर सड़के बनेगी, यह अच्दी बात है। कई जगहों पर सड़कों की डिमांड है। कई जगहों पर सिगल रोडज है जिसके कारण लोगों को गाडियों को कच्चे में उतारना पड़ता है। कुछ सड़कों की रिपोयर होनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि

मार्किट कमैटियों का 40 परसेन्ट पैसा सड़कों के ऊपर खर्च किया जाएगा। इसलिये मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि जो सड़के अधूरी है, जिन पर मिट्टी डली हुई है उनको सबसे पहले बनाया जाए क्योकि अगर उनको प्रायरिटी न दी गई तो बरसात के मौसम में वह सारी मिट्टी बह जाएगी और सरकार को काफी नुक्सान होगा। महमूदपुर गांव की दो–अढ़ाई किलोंमीटर सड़क का टुकडव है जाकि पानीपत से लिक होता है और इसी सड़क द्वारा गुरूकुल मं लड़किया पढ़ने भी जाती है। इसकेां भी प्रारिटी बेसिज पर पूरा किया जाए। छपरा गांव ` पास एक सड़क है जिसके न बनने पर डेढ़ किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है, इसकी ओर भी ध्यान दिया जाए। इसलिये मेरी रिकवैस्ट है जो इस ताह की छोटी छोटी सड़के है जो दो जिलों को मिलती है, जिन पर मिट्टी पड़ी हुई है, ऐसी सड़कों को फर्स्ट परैफरैन्स दी जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ मतै एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार ने फैसला किया है कि कुछ परचेज सैन्टर्ज बनेगे, कुछ नही मंडिया भी बनेगी जिससे फारमर्ज को अपनी जिन्स लेकर दूर दूर मंडियों मे ंनही जाना पड़ेगा। सरकार ने यह फैसला किय है कि ये परचेज सैन्टर्ज 10–10 किलोमीटर के फासले पर बनेगे। यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन कुछ परचेज सैन्टर्ज कई सालों से अधूरे पडत्रे हुए है। कई बार ऐसा देखेन में ाअया है कि जो पड़ोसी मंडियों के व्यापवरी होते है वे कोि ा ा करत है कि अफसरों से मिल मिला कर इस सीजन मे ंपरचेज

सैन्टर न बने ताकि आस पास काअनाज उनकी मंडियों में आ जाए। इस कारण से किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपना अनाज दूर की मंडियों में ले जाना पड़ताहै। इसलिये मेरी रिकवैस्ट है कि जो परचेज सैन्टर्ज अधूरे पडत्रे है उनको पहले पूरा किया जाए। इसी तरह से गोहाना एक बड़ा भाहर है, वहां पर नइ ग्रेन मार्किट अन्डर कंस्ट्रक ान है। यह स्कीम पहले बनी थी, प्लान मन्जूर हुआ था पता नही किस कारण से अब यह रद्द हो गयी हो सकता है कि इस के पीदे कोई पोलिटिकल कारण हो। यह बहुत जरूरी है इसलिये इसकों नये सिरे से बनाया जाए ओर जितनपरचेज सैन्टर्ज अधूरे पहड़े है उनको पूरा किया जाए। एक बार मुख्य मंत्री जी धड़वाल गांव में गए थे। वहां के लोगों को परचेज सैंटर बहुत दूर पड़ता है, इन्होनें वहां पर नजदीक परचेज सैंटर बनाने के लिए कहा थां मै चाहूंगा कि वह परचेज सैंटर जल्द बनाया जाए।

इसके बाद में हैल्थ के बारें में कहना चाहूंगा। हैल्थ इज वैल्थ। सरकार ने फैसला किया है कि अपने वाले सात मतें 150 सबसिडरी हैल्थ सैंटर, 31 प्राइमरी हैल्थ सैंटर और 10 कम्यूनिटी सैंटर खोले जाएंगे। मैने एक सवाल पर सप्लीमैटरी पूछते वक्त भी कहा था कि कि ऐसे ऐसे इलाके भी है जहां पर आस पास कोई पी0 एव0 सी0 भी नही है। वहां पर फ्लड आते है जिसकी वजह से बीमार आदमी भाहरों के हस्पतालों में भी नही जा सकते। ऐसे इलाकों में लोग बीमार भी ज्यादा होते है क्योंकि

फ्लड के पानी से बहुत सी बीमारियां फैल जाती है। इस लिये इसका फैसला पोलिटिकल लैवल पर नही होना चाहिए बल्कि जहां जरूरी हो वहां पर हैल्थ सैंटर खोलना चाहिए। मेरे एरिया में धनाना, झाकसी और गंगानी गांव है जिनकी आबादी 15–16 हजार के आस पास है। इनके अलावा दो तीन गांव और है उनकी भी आबादी काफी है। सरकारकी यह नीति है कि 30 हजार की आबादी के ऊपर एक डिसपैंसरी बनाएंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इन गांवों की तरफ भी ध्यान दिया जाए।

इसके बाद में भुगर मिल के बारें में कहना चाहूंगा। गोहाना में भुगर मिल के लाइसैंस के लिए दो साल से सैंट्रल गवर्नमैंट को लिखा हुआ है लकिन अभी तक लाइसैस नही मिला है। मेरा सुझाव है कि भूगर मिल बनाते समय जिले का क्राइटेरिया नही रखना चाहतए बल्कि जहां गत्रा ज्यादा पैदा हो वहां पर मिल खोलना चाहिए। मेरा निवेदन है कि गोहाना के मिल के लिए सरकार भारत सरकार से बात करें अभी पंजाब में तीन नए भुगर मिल खोलने के लिए लाइसैसे मिले है, क्या कारण है कि हम पीछे रहे जाए। मै मुख्य मत्री जी से निवेदन करूगा कि अगर वहां पर मिल चालू कर दिया जाए तो लोगों को हौसला मिलेगा और वे आगे के लिएज्यादा गत्रा बोने लगेगे। इस लिए सरकार को अपना केसू परसू करना चहिए। लासैस लेने में कोई खास दिक्कत नही आती। यह भी जरूरी नही है कि लाइसैस मिलते ही जमीन ऐक्वायर करनी होगी, जब उस एरिया में ज्यादा गत्रा पैदा होना

भाुरू हो जाए तब मिल की स्थापना कर लें। इन भाब्दों के सथ मै इस बजट की ताइद करतेहुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी): डिप्टी स्पीकर साहब, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री सागर राम गुप्ता जी ने जेा बजट पे ा किया है मै उसका स्वागत करत हूं। जैसे कि अभी एक साथी स्वास्थ्य के बारें में बोल रहे थेा इसके लिए इन्होने 12 करोड़ रूपए आने वाले साल के लिए रखे है। यह भी बताया गया कि 30 हजार की आबादी परएक प्राइमरी हैल्थ सैंटर खोलने की सरकार की नीति है इसके साथ साथ रूरल डिसपैसरीज ओर कम्यूनिटी सैंटर्ज भी खोल जाएंगे। यह बड़ी अच्छी स्कीम हैं जहां लोगों की सेहत का ध्यान रखा जात ाहै वहां प्रदे ा की तरक्की भी होती है। जिस प्रदे ा क लोगो की सेहत अच्छी होगी। वहां पर लोग मेहनत करके ज्यादा उपज कर सकते है। सरकार ने जहां नए सैटर्ज खोलने का प्रावधान किया है वहां मै पुराने हस्पतालों के बारें में भी कुछ कहना चाहूंगा। जो हस्पताल पहले से बने हुए है उनमें दवाईयों की बहुत कमी रहती हैं और गरीब आदमियों को थोड़ी थोड़ी दवाईयों की बहुत कमी रहती है। इसलिए मै अनुरोध करूंगा कि इन हस्पतों में दवाईयों के लिए और पैसे का प्रावधन करें ताकि गरीब आदमियों को वहां से मुक्त दवाइयां मिल सकें आपको मालूम है कि गरीब आदमी जिसका कोई साधन नही होता वह प्राइवेट डाक्टर के पास जा कर अपना इलाज नही करवासकता।

उसका ध्यान हमे ाा सरकारी हस्पताल की तरफ लगा रहात है। इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाए।

इसके साथ साथ जल सप्लाई के लिए और गन्दा पानी निकालने के लिए 26 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। यह बहुत अच्छी बात है। हरियाणा जा दिन प्रति दिन तरक्की कर रह है। उसकी वजह से हमाराखर्चा भी बढ़ रहा है। जैसे आंकड़े दिए गए है उनके मुताबिक हमारी आमदनी भी बढ़ रही है। वाटर सप्लाई के लिए हमारे वाटर वर्कस बने हुए हैं उनमें बिजली की कमी की वजह से काफी परे ाानी रहती हे। कई बार पानी राम के 12बजे आता है। और कइ बार सारा दिन पानी नही आता। बिजली न मिलने की वजह से इन वाटर वर्क्स का काई फायदा नही रहता क्योंकि लोगों को टाइम पर पानी नही मिलता। जो वल्डै बैक की स्कीम के तहत नए वाटर वर्क्स है जिनमें मेरा भाहर भी आता है उनके लिए जनरेटर या कोर्ठ और प्रबन्ध किया जाए ताकि सही टाईम पर लोगों का पानी मिल सके। पुराने वाटर वर्क्स से 30 गैलन प्रति दनि प्रति व्यक्ति पानी देने का प्रावधान हैं हांसी जैसा भाहर जहां 30—40 हजार की आबादी पहले थी वह अब डबूल हो गई है लकिन पानी की सप्लाई पुराने हिसारसे ही चल रही है। इसलिये वहां के वाटर वर्क्स की कैपसिटी बढ़ा कर लोगों को अधिक पानी दिया जाए। जितन भी पुरान वाटर वर्क्स हैं सब की कैपेसिटी बढ़ाई जाए और इस काम के लिए जितनी धन रा ि ा चवाहिए वह दी जासए। इसके साथ साथ भाहरों में जैसे सीवरेज

की स्कीम है उससे काफी उत्रति हो रही है। हर भाहर में सीवरेज सिस्टम होना जरूरी हैं भाहरों के साथ साथ देंहात में भी सीवरेज सिस्टम होना जरूरी हैं क्योंकि पहले जहां देहात के आस पास जंगल हुआ करता था जहां हमारी माताएं बहिने जंगल क लिए जाती लकिन आज वह जंगल साफ हो गए है और खेती बाड़ी देहातेां के कोने तक पहुंच चुकी है। इस वजह से हामरी मातओं और बहिनों को परे ाानी होती है। इसलिए देहात में भी सीवरेज सिस्टम हो होना जरूरी है ताकि औरते उसका इस्तेमाल अपने घरेां में ही कर सके और वर्तमान परे ाानी से उनको मुक्ति मिले। भाहरों मे ंभी बहुत जगह सीवरज की स्कीम पूरी नही है। जैसे हांसी है वहां पर यह स्कीम चली और उस पर 60 लाख रूपए खर्च आया लेकिन उसके बाद अभी काम होना बाकी रहता है। सो इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। मै चाहता हूं कि भाहरों में हर गली ओर हर मुहल्ले में सीवरेज की स्कीम बनाई जाए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके।

इसके साथ साथ वनों के बारें में भी बताया गया है। हरियाणा के किसी भी हिस्से में जब हम जाते है तो हमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। सड़कों पर ओर नहरो ंपर चारो ंतरफ हरियाली हैं यह हमारी बहुत अच्छी स्कीम चल रही है। कहावत भी है कि जहां हरियाली होती है वहा खु ाहाली होती है। आज हमारे यहां पंचायतों के पास काफी जमीने पड़ी है। ओर भी कई जगह बहुत जमीने पडत्री है ऐसी जमीनो ंपर भी वन

लगाए जाऐ। अगर पानी का साधन मुहैया किय जाए तो ऐसी बहुत सी जमीनों पर वन लगाए जा सकत हैं कुछ लोगों ने सरकार की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है, उनसे वह जमीन खाली करवा ली जाए और वहां पर वन लगाए जाएं इससे हमारे प्रदे ा में और भी हरियाली बढ़ेगी ओर सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी।

हमारे वित्त श्री सागर राम गुप्ता जी ने मुलाजिमों के बारें मे ंभ कहा है और उन्होने मुलाजिमों की जो मांगे थी उनको ंकाफी हद तक पूरा किया है क्योंकि इनका लेबर यूनियन से ताल्लुक रहा हैं जैसे डबल डियूटी के लिए स्पै ाल अलाउंस देने की स्कीम है, इस बारें में फोर्थ क्लास के मुलाजिमों की कई दिनो ंसे मांग थी, उन्होने उनकी इस मांग को पूरा किया है, उसके लिए मै उनका धन्यवाद करत हूं जो डबल डियूटी देने वाले फौर्थ क्लास के कर्मचारी है जैस माली कम चौकीदार, पीयन कम चौकीदार उनकों 30 रूपए स्पै ाल अलाउंस देने का प्रावधान किया हैं मै समझता हूं कि 30 रूप्ए थोड़े है इनकों बढ़ाया जाए क्योंकि एक आदमी दो आदमियों का काम करता हैं इसके साथ साथ फौर्थ क्लस के मुलाजिमेां की और भी मांगे है मेरे ख्याल में वे मांगे गुप्ता जी के पास पहुंच गई होगी लकिन एक बात मै कहना चाहूंगा कि फौर्थ क्लास के कुछ कर्मचारी पिछले 10–12 साल से सर्विस में है लेकिन वे रैगुलर नही हुए है, उनकों रैगलर नही हुए है, उनको रैगुलर किया जाए। इसके अलावा फौर्थ क्लास के कर्मचारियों की कुछ छोटी मोटी डिमाडज को पूरा करें ताकि वे

लोग बहुत है जैसे साईकिल अलाउंस,वर्दी अलाउंस, इस प्रकार की मांगे भी पूरी कर दी जाएं। अगर इस प्रकार की छोटी छोटी मांगे पूरी कर दीजाती है तो वे लोग सरकार की जय जय कार का नारा लगाएंगे। उनको इस तरह की छोटी छोटी डिमाड्ज को पूरा करें ताकि वे लोग बहुत खु ाी से अपने काम को करे। क्योंकि यदि नीचे से काम अच्छा चलता है तो ऊपर तक अच्छा चलता है। मुलाजिम भी खु ा रहेगे और कम भी अच्छा करेगे। मै एक बात यह भी कहनाचाहूंगा कि हांसी का जो टैक्सटाइल मिल है उसके मजदूरों ने भी कुछ मांगे की है, उनकों भी दूसरे फौर्थ क्लास के मुलाजिमों की मांगों के साथ भाामिल कर लिया जाए और वित्त मंत्री जी उनका निरीक्षण करके लेबर एक्ट के तह उनकी जो मांगे बनती है उनकों पूरा करें उन मजदूरों ने हमं यकीन दिलाया है कि वह मिल पहले बन्दर हो चुकी थी, उसको अब चालू क रहे है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनकी जायज मांगों को पूरा किय जाए ताकि वे लोग हौसले से काम कर सके। इसके साथ साथ मै। यह भी कहना चाहूंगा कि गुप्ता जी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वासयि देखभाल तथा चिक्त्सिा भत्ता स्कीम लागू की है, यह बहुत अच्छी काम किया हैं उन्होने अपनी बजट स्पीच में बताया है कि कर्मचारियों की तन्ख्वाह के साथ 100 रूपया का सालाना स्वास्थ्य देखभाल तथा चिकित्सा भत्ता जोड़ दिया गया है। मै इस बारें में एक बात कहना चाहूंगा कि इससे मुलाजिमों में एक निरा ाा पैदा हुई हैं वैसे तो यह अच्छा हुआहै कि उनकी तनख्वाह के साथ जोड़ दिया गया है लेकिन मै कहना

चाहूंगा कि सरकार इसमें ऐसा करे कि जिस किसी सरकारी कर्मचारी को जो दवाई चाहिए वह डज्ञक्टर हस्पताल से दिलवाए चाहे वह दवाई हस्पताल को खरीदनी पड़े लेकिन सरकारी मुलाजिम को हस्पताल से दवाई उपलब्ध करवाई जाए। ऐसा करने से छोटे मुलाजिमों कोई दिक्कत का सामना नही करना पडेगा। जो 100 रूपए फिक्स किए गए है यह बहुत कम है क्योंकि 8 रूपए महीने के हिसाब से बनते है, 8 रूपए में तो कान की भी दवाई नही आती है। मै सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो छोटै मुलाजिम है उनके परिवारों में जिस किसी को भी कोई रोग लगता है उसके लिए हस्पताल की तरफ से दवाई का प्रबन्ध किया जाना चाहिए उसके लिए 100 रूपए की दवाई आती है चाहे 200 रूपए की दवई आती है औरचहो 1000 रूपए की दवाई आती है उसकेां हस्पताल से दवाई उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि वे अपना इलाज सही ढंग से करवाकसे। जो 100 रूपए मैडीकल भत्ता मुलाजिमों की तनख्वाह में जोड़ा गया है उससे एक बात तो अच्दी होगी कि जो लोग इसमें गलत धंधा करते थे वह खत्म हो जाएगा लेकिन मै यह कहता हूं कि सरकार मुलाजिमों को दवाई हस्पताल से उपलब्ध कराने का प्रबन्ध जरूर करें, उनको हस्तपाल से दवाई जरूरी मिलनी चाहिए। यदि उनकों हस्पताल से दवाई उपलब्ध नही कराइ जाती है तो मैडीकल भत्ते को बढ़ाया जाए ताकि जो छोटे मुलाजिम है वे अपने बच्चों का और अपना इलाज आसानी से करा सकै।

इसके अलावा मै कहना चाहूंगा कि ि ाक्षा के बारें में मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने काफी चर्चा की हैं बहिन जी ने बोलते हुए यह कहा कि बच्चो को नैतिक ि ाक्षा देना बहुत जरूरी हैं प्राइवेट कालेजिज या स्कूलों के टीचर्ज ने हरियाणा सरकार के सामने अपनी यह मांग रखी थी कि उनको बैक की मारफत तनख्वाह मिलनी चाहिए। वह सरकार ने मानी है, उसके लिए मै सरकार को बधाई देता हूं। इसके साथ साथ मै एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि उनकी मांग के साथ साथ गवर्नमैट स्कूलों और कालेजों के टीचर्ज की भी जो मांगे है, उनका निरीक्षण करके जा जायज मांगे है, उनकें सरकार पूरा करें ताकि जो टीचर हमारे बच्चो को पढ़ाते है ओर एक अच्छा इन्सान बनाते है वह खु ा हो ओर वे बच्चों को अच्छी तरह से ि ाक्षा दें जब तक टीचर्ज की खुद की डिमांड्ज पूरी नही पूरी नही होगी तब तक वे बच्चों को अच्छी तरह से नही पढ़ाएगे। वे बच्चों को टयू ान पर पढ़ाने के लिए रख लेते है क्योंकि वे समझते है कि उनका वेतन कम है। टयू ान के लालच में वे बच्चों को स्कूल में अच्छी तरह से नही पढ़ाते है। (घंटी) डिप्टी स्पीहकर साहब, अपने घंटी जल्दी ही बजा दी है। मै अपने हल्के के बारें मं कुछ बातें कर अपना स्थान लूंगा। मै सरकारसे अनुरोध करूंगा कि गवर्नमैंट टीचर्ज की डिमाड्ज के बोरं में हामरे मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी आपस में बैठ कर सोच विचार कर लें ओर उनकी जाज मांगों को पूरा करे। एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जैसे क्वै चंज आवर में दस जमा दो प्रणाली के बोरं में जिक्र आया था

और उसको ंलागू भी किया गया है और आगे भी कर रहे है। इसी तरह से नैतिक ि ाक्षा जब तक हमारे बच्चों को नही मिलेगी तब तक कोई सुधार नही हो सकता। सरदार भगत सिंह ने लाहौर मे ंनैतिक ि ाक्षा प्राप्त की थी और वह नैतिक ि ाक्षा का ही परिणाम था जो उन्होने दे ज्ञ की आजादी के लिए अपनस सब कुछ कुर्बान कर दिया। मै कहना चाहता हूं कि जिस दे ा या प्रदे ज्ञ में बच्चों को नैतिक ि ाक्षा मिलेगी वह दे ा या प्रदे ा जरूर तरक्की करेगौ। जैसे हमारे पड़ोसी प्रदे ा पंजाब में लोग उग्रवाद के रास्ते पर चल रहे और आजादी का नाम खत्म करने की कोि ा ा कर रहे है। वह इसलिए कर रहे है क्योंकि उनमें नैतिक ि ाक्षा नही है। यदि उनमे ंनैतिक ि ाक्षा हाती तो वे इस किस्म के काम नही करते तो आजकल पांजब मेंं कर रहे है। हमें आजादी कितनी कुर्बाथ्नयों से मिल है, बहुत लोग भाहीद हुए है तकि कही जा कर हमें आजादी मिल है।

इसके अलावा मै हांसी के बारें में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हांसी के अन्दर मजदूरों की अलग कालोनी होनी चाहिए। वहां पर लगभग 1200 मजदूर काम करते है। उन मजदूरों के लिए मिल मालिकों की तरफ से भी कोई मकान नही बनाए हुए है। वे सारे मजदूर प्राइवेट मकानों में किराए पर बहुत दूर दूर तक रहते है। उनकों अपने काम पर आपने में बहुत दिक्कत हाती है। मै सरकार से अनुरोध करूंगा कि मिल के एरिया में ही कालोनी बना दी जाए ताकि उनकों मकानों का किराया भी न देना पड़े औ

अपने काम पर वे समय पर पहुंच सके।। पहले भी इस बारें में डिमाड रखी थी कि हांसी को काफी लम्बा चौडा एरिया है। जिसमें एक ही टैक्सटाइल मिल है। इसलिए वहां पर फलोर मिल भी लगाया जाए। हांसी के एरिया में गेहूं की पैदावार बहुत होती है। इसलिए वहां पर एक फलोर मिल जरूरी लगाया जासं मै यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हांसी में फलोर मिल बहुत अच्छा चलेगा,, उसमें घाटे की बात नही रहेगी।

इसके अलावा मै यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के हांसी में कुछ सड़कों को बनाया जाना बहुत ही जरूरी है। मैने उन सड़कों का नाम राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर बोलते हुए बताया था। उन सड़कों को जल्दी से जल्दी कम्पलीट करवाया जाए। इसी तरह से मै एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हांसी में हाई स्कूल है लेकिन कालेज नही है। सारी हांसी तहसील में ही केई कालज नही है। कालेज के लिए जमीन भी सी0एम0 साहब न दिलवाई थी। उस जमीन का मालिक पहले उस जमीन का कब्जा नही दे रहा था लेकिन अब अदालत ने उस जमीन के बोरं में फैसला दे दिया है। उस जमीन के मालिक के साथ समझौता हो गया हैं सरकार को उस जमीन का कब्जा भी मिल गया है। इसलिए मै सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस कालेज को बनाने का काम जल्दी भ्रारू करवाएं ताकि वहां के बच्चों को ि ाक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इन्हों भाब्दों के साथ मै इस बजट का स्वागत करते हुए हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी सुबे सिंह पूनिया (उचाना कलां): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री श्री सागर राम गुप्ता जी ने कल 25 तारीख को जो बजट सदन में पे ा किया है मै उसे संबंध में चली चर्चा में अपने आपकों भाामिल करनाचाहता हूं। जे बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा बिजली और सिंचाई पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। जो खर्चे बिजली ओर सिंचाई के लिए रखे गऐ है यह इस बात का प्रतीक है। कि हरियाणा निरन्तर विकास की तरफ बढ रहा है। आज विकास के लिए कृशि में नए उपकरणों की जरूरत है। या ट्रैक्टरों की जरूरत है इनकेां बनाने के लिए जो उद्योग लगे है ये इसबात का प्रतीक है कि हरियाणा वाकई विकास की तरफ बढ़ रहा है उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी जरूरत आज प्रदे ज्ञ में ही नही बल्कि पूरी दुनिया में उर्जा के साधनों की है। बिजली पर जो बजट रखा गया है वह पिछले साल से तकरीबन 40 करोड रूपये अधिक रखा हैं आज स्थिति यह है कि हरियाणा के हर गांव में बिजली की लाईने बिछी हुई है लेकिन बार बार ि ाकायत भी आम आती है कि ट्रांसफार्मर बहुत अधिक सड़ रह`हैं मै आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह केकन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करें कि हरियाणा राज्य में एक आधुनिक टैक्नोलोजी के ट्रांसफार्मर का कारखाना लगाये ताकि आगे आने वाले समय में हरियाणा के लोगों की बिजली की मांग को पूरा किया जा सके ओर हरियाणा में नए उद्योग लग सके। ऐसा होने पर हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के सपनों के अनुरूप हम 21वी

सदी के आधुनिक भारत की मिसाल को कायम कर सकेगे। यह तभीसंभव है हो सकता है जब हम उर्जा के साधन अधिम उत्पन्न कर सकेगे और लोगों की बिजली की मांग की पूर्ति कर सकेगे। दूसरी बात मै यह कहना चाहूंगा कि यहां पर केन्द्रयी सरकार को एक परमाणु यूनिट लगाना चाहिए। इस परमाणु बिजली यन्त्र लगाने के प्रयास सरकार को जारी रखने चाहिए ताकि केन्द्रीय सरकार हमारी बात को ध्यान में रखकर उचित पग उठा सके।

दूसरी वि ोश बात इस बजट में सिंचाई के बारें में रखी गई है। सिंचाई के लिए भी सरकार ने पिछले साल की बजाये इस साल 27 करोड़ रूपये अधिक रखे है। सिचाई के अधिक साधनों से ही प्रदे ा की तरक्की को चार चान्द लगा सकते है क्येंकि हरियाणा मूलतः गांवों का प्रदे ा है। गांवों के अधिकतर लोगों का जा रोजगार है वह कृशि से जुड़ा है। कृशि के लिए सिचाई के साधनो का होना बहुत जरूरी हैं इस बजट के अन्दर 28 करोड़ रूपये नहरेां को पक्का करने के लिए रखे गए है। इन 28 करोड़ रूपयों से छोटे छोटे जो खाल ओर माईनर है उनको ंभी पक्का किया जाना हैं इस बोरं में मै सरकार का ध्यान इस बात की तरफ आकर्शित करना चाहूंगा कि जो बडी बडी नहरें है जैसे सिरसा नरवाना ब्राच है उनकों पक्का किय जाये न कि छोटे छोटे नालों और माइनरों को पक्का किया जाये। बड़ी नहरों में ज्यादा पानी की सीपेज होती ओर इन्ही बड़ी नहरों में छोटी छोटी माईनरों की अपेक्षा पानी अधिक खरबा होता हैं यदि बड़ी

नहरों में छोटी छोटी माईनरों की अपेक्षा पानी अधिक खरबा होता है। यदि बड़ी नहरों का जैसे सिरसा–नरवाना या ओर दूसरी है उनकों पक्का कर दिया जाता है तो उससे दो–अढाई लाख हैक्टेयर जमीन की अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे उस इलाकें में हम 4–54 गुणा ज्यादा जमीन की सिंचाई कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मै कृशि के बारें में कहना चाहूंगा। कृशि हरियाणा प्रदे ा की रीढ़ की हड्डी है। आज स्वयं भी किसान है ओर इस सदन के अधिका ा सदस्य भी किसान है। आपकों अच्छी तरह मालूम हे कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ कृशि की जोते बहुत छोटी छोटी होती जा रही हैं आज के दिन आध–आध एकड़ के किसान रह गए है। यदि आज के किसान का कोई युवा पुत्र कृशि में रूचि रखता है और वह तरक्की करना चाहता है तो उसकों वि ोश सुविधाएं सरकार की तरफ से नही मिल रही। आज जमीन का भाव 30 हजार रूपये एकड़ का है। यदि कोई जमीन के कर्जा लेना चाहे तो उसे सिर्फ 6 हजार रूपए ही मिल सकते हैं मै बार बार सदन से प्रार्थना कर चुक हूं कि कृशि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो किसानों को कृशि के उपकरण मिलेगे, उन्हे लोन और सबसिडी वगैरा भी मिल सकेगी। इसे अलावा कृशि से संबधित जितने भी विशय है उन सबकों औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिया जाये। जैसे मछली पालने का काम है, मुर्गी व सुअर आदि पालेन

को काम है या घोड़े पालने का काम हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सब उद्योग के रूप में होने चाहिए। ऐसा होने पर किसान के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होगा। उसकी आमदनी में भी बढ़ौतरी हो सकेगी ओर प्रदे ा में भी खु ाहाल होगी। इतनाप ही नही इससे प्रदे ा को अधिक राजस्व भी प्राप्त होगा। इसलिए इस बारें में मेरा सरकार से पुनः अनुरोध है कि कृशि से जितने भी विशय जुडे हुए है। उन सबाके उद्योग का दर्जा देनपा चाहिए। इसके साथ साथ मै एक और अर्ज करना चाहूंगा कि प ुधन को बढ़ावा देने के लिए प्रद र्ानी आदि लगाइ जानी चाहिए। हिसार के अन्दर एक लाईव स्टार फार्म है। वहां पर प्रतिवर्श प्रद र्ानी लगती है। सरकार द्वारा अच्छे प्रयास किए जा रहे है। इस काम के लिए मै सरकार को बधाई देना चाहता हूं। प ुधन को बढ़ावा देने के बारें में मेरा सरकार से फिर अनुरोध है कि वह प्रतिवर्श प ुओं की प्रद र्ानी आदि लगाये ताकि लोग यहां पर अधिक से अधिक प ुधन का लाभ उठा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मै सड़कों के बारें में कहना चाहूंगा। यहां की सड़कों को बोरं कहा गया है कि बहुत अच्छी हैं सरकार ने इस काम के लिए इस बजट में 14 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है और 247 किलोंमीटर लम्बाई की नहई सड़के अगले साल में बनाई जाएंगी। मै इस बोरं में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मेरे हल्के में वे दूसरे हल्कों में जो पुरानी सड़के है पहले उनकी रिपेयर होनी चाहिए। नई सड़कों अधिक नही बनाई

जानी चाहिएं जो सड़कों बची में अधूरी रह गई है या जिनके रिपेयर नही हो रही है, उनकी तरफ सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए। मेरे हल्के में भी कुछ ऐसी सड़के है जिन पर अर्थ वर्क ही हुआ है या थोड़ा या और अधिक कमा हुआ हैं इसलिए इस बारें मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन सड़कों पर काम चल रहा है और जिनकी रिपेयर नही हो रही, उनको पहले पूरा करने के प्रयास किये जाने चाहिएं उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाशण में भी कहा गयाहै कि गांवों के अन्दर लाल डैरे में जो स्कूल, मन्दिर वगैरा है उनकों सड़कों से जोड़ा जायेगा। इसके साथ–साथ यह भी कहा गया है कि हरिजन बस्तियां जो अभी तक पक्की सड़कों के साथ जोड़ी नही गई है, उनकों भी जल्दी से जल्दी पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। इस बों में मै इतना ही कहना चाहता हं कि इन सभी सड़कों को जल्दी से जल्दी बनाया जाए।

उपाध्यक्ष माहेदय, सड़क के साथ परिवहन की बात भी जुडी हुइ हैं परिवहन के लिए सरकार ने पिछले साल 30 करोड रूपये रखे थे जबकि इस साल 28 करोड रूपये रखे है। सरकार ने इसा साल परिवहन के लिए पिछले साल की बजाये 2 करोड़ रूपये कम रखे हैं यह भी कहा गया है कि सरकार इस वर्श 150 नई बसें खरीदेगी। आज हरियाणा क अन्दर सबसे गम्भीर समस्या बेरोजगारी की हैं। इस बारें में मेरा सरकार को सुझाव है कि हरियाणा के अन्दर छोटे छोटे जो परिवहन के साधन है जैसे मिनी

बस या मैटाडोर है लोकल रूट पर इनकों चलाने के लाईसैस पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को दिए जाने चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो उससे परिवहन की समस्या भी काफी हद तक दूर हो सकती है। और लोगों को रेाजगार भी मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, ि ाक्षा का होना बहुत महत्वपूर्ण हैं इसकी ओर सकरार ने काफी ध्यान दिया है। मेरे क्षेत्र के अन्दर काफी हाई स्कूल्ज है और तकरीबन 6 हजार लड़के उचाना क्षेत्र से मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे है लेकिन हमारे इलाके में उच्च ि ाक्षा का थोडा अभाव हैं मैने पहले भी मांग की हैं कि उचाना के अन्दर एक कालेज खोला जाए जिससे साईस कौमर्स पढाने का भी प्रावधान हो ताकि इस इलाके के लोग उच्च ि ाक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ सके और अपना जीवन स्तर सुधार सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मै सरकार को बधाई भी देनाचाहता हूं क्योंकि इसने प्राइवेट कालेजिज के प्राध्यापकों को बैक से वेतन देने का प्रावधान किया हैं

स्वास्थ्य के बोरं में भी बजट में जिक्र आयाहै। 31 नई प्राईमरी स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे ओर 150 नए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल जाएंगे। 30 हजार की आबादी के ऊपर एक प्राईमरी स्वास्थ्य केन्द्र होगा लेकिन मै सरकार से गुजारि ा करूंगा कि उचाना कस्बे के अन्दर जहां ब्लौक लैवल का हैडक्वार्टर है, सब तहसील है एक मंडी है वहां स्वास्थ्य केन्द्र नही हैं पता नही क्यो? मै सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक पी0 एच0 सी0

ओर दूर दराज के गांवों के अन्दर दो उप–स्वास्थ्य केन्द्र खोल जाए। जहां तक इस दिक्कत का संबंध है कि देहात में डाक्टर्ज नही ठहरते, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि जो डाक्टर्ज देहात में डियूटी किए जाए उन्हें वि ोश ग्रामीण भत्ता दिया जाना चाहिए ताकि वे वहां पर दिल लगा कर सेवा कर सकें और भाहरों की तरफ न भागे।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के साथ ही जन–स्वास्थ्य की बात भी कही है क्योंकि आम नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है। बजट में कहा गया है कि आगमी वर्श में 310 और गांवों को पानी की सुविधा प्रदान की जाएगी। जन स्वास्थ्य की जो पुरानी स्कीमें है वे चार, पांच ओर दस गांव के समूह के लिए बनाइ गई थी लेकिन जो स्कील दस साल पहले लागू हुई थी आज उन पर लोड बढ़ गया है क्येांकि आबादी काफी बढी हैं वे स्कीमें अब केवल एक दो गांवों को पूरा पानी सप्लाई कर पाती है और बाकी गांवों को पानी नही दे पाती। ऐसी स्कीमों को पुनरीक्षण किय जाए। जिन गांवों में पानी नही पहुचता है उने लिए अलग से स्कीमें बनाई जाएं ताकि उन्हें भी स्वच्छ पानी मिल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात के लिए भी मै सरकार को मुबारिकबाद देना चाहूंगा। सरकार ने ऐलान किया है कि सुलक्षणा स्कीम के अन्तर्गत जो गांव तरक्की के रास्ते पर होगे,

जहां हर तरह की खु ाहाली होगी उनकों ईनाम दिया जाएगा। मेरा अनुरोध है कि इस स्कीम को और बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, भाहरी विकास के बारें में मै निवेदन करना चाहूंगा कि जिन म्यूनिसिपैलेटीज में म्यूनिसिपल कमेटीज या सरकार ने नागरिकों को या दुकानदारों को आवास के लिए या बिजनैस के लिए लीज पर जगह दी है और जिस पर उन्होने भवन या दुकान का निर्माण कर लिया है वह उनहें ही दे दी जानी चाहिए क्योंकि इस वक्त जो लीज मनी मिल रहा है। उससे ज्यादा रा ि ा हाउस टैक्स के रूप में मिल जाएगी। दुकानदार ओर दूसरे लोग उन जगहो ंको लेने के लिए तैयार है। ऐसा करने से सरार को बहुत ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा, लोगों की द ाा सुधार होगा ओर भाहरों के विकास में भी बहुत ज्यादा मदद मिल सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को मै एक विकास ील ओर आधुनिक बजट कहना चाहूंगा क्योंकि इससे हम हरियाणा को विकास और आधुनिकता की तरफ ले जाने वाले होगे। हमारेयुवा प्रधान मंत्री जी का सपना है कि दे ा को 21वी सदी में ले जाया जाए ओर भारत एक आधुनिक भारत बने। अगर हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना करे कि इसके लिए हरियाणा प्रदे ा को टारगैट मान लिया जाए तो आने वाले पांच साल के अन्दर हरियाणा प्रदे ा एक खु ाहाल प्रदे ा साबित हो सकता है और यह एक मिसाल होगी पूरी दुनिया के लिए कि हरियाणा एक आधुनिक प्रदे ा है। इन भाब्दों के साथ मै इस बजट की सराहना

करते हुए, वित्त मंत्री और सरकार को बधाई देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी): आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, मुझ समय देने के लिए आपका हादिक धन्यवाद। श्री सागर राम, वित्त मंत्री, हरियाणा के भाशण का, जो उन्होने हरियाणा विधान सभा में वर्श 1986–87 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए, 25 फरवरी को पे ा किय, मै समर्थन करता हूं और उन्हें मुबारिकबाददेता हूं कि उन्होने कोई नया टैक्स नही लगाया। यह एक अच्छी बात है। डिप्टी स्पीकर साहब, इनकों बजट स्पीच में पंजाब समझौते का भी जिक्र आया है। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री और संत लौगावाल के दरम्यान एक समझौता हुआ। इसमें कोई भाक नही कि भाांति के लिए वह समझौता हुआ था लेकिन भाांति बराबर के प्रदे ा में तो नही रह सकी परन्तु हमार प्रदे ा में भाांति है। इसके लिए हमारी सरकार और चीफ मिनिस्टर साहब बधाई के पात्र है। आज हरियाणा में हर किस्म का अमन और भाांति है। यहां ला एंड आर्डर की हालत बहुत अच्छी है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने टैक्स में कुछ रियासते भी दी है। यह भी बहुत अच्छी बात है। दाल चने पर बिक्री कर की दर 4 परसैट से घटा कर 4 परसैट की गई है।

इस बार मौसम ठीक नही था, विपरीत था लेकिन फिर भी हमने उत्पादन में काफी तरक्की की है। उमम्दी है कि आयंदा

भी हमारे किसान भाई और उद्योगपति भाई इस तरह की तरक्की कीह तरफ कदम बढ़ाते रहेगे। चालू कीमतों के आधार पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय 3296 रूपए के स्तर तक पहुंच गई है। यह बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में इस समय हम भारत में नम्बर एक पर हैं जो खर्चे के अनुमान है उनके अनुसार सातवी योजना का खर्चे 2900 करोड़ रूपए रखा गया है। इसमें से 1000 करोड़ रूपया बिजली के लिए, 585 करोड़ सिंचाइ के लिए और 200 करोड़ रूपया ट्रांसपोर्ट के लिए रख गया है। सामाजिक सेवाओं के लिए 555 करोड़ रूपया रख ागया हैं यह भी बहुत अच्दी बात हैं लेकिन एक बात मै सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। भाहरी विकास के बारें में मेरे ख्याल में कोई विचार नही किया गया। हरियाणा में कोई 85 म्यूनिसिपल कमेटीज है और दो चार को छोडकर तकरीबन सभी घाटे वाली है। वहां विकास का काम बगैर सरकार की मदद के हो नही सकता। मै तो समझता था कि कम से कम 30—40 करोड़ रूपया इनकों दिया जाता ताकि भाहरों में कोई विकास का काम हो सकता। इस समय 30 परसैंट लोग भाहरी है और 70 परसैट लोग देहाती है लेकिन टैक्स का 70 परसैंट भाहर वाले देते है। इस लिएउनका हक जा उनको मिलना चाहिए वह मै समझता हूं नही मिल रहा है।

ला एंड आर्डर की स्थिति जैसा मैने पहले जिक्र किया हमारे प्रदे ा में बहुत अच्छी है। जहां कही भी कोई गलत बात होती है वहां तुरन्त मुलजिम पकड़े जाते है। यह खु ी की बात

है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौधरी इन्द्र सिंह नैन पदासीन हुए) पंजाब के एकोर्ड के मुताबिक एस0 वाई0 एल0 15 अगस्त, 1986 तक मुकम्मल हेनी चाहिए थी लेकिन मुकम्मल होती नजर नही आती। अभी तक वह भाुरू भी नही हुई है। हमारे आई0 पी0 एम0 साहब ने कहा है कि वहां पर भाायद एक परसैट लाइनिग हुई है। एस0 वाई0 एल0 हमारी सब से बड़ी जरूरत है। जब तक एस0 वाई0एल0 से हरियाणा की प्यासी धरती को पानी नही मिलता तब तक काम नही चलेगा।

हरियाणा में बिजली की कमी को पूरा करने की पूरी कोि ा ा की जा रही है। अच्छी बात है लेकिन अम्बाला तहसील के लिए बिजली का अलग से कोई प्रोग्राम नही है। अम्बाला मे ंसात हजार छोटे यूनिट बिजली की कमी की वजह से भारी नुक्सान उठा रहे है। उधर कोई ध्यान नही दिया गया है। आप जानते है कि हरियाणा की टोटल एक्सपोर्ट का वन थर्ड अम्बाला से होता है।

हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रदे ा है। हमारे यहां कृशि में काफी पैदावार बढ़ी है। और आगे बढ़ने की भी आ ाा है। सरकार ने जहां जमीदारों के लिए इतना पैसा खर्च किया है वह बधाई की पात्र है और हमारे जमीदार भी बधाई के पात्र है जिन्होने इतनी अच्दी तरह से काम किया है।

चेयरमैन साहब, प ा पालन की सुविधाओं की बढ़ाने के लिए वर्श 1986–87 में चालीस नयी प ा चिकित्सा डिस्पैसरिया खोली जा रही है। पांच हजार परिवारों को मुर्गीपालन, सुअरपालन, भेड ओर संकर–बछड़ा प्रजनन के लिए पैसा दिया जायेगा। जिससे आम लोगों को काफी लाभ होगा। चेयरमैन साहब सरकार ने पहले भी 1502 डिस्पैसरिया खोली हुई है और अम्बाला कैन्ट में सिर्फ प ा चिकित्सा की दो डिस्पैसरियां है। हरियाण सरकार चालीस नयी प ा चिकित्सा डिस्पैसरिया खोलने जा रही है। हमारे यहां अम्बाला छावनी में कम से कम एक डिस्पैसरी तो जरूर खोली जानी चाहिए। हमारे हिस्से में चालीस में से एक डिस्पैसरी तो आनी चाहिए।

चेयरमैन साहब, ग्रामीण उद्योगीकरण स्कीम के तह वर्श 1986–87 के दौरान चार हजार से अधिक यूनिट खोले जायेगे जिन में 12 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यह बहुत अच्छी बात है।

हरियाणा रोडवेज चलने में बहुत अच्छी है। हरियाणा रोडवेज तकरीबन सभी प्रदे ाों से अच्छी हैं हिसार में बस अड्डे के भवन को प्रथम पुरस्कार मिला हैं हमारी बसे भी अच्छी है। इनका सारे भारत मे ंनाम हैं हरियाणा की बस जब रोड पर होती है तो पहले हरियाणा रोडवेज की गस में ही लोग बैठना पसन्द करते हे बाद मै किसी ओर बस में। चेयरमैन साहब, अम्बाला छावनी का बस स्टैन्उ बहुत पहले का बना हुआ हैं जब हरियाणा

पंजाब एक थे। यह बस स्टैन्ड हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में सबसे पहले बना था। अब पांच गुणा आबादी बढ गई है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि नए बस अड्उे को अगले साल पूरा करने की कोि ा ा करें।

चेयरमैन साहब, अब मै तालीम के बारें में अर्ज करना चाहता हूं। तालीम पर अब भी अंग्रेजो का साया है। इस साये को हटाया जाना चाहिए जो अंग्रेजों के वक्त का है। अब भी वही ढांचा चल रहा है, इसे हटाया जाना चाहिए। अब तो आई0टी0आई0 और पोलिटैक्निक की ओर ध्यान दिया जाये। अगर बाबू बढ़ते है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। अगर आई0टी0आई और पोलिटैक्निक बढ़ते है तो दे ा की प्रगति होती है, बेरोजगारी खत्म होती है। आज के जमाने में एक लड़की पढ़ती है तो खानदार पढ़ता है। और लड़का पढ़ता है तो एक लड़का पढ़ता है। लड़कियों की ि ाक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अगले साल केवल सौ स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है। दूसरे प्रौढ़ अनपढ़ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए 1986–87 के दौरान 100 प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें मिडल स्कूल बनाने का भी प्रस्ताव है। इस बारें में मेरा निवेदन है कि अम्बाला छावनी में कोई लड़कियों केा स्कूल नही हैं इसलिए वहां पर लड़कियों को स्कूल खोला जाना चाहिए। दूसरे यह भी खु ाी की बात है कि 1.4.1986 से प्राइवेट कालेजों के प्रौफेसरों की तन्खाह की अदायगी बजरिए चैक बैकों से दी जायेगी सरकार ने यह अच्छी नीति

अपनायी है। उनकी बहुत मुद्दत से यह मांग थी। यह मांग पूरी हो गयी है, बड़ी अच्छी बात है।

चैयरमैन साहब, जैसे गांवों में पीने के पानी की समस्रूा है इसी तरह से भाहरेां में भी हैं जिन गांवों में पानी की कमी है। है उन्हें समस्रूाग्रसत गांव कहा जाता है। इसी तहर से जिन भाहरेां मे ंपानी की कमी है। उनहें भी समस्याग्रस्त सिटी कराकर दिया जाना चाहिए औरवहां पर पनी का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी स्कीम को पचास परसैन्अ पूरा कर दिया जाता हैं लेकन उससे अगले साल पैसा नही दिया जाता है जिससे वह सिस्टम टूट जाता है। अगर पले साल किसी स्कीम के लिए 35 लाख रूपया दिया है तो अगले साल पांच लाख तो दिया जानाचाहिए ताकि वह स्कीम चालू रहे।

इसके अलावा मै हस्तपालों के विशय में भी अर्ज करना चाहता हूं जिस प्रकार गांवों में तीस हजार की आबदी पर प्राइमरी हैल्थ सैंटर का नार्म फिक्स है इसी प्रकार भाहरों में भी नार्म फिक्स होना चाहिए। अम्बाला छावनी की डेढ लाख की आबादी है लेकिन वहां पर पचास बैड का हस्पताल ै। इसलिए भाहरों में भी आबादी के लिहाज से नार्म फिक्स होना चाहिए।

चेयरमैन साहब, राज्य सरार ने स्वतन्त्रता सेनानियों और भूतपूर्व सैनिाकों के परिवारों के लिए भी कुछ किया है। सरकार ने

उनके लिए जो कुछ भी किया है वह बधाई की पात्र है बहुत ही अच्छा काम किया है।

जहां तक बीस सूत्री कार्यक्रम का संबंध है उस बारें में हामरे नौजवान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने जो रास्ता दिखाया है। वह दे ा की तरक्की के लिए सब से अच्दा रास्ता है। इस प्रोग्राम से बेरोजगारी कम होगी ओर इसकी तरफ जितनी ज्यादा तवज्जों देगे उतना ही अधिक लाभ होगा।

मार्किट कमेटियों के बारें जो फैसला हुआ है कि उनकी आमदीन का चालीस परसैन्ट पैसा पी0 डब्लयू0 डी0 को दे कर सड़कों की मुरम्मत करायी जायेगी। म्यूनिस्पिल कमेटी की आमदन कम होती थी और खर्चो ज्यादा होता था लेकिन मार्किट कमेटी में खर्चा कम होता था और आमदन ज्यादा होती थी। इसलिए अब मार्किट कमेटी इन सड़कों के बनाने में मदद कर देगी तो सड़के सही तरह से बन सकेगी। यह अच्छी रवायत डाली हैं

चेयरमैन साहब, गुप्ता जी व्यापरी घर से है। वे व्यापारियों की तफलीफों को समझते है। लेकिन बराबर के सूबे मेंसेल्ज टैक्स कम है ओर हमारे यहा ज्याद हैं जिना सेल्ज टैक्स कम होगा उतनी ही ज्यादा आमदनी होगी। दिल्ली में 6 परसैट है, पंजाब में 7 परसैट है ओर हमारे यहां 8 परसैट है। बल्कि हमारे यहा तो 12 परसैट हो जाता है। आठ परसैट तो हमारा और 4 परसैट सेन्ट्रल टैक्स है। चण्डीगढ़ में भी सात परसैट है। जितना

टैक्स हमारे यहां है उतना कही नही है। अगर कोई आदमी सेल्ज टैक्स की चोरी करना चाहता है तो वह कार या ट्रक में माल राजपुराया सहारनपुर से लेकर आयेगा। इसलिए चोरी से बेचने के लिए वे ऐसा करते है। चोरी को खत्म करने के लिए बराबर के प्रदे ा जैसी सेल्ज टैक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। यहां आठ परसैट है तेा वहां सात परसैट हैं यहां पर 10 परसैट और 12 परसैट तक अैक्स की चोरी हो रही हैं मिसाल के तौर पर पानी की टूटी की कीमत पचास रूपये है, उस पर 6 रूपये सेल्ट टैक्स बनाता हैं अगर कोई कार वाला आदमी सौ टूटियो बाहर से ले ओय तो छ सौ रूप्ये का सरकार को नुकसान हुआ। यह उसेन चोरी इसलिये की कि बाराबर की स्टेट में टैकस कम है इसलिये हमारी स्टेट में भी सेल्ज टैक्स बराबर का होना चाहिए, ज्यादा नही होना चाहिये।

चेयरमैनप साहब, अम्बाला भाहर ओर छावनी के बची में टूरिस्ट कम्पलैक्स बन रहा है यह बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। अच्छा टूरिस्ट कम्पलैक्स होगा तो सरकार को भी लाभ होगा।

अपोजी ान के भाईयों ने 23 तारीख को सड़कों के किनारे से दरख्तों को काट कर सड़कों पर गिराया जिसके कारण सड़क पर रूकावट खड़ी कर दी। ऐसा करने से प्रदे ा को भी नुकसान हुआ और आने जाने में रूकावट हुई। अपोजी ान के भाई आज यह नही समझते है कि प्रदे ा में क्या कुछ हो रहा है।

जिस लोगों न उन्हें चुन कर भेजा है उनकी तकलीफो को यहां ब्यान न करके, हाउस से बाईकाट करके बाहर चले गये। ये लोग जनता की क्या नुमाइन्दगी करेगे। उनकी नुमाइन्दगी तभी बनती है जब वे यहां आ करलोगों की तफलीफे बताये। चेयरमैन याहब, 26. 2.86 को बन्ध का प्रोग्राम बनाया हुआ था। अपोजी ान के भाईयों ने लोगों से जोरदार तरीक`से चन्दा इकट्ठा करना भुरू कर दिया। 25 तारीख केा अखबार में निकाल दिया कि हम हड़ताल नही करेगे, बन्ध में भागमिल नही हेागे लेकिन वे लोगों से लाखो रूपए इकट्ठा कर ले गये। उस पैस का क्या बनेगा, वैसे ही इजम हेाग। न्दि्ू सुरक्षा समिति, संघर्श समिति तथा बी0 जे0 जी0 ने यह पैसा इकट्ठा किया जिनमें अब बन्ध में भी भागमिल नही हुए।

एक बात मै ओर अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार ने दोहरे काय्र के लिए वि ोश भत्ता चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिए जाने का फैसला लिया हैं जिसके अनुसार सेवादार एंव चौकीदार, सेवादार एवं माली तथा चौकीदार एवं माली के दोहरे पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को तीस रूपय प्रति मास के हिसाब से वि ोश भत्ता मिलेगा। लेकिन इसमें चौकीदार कम सफायी कर्मचारी के पद का नाम नही लिखा है। इसलिए मचौकीदार कम सफायी कर्मचारी को भी तीस रूपये दिये जोन चाहिए।

चेयरमैन साहब, हरियाणा में हरिजनों की रिर्जव प्राइस पर प्लाट दिये जाये और खाततौर पर भाहरों में ताकि वे भी

भाहरों में ताकि वे भी भाहरेां मे रहे सके। आखिर में मै चेयरमैन साहब, आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझ बोलेने के लिए टाईम दिया। मै इस बजट का समर्थन करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी हुक्म सिंह (साल्हावास): चेयरमैन साहब, हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे वित्त मंत्री श्री सागर राम गुप्त जी ने कल वर्श 1986–87 का बजट अनुान रखा, मै उनका धन्यवाद करता हूं और उसका समर्थन करनेके लिये खड़ा हुआ हू। सबसे पहले मै आपका धन्यवाद करता हू और उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं सेसबे पहले मै ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं वर्श 1985–86 मे प्रति व्यक्ति की आय में 7–7 प्रति ात वृद्धि हुई है और आमदनी 3296 रूपये के स्तर तक पहुंच गयी है। यह एक बहुत ही सराहनीय बात है इससे यह जाहिर होता है कि आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान को ओर मजदूर को पिछले बजट में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है। और उसी तरह से इस मौजूदा बजट से जिसका हम समर्थन कर रहे है, फायदा पहुंचेगा। इस में यह द ार्या गया है कि हरियाणा सरकार ने देहातों में जनता की हर प्रकार की सहायकत की हैं जनता को हर प्रकार की आव यक वस्तुए उचित कीमतों पर मुहैया करवाने के लिये देहातों में 6800 सस्ते रेट की दुकान खोल रखी है। इनसे गरीब मजदूर तबके के लोगां को वि ोश फायदा हुआ हैं इन दुकानों से 10 किस्म की रा ान की चीजे मिलती है।

इस प्रकार से हमारा कृशि प्रधान प्रदे ा होने के नाते से हमारे किसान ओर मजदूरों को आज पानी की और बिजली की वि ोश जरूरत रहती हैं हमारी सरकार ने हर किसान ओर हर मजदूर को भावना को समझते हुए चालू पंचवर्शीय योजना में यानी सातवी योजना में बिजली के लिये एक हजार करोड़ रूपये और सिचांई के लिए 585 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है मै समझता हूं कि यह हमारे प्रांत के हर किसान और मजदूर के लिये एक बहुत ही अहम बात है। इससें हरके किसान ओर मजदूर को फायदा होगा क्योंकि आने वाले साल के बजट मे भी सरकार ने कुल 525 रूपये में से सिचाई के लिये 169 करोड़ रूपया ओर बिजली के लिये 163 करोड़ रूपया रखा है इसके माध्य में जा पुराने काम चले आ रहे है और बची में अधूरे पड़े है एक तो उनको पूरा किया जायेगा और दूसरे जो नीय स्कीमें भुरू करने की योजना बनाई गयी है, वह भी भुरू होगी। मै अपने हल्के की तरफ से इन दोनों मुद्दों यानी सिचाई और बिजली के बोरं में भी सरकार से निवेदन करूंगा। मेरे हल्के साल्हावास में गाव मातनहेल मैं 132 के0 वी0 सब स्टे ान पर काम पिछले एक साल से चल रहा है। जिसका 40–50 परसैन्अ काम पूरा हो चुका है। मेरा कहना यह है कि यह 132 के0वी0 सब–स्टे ान का काम आने वाले साल यानी 1986–87 में पूर कर दिया जाये ताकि वहां के आस पास के करीब 15–20 गांवों को वि ोश फायदा हो सके। इसी प्रकार से मेरे यहां पर एक कोसली गांव में 132 के0 वी0 सब–स्टे ान बहुत पुरान बना हुआ है इसके साथ ही एक

बहुझोलरी गांव मे ंभी 33 के0 वी0 सब स्टे ान बना हुआ हैं वहां पर ट्रांसफार्मज पर लोड बहुज ज्यादा पड़ता है जिसकी वजह से वहां परटयूबवैल और घरां को लोड वे एक साथ बर्दा ात नही कर पाते। यहां पर ट्रांसफार्मज बहुत जल्दीजल जाते है। मै आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि 132 के0 वी0 का पावर सब स्टे ान कोसी में 33 के0 वी0 का बहुझोलरी में 16–16 एम0 वी0 ए0 का लगाकर वहां के किसानेां को सुविधा दी जायें इससे आपका सारा सिस्टम ठीक हो जायेगा ओर जो ओवरलोड है, वह भी ठीक हो जायेगा।

इसी तरह नहर के मामले में मै यह कहना चाहता हूं कि हमारे रेाहतक जिले के बीच में से जे0 एस0 बी0 ओर जे0 एल0 एन0 नहर एक साथ गुजरती है। चेयरमैन साहब जे0 एस0 वी0 काफी पुरान नहर बनी हुइ हे। कुछ तो उसके वैड्ज मिट्टी से भर गये है ओर साथ ही वाहं पर सीपेज भी बहुत होती है इससे साथ लगते 10–15 एकड़ या आपयो कह लीजिये कि एक सवा किलोंमीटर तक किसानों की जमीन बरबाद हो गयी हैं आम आमदी की यह मांग है कि इसकों पक्का किया जाये। इसके लिये लोग आई0 पी0 एम0 साहब से ओर चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले थे। मैने पिछले बजट सै ान में भी यहां पर यह मांग रखी थी कि किसानों की सुविधा के लिये, किसानों की जमीन को उपजाऊ बनाये रखने के लिय और उनकों बरबाद होने से बचाने के लिये जे0 एस0 बी0 नहर को पक्का किया जाये। उस नहर मे

सीपेज और लेकेज इतनी रहती है कि न तो उस जमीन में अशाढी की फसल हेा सकती ै और नह ही सावनी की फसल की बीजाई हो सकती है इसलिये मै एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि 1986–87 वर्या में इसको ंपक्का करने के लिये अगर पूरा प्रावधान नही कर सकते तो कुछ थोड़ा बहुत पैसा जरूर दे दिया जोय ताकि इस स्कीमताकि इस स्कीम पर काम चाले किया जाये। नहर जे0 एल0 एन0 की लम्बाई 140 किलोंमीअर के करीब है। यह नहर 1967–77 में बन कर तैयार हुई थी ओर इसके बनोन पर हरियाणा सरकार का 72 करोड़ 88 लाख रूपया खर्च हुआ थ। इसके माध्यम से 124 लिफ्ट स्कीम्ज बनाई गयी है। इसका पानी राजस्थान की सीमा तक पहुंचता है। जिसमें महजेन्द्रगढ़, भिवानी, रोहतक और गुडगांवा जिला आता हैं साल्हावास पम्प हाउस जो एि िया का सबसे बड़ा पम्प हाउस है। ये लेकर राजस्थान की सीमा तक 249905 हैक्टेयर जमीन की यह नहर सिंचाई करती है। साल्हावास से लेकर राजस्थान सीमा तक हमारे प्रांत के अन्दर महेन्द्रगढ जिले में जोकि काफी ऊंचाई पर है इतनी ऊंचाई पर भी यह नहर लिफ्ट स्कीम द्वारा जमीन की सिंचाई करती है। इसके अलावा जैसे हमारा एस0 वाई0 एल0 का खुदाई का काम चल रहा हैं और विरोधी भाई हमारी पार्टी के खिलाफ ओर हमारी सरकार के खिलाफ अपनी जाति मुफाद के लिये देहातों मे जाकर लोगों को बरगलाते हैं उन्हें ये कहते है कि यह नहर तैयार नही होगी। और एस0 वाई0 एल0 का पानी हरियाणा प्रांत को नही आयेगा वे कहते है कि कांग्रेस सरकार अपना दायित्व नही निभारही है इसक

अलावायह भ कहते है कि चौधरी भजन लाल की सरकार ने हरियाणा प्रांत के साथ धोखा किया है औरपूरा पानी नही लिया हैं मै आपके माध्यम से अनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 1976 में जे0 एल0 एन0 कैनाल तैयार हो गई थी। चौधरी बंसी लाल की मेहनत से यह नहर बनी थी औरयह नहर इस उद्दे य से बनाइ गई थी कि एस0 वाई0 एल से जो पानी आएगा उसपानी को इस नहर के द्वारा डेजरटिड एरिया का दिया जाएगा। 1977 में कांग्रेस पार्टी लूज कर गई अैर जनता पार्टी का भाासन आ गया। चौधरी देवी लाल उस वक्त हरियाणा के मुख्य मंत्री थे और सरदार प्रका ा सिंह बादल पंजाब स्टेट के मुख्य मंत्री थे। इस नहर पर 72 करोड़ 88 लाख रूपया खर्च हो चुका था अैर 1976 में एस0 वाई0 एल0 के पानी को लेज ने की व्यवस्था हो गई थी तो यह बात चौधरी देवी लाल ने श्री बादल के साथ क्यों नही उठाई? इस नहर का काम चौधरी देवी लाल ने क्यों उठाया? क्यों नही सोचा गया कि एस0 वाई0 एल0 न बनने से हरियाणा के किसान का नुक्सान होता है। चेयरमैन साहब जे0 एल0 एन0 नहर पर इतना अधिक पैसा खर्च किय गया लेकिन आज वह नहर यों ही पड़द्यी है उसका कोई इस्तेमाल नही होता। हमारे आदरणीय चौधरी देवी लाल यह सोचते कि हरियाणा के किसान के ऊपर उठाने के लिए एस0 वाई0 एल0 का पानी पंजाब से लोते तो आज यह समस्या पैदा नही होती। उस समय यह स्कीम सिर्फ 45–46 करोड़ रूपये मै तैयार हो जानी थी। आज इसकों तैयार करने में 240–245 करोड़ रूपये चाहते है। आगे आगे मंहगाई बढतीहै भाायद कीमत

और भी बढ़ जाये जिससे प्रांत का ही नुक्सान होगा। उस वक्त आसानी से पानी लाया जा सकात था। उस वक्त आसनी से नहर खु सकती थी। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, चोधरी देवी लाल ने इस बारें मं कोई कश्ट नही किया। अध्यक्ष महोदय, राजीव लौगेवाल के बची जो फैसला हुआ उसके अनुसार 15 अगस्त 1986 को नहर तैयार हो जातनी चाहिए लकिन जैसा कि आई0 पी0 एम0 साहब की मारफत पता लगा है उस नहर का काम उस गति से नही चल रहा है जिस गति से वह चलना चाहिएघ। हमें अब संदेह पड़ता है कि 15 अगस्त, 1986 तक यह नहर तैयार नही हो सकतेगी। अध्यक्ष महोदय, मै सरकार से और चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि जितना अधिक से अधिक दबाव वे भारत सरकार पर डाल सकते है। कि वह इस काम को अपने हाथ में ले, वे डाले। इसमें कोई भाक नही है कि वे अब भी बहुत अधिक दबाव डाल रहे है लेकिन मेरी प्रार्थना है कि वे और अधिक दवाब इस बात के लिये डाले कि इस नहर के काम को केन्द्रयी सरकार अपने हाथ में जितना जल्दी हो सके लो। मै परमात्म से भी प्रार्थना करत हूं कि चीफ मिनिस्टर अपने मि ान कामयाब हो और भारत सरकार इस नहर के काम को अपने हाथ में लो ले, नहर जल्दी तैयार हो और किसान के खेत में जल्दी से जल्दी पानी पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय, अब मै प ा पालन के बारें में कहना चाहता हूं। 1986–87 में सरकार चालीस नई वेटरीनरी डिस्पैन्सरीज

बनएगी, तीस डिस्पैन्सरीज को अस्पताल के रूप में बदलेगी ओर एक पोलीक्लीनिक खेलेगी। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूंकि मेरा हल्का साल्हावास काफी पिछड़ा हुआ है। वहां के लोग खेती बाड़ी करते है लेकिन पचास प्रति ात लोग प ा पालन का काम करते है मेरी प्रार्थाना है कि मेरे हल्के के गांव गोरिया, झांसवा, सेहलांगा अैर रेहडूवास में प ा डिस्पैन्सरीज, अस्पताल, सब सैन्टर या प ा चिकित्सा की कोई दूसीर सुविधा प्रदान की जाए जिससे कि किसान का फायदा हो सके ओर किसान आत्मनिर्भर हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, अब मै सहकारिता के बारें में आपकी मारफत सरकार से कहना चाहता हूं। सहकारिता का काम सारे प्रदे ा में बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। किसान ओर मजदूर सहकाारिता के माध्यम से बड़ा फायदा उठा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, बजट में भी जिक्र आया है और राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में भी कहा गया था कि उठारह भूमि विकास बैंक किसान की सेवा के लिये खोले है। मेरे हल्के में भी एक बैक खोला गया है उसके लिए मै सरकार का धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष महोदय ,मै सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि देहात में आए दिन ि ाकायत मिलती रहती हैं कि बैक से डीलर को सीधी पेमैट होती है किसान को पेमैंट नही होती। मेरी सरकार से प्रार्थना कि इस एक्ट में अमैडमैट की जाए। किसान को या तो सीधी पेमैट की जाए या कोई और रास्ता अपनाया जाए कि जिससे डीलर किसान को

इतनाबाउन्ड न करे ले क वह किसान का पैसा लेकरभाग जाए। आम ि ाकायत यह है कि किसान दस्तखत करके डीलर को देता है जिसके माध्यम से वह सामान होताहै कि उसकी पेम्ेट डीलर को कर दी जाए और डीलर को पेम्ेट हो जाती है डीलर भोले भोले किसान की वृद्धि का नजायज फायदा उइा लोत है और उस किसान का अंगूठा लगवा लेाता है और पैसा लेकर भाग जाता है। मेरी कोसली गांव में आठ दस केसिज ऐसह`हुए है जिनमें डहलर किसान की पेमैंट बैंक से लकर भग या। किसान डीलर की मारफत इसलिए समान लेता है कि कानून यह है कि जो लोन सैक ान हुआ है उसके अगैन्सट उसी डीलर से, जो बैक ने नौमिनेट किया है, सामान लेना पडेगा। डील र इस बात के दस्तखत करा लोत है कि किसान ने पूरा सामान ले लिया है। इस धोखाधड़ी से किसान को बचाने के लिए मेरी सरकारसे प्रार्थना है हकि कानून में अमैडमैट की जाएं जिस तरह से किसान को बाउन्ड किया जाता है उसी तरह सै डीलर को भी बाउन्ड किया जाएसं जब किसान इस धोखाधड़ी के खिलाफ कोर्ट में जात है तो फैसला उसके खिलाफ होात है क्योंकि उसने पहले ही लिखकर दिया होता है कि उसने सामान ले लिया है। इसलिये कानून में अमैडमैट की जाए ओर किसान को डीलर के चुंगल से बचाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अब मै उद्योग के बारें में कहना चाहता हूं भारत सरकार से हरियाणा में कोइ ए क्लास औद्योगिक बैकवर्ड

एरिया घोशित नी है बी0 एण्ड सी0 क्लास औद्योगिक बैकवर्ड एरियाज भारत सरकार की ओर से घोशित है। मेरे हल्के में एक पुरानी तहसील नहाड़ थी जिसकों कोसली तहसील बना दिया। भारत सरकार की तरफ से वही पुरानी तहसील नहाड़ को बैकवर्ड एरिया घोशित कर दिया गया। मेरी सरकारसे प्रार्थना है कि नाहड़ की जगह कोसली को बैकवर्ड तहसील घोशित किया जाए ओर इसके तहत लोगो को इंडस्ट्री लगाने की सुविधा प्रदान की जाए। वहां के नौजवानों को काम देने के लिये वहां पर कोई फैटरी लगाई जाए ताकि उस एरिया की उन्नति हो सके ओरवहां के लोग आत्म निर्भर हो सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मै सड़कों को बारें में कहनाचाहता हूं। यह ठीक बात है कि हमारे प्रदे ा में जितना काम सड़कों का हुआ है उतना कही नही हुआ। सड़कां के लिये सारे दे ा में हरियाणा की वाह वाह हो रही है दे ा में कोई ऐसा प्रांत नही है जहां हर गांव सड़क से जुडा हुआ हो। स्पीकर साहब, हमारे प्रांत में हर गांव तक सड़क पहुंची हुई है। 1986–87 के बजट के सड़कों पर 14.5 करोड़ रूप्या खर्च किया जाएगा और इस रूपए से 247 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय मेरे हल्के में भी कुछ सड़के ऐसी है जहां थोड़ा थोड़ा काम होना है। जैसे भयाम नगर से दूमना तक एक या डेढ किलोमीटर की सड़क है इसके बनाया जाए। दूसरी सड़क रेहडूवास से चढवाना तक की है जिसकाफासला एक किलोमीटर का है। अगर यह सडत्रक बना दी

जाए तो कोसली मण्डी और रिवाडी मण्डी आने जोन में लोगों को आसानी हो जाएगी। इसती तरह सेहलंगा से पातूवास का एक या डेढ किलोमीटर का फासला है जिसकां मिलाया जाए। दादरी मण्डी सेपातूवास तक पक्की सड़क पहले ही बनी हुई है औ इधर से बिरहोड से गांव सेहलंगा तक पक्की सड़क मिलाई हुई है। बीच में डेढ़ किलोमीटर का टुकडा मिलाया जाए जिससे लोगों का सुविधा मिले। ऐसा करने से दस बारह किलोमीटर का फासला कम हो जाता है। मेरी सरकारसे प्रार्थना है कि इन दो तीनटुकडों को जरूर मिलाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, ि ाक्षा के बारें में हमारे हरियाणा प्रांत ने बड़ी तरक्की की है, वह बड़ी प्र ांसनीय बात है। हमारे नौजवान जो हमारी आने वाली पीढी है, जिनके कन्धों पर इस दे ज्ञ का भारत है अगर वे ि ाक्षित होगे तो हमारे प्रांत का, हमारी बिरादरी का, अपने गांव का, अपने दे ाका नाम रो ान करेगे। इन सब बातों को मद्देनजर राते हुए हरियाणा सरकार ने सातवी पंचवर्शीय योजना में केवल लड़कियों के लिए 500 नये प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय किया है। इनमें से 100 स्कूल खुल चुके है अैर वर्श 1986–87 में 100 ओर स्कूल खोल दिये जायेगे। यह बड़ी खु ाी की बात है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से अपने इलाके के बारें में सरकार से यह कहना चाहता हूं कि गांव सेहलांग वासियों ने दो तीन लाख्य रूपया इकटठा करकेएकहाई स्कूल खोलने के लिए बिल्डिग बनायी है। ओर उसमें

14—15 कमरे भी तैयार कर दिये गये हैं उन लोगों की यह रिकवैस्ट है कि वहां मिडल से हाई स्कूल बनना चाहिये। इसी तरह से एक दूमना गांव है वहा पर मिडल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाना चाहिये। वहां के लोगों ने भी आपस में चन्दा इकट्ठा करके ए बिल्डिग तैयार की है इसी तरह से गांव खचरौली, कालियावास और नोगांवा के लोगो ंने अपने पास से चन्दा इकट्ठा करके बिल्डिग तैयार की है और यह मांग की है कि वहां पर जो प्रामरी स्कूलज है, उनका दर्जा बढ़ाकर मिडल स्कूल किया जाए। इसलिये मेरी सरकार से करवेस्ट है कि इन गांवों के लोगों को और ि ाक्षित बनाने के लिये इन प्राइमरी स्कूलों के दर्जे को बढ़ाकर मिडिल स्कूल बना दिया जाए। इसी तरह गांव बिरोहड़ में भी लागो ंने साढत्रे सात लाख रूपए इकट ठे किये है और वहां पर एक हाई स्कूल चल रहा है। उस बिल्डिग में कम से कम 25—26 कमरे तैयार पड़े है उस गां के लोगों की यह प्रार्थना है कि वहां पर 10+2 सिस्टम भाुरू करवा दिया जाएं पिछले दिनों सिंचाई एवं बिजली मंत्री श्री सुरजेवाला जी वहां पर गये थे उन लोगें ने मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की थी औ मैने भी उनकों यह वि वास दिलाया था कि इस बतट में अगर व्यवस्ाि रहेगी तो उस स्कूल में 10+2 सिस्टम भाुरू करवा दिया जाएगा। तो मै सरकार से आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि बिरोहड़ के हाई स्कूल में 10+2 सिस्टम चालू किया जाए।

सरकार ने स्वास्थ्य के बारें में भी काफी सराहनीय काम किये है। 1986–87 के दौरान 150 उप–स्वास्थ्य केन्द्र, 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है। मै आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के के एक गांव विरोहड़ मे ंएक रूरल डिसपैन्सरी लगभग 18–20 सालां से चल रही है। ओर उस गांव की जनसंख्या 8–10 हजार के लगभग है। उन लोगो ंकी मांग हे कि उसका दर्जा बढ़ाकर वहां परएक माडन्र प्राइमरी हैल्थ सैंटर बनाया जाए। इसी तरह से गांव गोरिया, भूरावास झांबरी ओर भााामनगर के लोगों ने जमीन भी दे रखी हैं लोगों की यह मांग है कि इन गांवों में भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलबध हो सकें और लोग इनसब केन्द्रों का पूरा पूरा फायदा उठा सके।

इससे आगे मै जन–स्वास्थ्य के बोरं में आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा और सरकार का धन्यवाद भी करूंगा कि सरकार ने मेरे हल्के साल्हावास जिससे लगभग 78 गांव है जिनमें सिर्फ 40 गांवों को 1982 में पीने के पानी की व्यवस्था थी। 38 गावों में हमने 1982 के बाद कराई और जो स्कीम पहले से चालू थी परन्तु सन्तोशजनक कार्य नही था उसकौ भी ठीक कराया और आगे बढ़ाई। अब 100 प्रति ात मेरे इलाके में पीने के पानी की ठीक व्यवस्था है। सरकार ने मेरे भोश इलाके के लिये लगभग चार साढ़े चार करोड़ रूपया दिया है। मुझे खु ाी है कि सरकार ने हम पर ऐसा करके बड़ा भारी एहसान किया है मै इसके लिए

सरकार का आभारी हूं क्योंकि वहां पर पीने कापानी बहुत नीचा था और खारा थाअब सरकार की अच्छी पोलिसी के अनुसार उस इलाके के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सरकार से यह भी रिकवैस्ट करूंगा कि जितनी स्कीम्ज पिछल तीन सालों से चल रही है, वे बची मे ंही लटकी पड़ी है, उनको पूरा किया जाएं। तहसील कोसली ओर सब तहसील मात नेहल दोनों में 140 गांवों को सूखा ग्रस्त घोशित किया गया था। इस इलाके के लोगों को रहात पहुंचाने क लिये डी0 सी0 साहब ने 35 लाख रूपये का प्लान बनाकर सरकार के पास भेजा था ताकि तकावी के लिये ओर प ुाओं के चारे वगैरह के लिए और लोगों की मदद के लिएयह पैसा दिया जा सके उसमें से केवल 15 लाख रूपये की रा ि ा लोगों में वितरित हो चुकी है। इसलिये मेरी रिकवैस्ट है कि भोश राशि भी लोगों को जल्दी ही दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और मै आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि मेरे हल्के में साल्हावास ओर नाहड़ दो बडऋे ब्लौकस है। नाहड खण्ड में 75 गांव पड़ते हे। अैर साल्हावास खण्ड में 80 के गरीब गांव आते है। दोनो को मिलाकर लगभग 155 गांव बनत है ब्लौक साल्हावास के गांव जैसे कि माछ रौली और लुहाडत्री खेड़ी काफी दूर है। ये लगभग 55 किलोंमीटर के फायले पर है और इसी तरह से नाहड ब्लौक के गांव छूछकवास, नाहड, ढानी गवालीसन वगैरह लगभग 30–40 किलोंमीटर दूरी

परह`। इस बोरं में मैने एक स्कीम बनाकर चीफ मिनिस्टर साहब को दी थी जिस परची से कमैन्ट्स भी मांगे गये हैं इन दोनों खण्डों में से कुछ गांव निकाल कर तीसरा ब्लौक बनाया जाए ताकि लोगों को रोजमर्रा की आव यकताओं की चीजे लेने के लिये दूर न जाना पड़े और लोगों हर तरह की सहूलियते नजदीक में ही उपलब्ध हो सके। मुझे पूर्ण आ ाा है। कि सरकार अव य ही मेरे इन सुझावों पर विचार करेगी औ जो जो सुझाव मैने यहां सदन में दिये है उनकों जल्द ही पूरा करने का प्रयत्न करेगी। इन भाब्दों के सथ्ज्ञ मै आपका धन्यवाद करत हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया अैर साथ में इस बजट का जो कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यहां सदन में प्रस्तुत किया है, भारी समर्थन करता हूं कि यह बहुत अच्दा बजट है। इससे किसानों पर और दूसरी आम जनता पर किसी प्रकारका कोई बोझ नही पड़ेगा। धन्यवाद।

चौधरी लीला कृश्ण (फतेहाबाद): स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, मै आपका धन्यवादी हूं। मै 1986–87 के बजट ऐस्टीमेट्स जोकि हमारे आदरणीय एफ0 एम0 साहब ने इस सदन में रखे है, का पूर्ण समर्थन करता हूं और उस पर अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। मै यह बात कहने में गुरेज नही करूंगा कि इस से बैटरबजट नही बनाया जा सकता था जाकि मुख्य मंत्री महोदय जी की देखरेख में बनाया गयाहै। सचमुच मे ही वे बधाई के योग्य है। एफ0 एम0 साहब, ने सब से पहले एस0 वाई0 एल0 के बारें में बताया है। मै समझता हूं कि

यह हरियाणा की जिन्दगी और मौत का सवाल है। स्पीकरसाहब, मै सदन को वह दिन याद दिलाना चाहात हूं जब हरियाणा को 3.5 एम0 ए0 एफ0 पानी मिला था और हरियणा के अन्दर खु ाी की लहर दौड़ गयी थी। यहां पर दीपावली मनायी गयी थी। और हरियाणा को यह पूरी आ ाा थी कि हमें पानी मिलेगा ओर हम तरक्की की दि ाशाओं को चूमेगे। स्पीकर साहब, हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाधी ने एस0 वाई0 एल0 कैनाल की खुदाई के काम का उद्घाटन कपूरी गांव में किया था उस वक्त यह कहा गया था कि दो साल के अरर्से मं यह नहर कम्पलीट हो जाएगी। मै तो यह कहने से भी गुरेज नही करूंगा कि इंदिरा जी ने हरियाणा के हितों के लिए आना बलिदान दिया है। उस समय पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्री वहां विराजमान थे अैर माना गया था कि दो साल में यह नहर कम्पलीट हो जाएगी लेकिन पंजाब वाले अपने वादे से पीछे हट गये। स्पीकर साहब, इस बारें में हमारे मुख्य मंत्री जी ने तथा सदस्यों ने भी बहुत प्लीडिग की,संघर्श किया परन्तु उसका जो हल निकलना चाहिए था। वह नही निकला। मुझे यह समझ नही आती कि यह नया इरैडी कमि ान क्यो बनाया गया है। जब हमें एक बार 3.5 एम0 एफ0 पानी मिल चुका है तो उसकों क्यो घटाया गया। लेकिन अब चूंकि यह कमिशन बना दिया गया है इसलिये मै समझता हूं कि हामर सरकार अपना केस प्लीड करके पूरा पानी लेगी। जितना पानी हमें श्रीमती गांधी ने घोशणा की तो उसे बाद पंजाब में उग्रवाद पना ओरहमारी खिलाफत की गई। उस वक्त मेरे खिलाफ पैटी ान हो

ई थी और मेरे खिलाफ फैसला हो गया था, मै एम0 एल0 ए0 नही रहा था। उस वक्त हमारे सामने बहुत समस्याएं थी। जब हम उन समस्याओं को याद करते है तेा हमारे रोंगटै खडे हो जाते है। उन दिनों मुख्य मंत्री ने हिसार में पब्लिकली घोशणा की थी जब मेरी गाड़ी के तीनआदमी मोटर साइकिलों पर चलते है तो मुझे डर लगता है कि कही कोर्ी उग्रवादी न हो। लेकिन पंजाब में जो आग लग रही थी उसकी आंच इन्होने हरियाणा में नही आने दी। मै अर्ज करना चाहता हूं कि इस नहर के बारें में जो रैजोल्यू ान हमने पास किया था कि राजीव जी की सरकार इस मसले को अपने हाथ में ले ले वरना नहर नही खुदेगी और हमें हमारा हिस्सा नही मिलेगा। इसलिए मै मुख मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे पूरी कोि ा ा करके इस नहर का काम सैंटल गवर्नमैंट को सौपने के लिए प्रधान मत्री को सहमत करवाएं तब हमें उम्मीद हो सकती है कि हमें अपने हिस्से का पनी मिलगा। मै यह भी कहने में गुरेज नही करूंगा कि लौगोवाल एक संत को अैर वे पंजाब और हरियाणा के हितों क लिये कुर्बान हो गए लेकिन उन्होने जो राजीव जी के साथ समझौता किया था उसका आज निरादार हो रहौ। हमें उस समझौते के मुताबिक 83 गांव ओर दो टाउन मिलने थे, यह ठीक फैसला था अैर हरियाणा के मुख्य मंत्री को भी इस बारें में कन्फीडैस में लिया गया था लेकिन आज पंजाब में अकाली दल ओरउसे निर्दे ाक अपने डिक्टेटर और अपने प्रधान के समझौतक का निरादर कर रहे है। ऐसी मिसाल आपकों कही भी नही मिलेगीं पोलीटीकली यह न मानने वाली बात है कि कोई

आपने नेता की बात न मोन। हम तो चण्डीगढ़ को छोड़ने के लिए तैया बैठे है, ब ार्त हमें 83 गांव और दो टाउन मिल जाए। तो उस समझौते का निरादन पंजाब वालों ने खुद किया है,हमने नही किया। मै मुख्यम ंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस फैसले को तब मानें जब हमें पानी भी मिल जाए। पानी चाहे 6 महीने के बाद मिले या एक साल के बाद मिले, सरकार तभी यह फैसला लागू करवा। इस मसले पर मुख्य मंत्री जी द्वारा लिए गए स्टैड की वजह से उनकी बहुत मान इज्जत हुई है। उनके इस स्टैड को हरियाणा के लोग नही भूल सकते, वे आज हरियाणा के लिये दि ाा सूचक बन चुके है।

स्पीकर साहब, मै बजट पर आता हूं मै तीन साल तक परे ाान रहा। अब 6 महीने से अपनी सीट संभाली है। इस बजट में एग्रीकल्चर के लिए अच्छी धन रा ि ा रखी गई है क्योंकि भारत एक कृशि प्रधान दे ा है और यहां के 85 प्रति ात लोग किसान है। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पे ज्ञ किया हैं इससे बेहतर बजट और नही हो सकता था। इन्होने लगभग 3 करोड़ 70 लाख रूपए केवल एग्रीकल्चर के लिये रखे हे जिसमें से 1.68 करोड़ रूपए ग्रीकल्चर सैक्टर और 1.63 करोड़ रूपए पावर और 38 लाख रूपए एलाइड सविसिज के लिए है इतना अधिक बजट खेतीबाड़ी के लिए देना, यह एक आइडियल बजट है। यह बजट हरियाणा की द ाओं को बदल कर हरियाण की डिवैल्पमैट का बढ़ाएगा और हरियाणा आका ा को छूएगा। परन्तु एक बात मेरी समझ से बहहर

है आज अखबारों में भी छपा है कि सैन्टर का ग्रोथ रेट 5 प्रति ात है लेकिन वित्त मंत्री ने हमें बताया है हमारा ग्रोथ रेट 6 प्रति ात है। तो एक परसैन्ट ाक बहुत बड़ा अन्तर होता है। इसलिये मै। चाहूगा कि मंत्री जी सदन को बताएं कि क्या हम सैन्टर से भी ज्यादा उन्नति करेगे। मै आनी ओर से कामना करता हूं कि हम ज्यादा उन्नति करें लेकिन यह बात समझ से बाहर नजर आती है। अब मै अर्ज करूंगा कि हरियाणा सरकार न किसानो की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। किसानों पर जब भी कोइ मुसीबत आई, चाह फ्लड आया, चाहे ज्यादा बारि ाआई या कहत टूटा तो हर मुसीबत में हरियाणा सरकार ने किसानों की मदद की। सरकार ने किसानों को रियायते दी, कर्जे दिए और भारत सरकार से कम्पनसे ान लेकर बांटा। मुझें उम्मीद है कि हरियाणा के किसान इस सरकार को नही भुलाएंगे। आज अपोजी ान के लोग किसानों के सैटीमैट्स बदलने के लिये लगहे हए है। मै चाहूंगा कि हरियाणा के किसान को पूरी तरह से जागरूक रहना चहिए अज्ञैर किसी की बातमों में नही आना चाहिए। एक मुसीबत पिछले अगस्त क महीने में हम पर बाढ़ की भी आई थी। खास कर फतेहाबाद में, कोइ भी कच्चा मकान नही बचा था। वहां पर गरीब आदमियों की जितनी कलोनीज थी वे सब डूब गई थी। मुख्य मंत्री जी मौके पर कई गांवों में गए थे और सम्बन्धित विभागों के अफसर भी वहां भेजे गए थे। इस बारें में पिछली बार भी मैन एक काल अटैन्ान मो ान दी थी जो मंजूर नही हुई थी उसका मै गिला नही करता इस बार भी मैने एक

काल अटैन्ान मो ान दिया है। मै चाहता हूं कि वहां पर जो कालोनीज है उनको रैगुलेराईज किय जाए। वहां पर गरीब हरिजन और डिस एबल्ड आदमी रहते हे। मै महाजन साहब से भी रिक्वैस्ट करूंगा कि वे उन कालोनीज का खास ध्यान रखे।

श्री अध्यक्षः लीला कृश्ण जी आप कन्टीन्यू करेगे। अब हाउस बाद दोपहर 2—00 बजे तक के लिए एडर्जन किया जाता है।

(तत्प चात सदन बुधवार दिनांक 26.2.1986 बाद दोपहर 2 बजे तक के लिये स्थगित हुआ)

ANNEXURE

Double link roads

***1107 Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Public Workds (B & R) be pleased to state the names of villages, constituency wise/circle-wise which have been provided double link roads so far in the state and the names of the villages which are likely to be connected with double link roads during the year 1986-87?

Public Works Minister (Sh. Amar Singh): It is not possible to submit reply constituency wise as well as circlewise as some of the constituencies fall under the jurisdiction of two cricles. However, district-wise/constituency-wise details of village provided with doublde link roads upto 31st January, 1986 is as per statment ecclosed.

836.82 Kms. length of double link roads for 574 villages is under construction as on 1st February, 1986. It is not possible to specify exact number of villages likely to be provided with double links during 1986-87.

STATEMENT

District wise/constituency wise detail of village provided with facility of duble link roads upt 31st January, 1986

Sr. No.	Name of District/Constituency	Name of Village
1	2	3
	Ambala District	
1.	Kalka	1. Khatauli 2. Nagal 3. Chhoti Khori 4. Wasulpur
2.	Naraingarh	1. Ganauli 2. Mandlai 3. Bhood 4. Hussani 5. Narainpur

		6. Rampur 7. Nayagaon 8. Raiwali 9. Bari Berheri 10. Badhouli 11. Rasidpur 12. Khanpur-Brahma 13. Rampur
3.	Sadhaur	1. Makar 2. Gianwala
4.	Chhachrauli	1. Makaur 2. Bahrampur 3. Bakarpur 4. Mukarrampur 5. Dadupr 6. Chintpur 7. Chhachhrauli 8. Lalheri Kalan 9. Amadalpur

5.	Jagadhri	1. Jandehra 2. Guglon 3. Maggarpur 4. Bhagwanpur 5. Hangoli 6. Sailba 7. Jhar chandana 8. Kalawar 9. Amadalpur
6.	Yamuna-Nagar	1. Chhota Kerena 2. Tigri 3. Kansepur 4. Kansli 5. Ratauli
7.	Mullana	1. Tangail 2. Dhanaura 3. Bihta 4. Ghasitpur 5. Mullana

		6. Jharoo Majra 7. Sohana 8. Kesri
8.	Amabal Cantt	Nill
9.	Amabal City	Nil
10.	Nangal	1. Ahma 2. Quarbanpur 3. Bara 4. Tharwa 5. Babaheri 6. Kot-katchwa 7. Baraula 8. Barauli 9. Nanhera 10. Akbarput 11. Samalkha 12. Chudiala 13. Khanpur
	Karnal District	

11.	Indri	1. Uchana 2. Gheer 3. Mohidinpur 4. Mugal Majra 5. Gumthala Rao 6. Chugaon 7. Biyana 8. Baragaon 9. Landora 10. Makhali 11. Kalri Jagir
12.	Nilikheri	1. Sagga 2. Raison 3. Barsula 4. Bhola Khalsa 5. Gholpur 6. Naraina 7. Laliani 8. Bir Naraina

		9. Taraori 10. Kher 11. Bir Badalwe
13.	Karnal	1. Bajida Jattan 2. Bhusli 3. Kurak 4. Jatpura 5. Rukanpur
14.	Jundla	1. Uplana 2. Uplani 3. Rattak 4. Jani 5. Budanpur 6. Zarifabad 7. Kachwa 8. Bhojpur 9. Sambli 10. Nissing 11. Gander

		12. Seri 13. Katlhri 14. Alipur Viran 15. Karsa Chor 16. Dachar 17. Sheikhupura 18. Brass sitamati
15.	Gharaunda	Arainpura Choura Babarpur Rajapur Ganjbar Upli Gianpur Sohan Asulpur Modipur Khankwala Mohmoodpur

		Bazidurp Jaraul Khurd Ranwar Palheri Harsinghpura Garhi Khajur Kaimla Kalheri Jarauli Jamalpur Bhaumajra Katail Pipalwali Karwali Uncha Samans Ganjogarhi Malikpur Gadian Kailran Bastara

		Gianpura Amritpur Kalan Brana Jhinwarheri Malipur Sheikhupura Rasin Rasulpur Chundipur Sharifabad Dabarki
16.	Assandh	Malikpur Paban Hassanpur Mehmoodpur Dharamgarh Thirana Madlauda Joshi Ahmadpur Majra

		Rajapur Kachroli Assan Kalan Assandh Manpura Kurlan Anchala Balrangra Rear Kalan Kawi
17.	Panipat	Nil
18.	Sama;ljs	Dadola Dadoli Rishipur Bapoli nagla Babail Nanchra

		Ujha Udmi Jalmaan Bhajaur Sanjoli Simla Gujran Jalapur Beholi Raimal Naraina Bhapra Manana Mohati Dehra Atta Paneti Hathwala Budhanpur Rakshera

		Ferozpur
19.	Naulths	kakoda Urlana Damyana Seenk Sutana Brahman Majrs Sutana Brahman Majra Jondhan Kalan Kharad Bhupur Nain Alupur Kalkha Nanberi Bhrsham Didwari Balan

		Plaheri Chamrara Bandh Mandi Gawalra Puthar Bhandari Darapur Assan Khurd Kutani Damyana Atoula Urlana Khurd Kurana
	Kurukshetra District	
20.	Shahabad	1. Kherindwa 2. Machrauli 3. kurri

		4. Tangore 5. Patti Boripur 6. Nagla 7. Kheri Saidan 8. Gorkha
21.	Radaur	1. Kalwas 2. Birthala 3. Lakhmari 4. Bhowai 5. Mehra 6. Shahazadpur 7. Ram Nagar 8. Bhagwanpur 9. Gumthala 10. Kandoli 11. Kolapur 12. Mehcheri 13. Bandi 14. Nagla

		15. Nala Sadian 16. Jaguri 17. Jandola 18. Sangour 19. Mehwa Kheri
22.	Thanesar	1. Mirzapur 2. Kheri Saidan 3. Kheri Saidan
23.	Pehowa	1. Lukhri 2. Bhustla 3. Goledwa 4. Guldhra
24.	Gulha	1. Malipur 2. Ferozpur 3. Kawartan 4. Peharpur
25.	Kaithal	1. Khurana 2. Khanpur 3. Geong

		4. Serta 5. Keorak 6. Barout 7. Teak
26.	Pundri	1. Sarsa 2. Pindarsi 3. Pabnawas 4. Chandlans 5. Habri 6. Begpur 7. Khamoda 8. Jandola 9. Solumajra 10. Bandrana 11. Pharal 12. Kaul 13. Sakra 14. Teontha 15. Fatehpur

		16. Hajwlana 17. Sirsa 18. Achhanpur 19. Rasulpur 20. Deeg
27.	Pai	1. Khanuda 2. Rawanhera 3. Sherda 4. Kotra 5. Sega 6. Slimbalwali 7. Pai 8. Harsola 9. Jakhouli 10. Kasan 11. Rehra 12. Bakal
	Rohtak District	
28	Hassangarh	1. Morkheri

.		2. Kansala 3. Baliana 4. Pakasama 5. Kasranti
29.	Kiloi	Nil
30.	Rohtak	Nil
31.	Meham	Nil
32.	Kalanaur	1. Mokhra Khas 2. Nigana 3. Katesra 4. Ballab 5. Timpurpur 6. Patwpur 7. Garhi Ballab 8. Nigana 9. Pilana
33	Beri	1. Kabulpur

.		2. Chimni 3. Dharana 4. Majra 5. Malikpur 6. Dhaur 7. Beri
34.	Sahlawas	1. Jhanswa 2. Sudherana
35.	Jhajjar	1. Gijarod 2. Salodha 3. Aurangpur 4. Zahidpur
36.	Badli	1. Kharaman 2. Dulhera 3. Khungai 4. Kakrola 5. Munimpur 6. Pelpa 7. Sondhi

37.	Bahadurgarh	1. Ladrawan 2. Shidipur 3. Gubana 4. Parnala 5. Kairpur 6. Kulassi 7. Jassaurkheri 8. Kanoda
	Sonepat Disrtict	
38.	Baroda	1. Kohla 2. Gharwal 3. Baroda 4. Rindhana 5. Madina 6. Chhichhrana 7. Butana 8. Gangana
39.	Gohana	1. Samri 2. Bajana Khurd

		3. Kasandi 4. Dubeta 5. Salimpur 6. Roland Latifpur
40.	Kailana	1. Pugthala 2. Bajana Khurd 3. Kailana 4. Khubru 5. Sekhuputa 6. Khizarpur 7. Babarpur 8. Sitawali 9. Agwanpur 10. Ganaur 11. Atail 12. Bhora
41.	Sonipat	1. Panchi Jattan 2. Mehra 3. Karewari

		4. Juan 5. Bobla 6. Salimpur
42.	Rohtak	1. Nakloi 2. Kheri Dahiya 3. Saidpur 4. Jatola
43.	Rai	1. Akbarpur 2. Chhatera 3. Manoli 4. Khurmpur 5. Bandpur 6. Sadipur
	Jind District	
44.	Kalyat	1. Batra 2. Nandsingwala 3. Dhanuri 4. Haripura 5. Sanghan

		6. Gurthali 7. Bhana Brahmna 8. Lohar 9. SudkainKhurd 10. Kalaser
45.	Nawana	1. Dhmtan 2. Bhullan 3. Khardwal 4. Samin 5. Dhabi Tek Singh 6. Gulheri 7. Rasidon 8. Padarth Khera 9. Badowal 10. Dublain 11. Ismilpur
46.	Uchana	1. Kakrodh 2. Surbrah 3. Gogrian

		4. Kasoon 5. Makhand 6. Sandlana
47.	Rajound	1. Retoli 2. Dhatrath 3. Rohera
48.	Jind	1. Intal Khurd 2. Khunga 3. Barah Kalan 4. Barah Khurd 5. Sunder Pur 6. Bohatwla 7. Pindara
49.	Julana	1. Deorar 2. Bhamanwas 3. Lajwana Kalanb 4. Shamlo Khurd 5. Khem Kheri 6. Shamlo Kalan

		7. Jhamola 8. Padna
50.	Safidon	1. Malsheri 2. Hadwa 3. Butani 4. Didwaa 5. Bhushlana
	Faridabad District	
51.	Faridabad	Nil
52.	Meola Maharajpur	1. Faridabad 2. Tigaon 3. Badshahpur 4. Riwajpur 5. Bhjaopur 6. Fattupur 7. Ankhir 8. Shahbad 9. Bhajansrali

		10. Dabwa Pali 11. Sulakheri
53.	Ballabgrah	1. Atali 2. Mathuka 3. Chhainsa 4. Charora 5. Chandpur 6. Kira;o 7. Daua;[ir 8. Junhera 9. Sadarpur 10. Aterna 11. Panhera Khurd 12. Panchera Kalan 13. Garkhera 14. Fatehpur Biloch 15. Behhalpur 16. Ladauli
54	Palwal	Nil

.		
55.	Hassanpur	1. Khanmbi 2. Paingllthu 3. Barka
56.	Hathin	1. Andhoop Sondh 2. Kondal Gehlab 3. Tiri Brahman 4. Bamnola Jogi 5. Alimeo 6. Pausar 7. Bahin Phari 8. Manpur 9. Mhiluka 10. Kot
	Gurgaon Distric	
57.	Feropur-Jhirka	1. Pingwa 2. Akbarpur 3. Papra-Papri 4. Dhana

58.	Nuh	1. Mohmadpur 2. Kotla 3. Nagine 4. Karhera 5. Sultanpur 6. Ter (Punchana) 7. Sarauli 8. Maluka 9. Ghagas 10. Shahpur
59.	Taoru	1. Sabras 2. Hasspur Taoru 3. Khanpur 4. Baldlaki 5. Ujjina 6. Karaikai 7. Sarai 8. Kota Khandeols
60	Sohna	1. Manesar

.		2. Naharpur-Kasan
61.	Gurgaon	1. Mankraula 2. Daurala 3. Caterpuri 4. Choma
62.	Pataudi	1. Duman 2. Yaqubpur 3. F. Nagar 4. Fazilpur 5. Daboda 6. Bisunda 7. Daba was 8. Shahpur-Jat 9. Muzafra 10. Rajpura 11. Mauzabad 12. Bhonkarka 13. Parasoli
	Bhiwani District	

63.	Badhra	1. MaiKalan 2. Jewali 3. Berla 4. Badrai 5. Unn
64.	Dadri	1. Dudiwala 2. Golpura 3. Sarupgarh 4. Imlota 5. Mehra 6. Chhappar 7. Rasiwas 8. Aehina
65.	Mundhal	1. Ghuskani 2. Mithathal 3. Talu 4. Gujrani 5. Nathuwas 6. Sui

		7. Balyali 8. Sakror
66.	Bhiwani	1. Goripur 2. Manheru 3. Dhana Narshan 4. Paluwas
67.	Tosham	1. Badal 2. Bangnwala 3. Dadam 4. Rewasn 5. Dhani Mahu 6. Endiwali 7. Dhab Dhani 8. Sharwa 9. Dinod 10. Deowr 11. Garnpura 12. Chhappar Jogian 13. Nigana Kalan

		14. Dhariwas 15. Simliwas 16. Maneserwas 17. Garanpura 18. Daryapur 19. Khawas 20. Bariwas 21. Jhulli 22. Salewala 23. hassan 24. Sagwan
68.	Loharu	1. Amirwas 2. Kalod 3. Shempura 4. Besri 5. Birsingwas 6. Jarwa
69.	Bawani Khere	1. Kunger 2. Siwara

		3. Ratera 4. Bohal 5. Talwandi 6. Badshhpur 7. Rupana 8. Dhani Khesla 9. Balyali 10. Dubeta 11. Chrnaud 12. Kauwas 13. Chirod 14. Bado Brahmana
	Hissar District	
70.	Barwala	1. Kumbha Khera 2. Latani 3. Kharkara 4. Parbhwala 5. Gabipur
71	Naraund	1. Badchhapr

.		2. Datta 3. Gurana 4. Patwar 5. Sisai 6. Lohari Raghu
72.	Hansi	1. Sisar 2. Kharbala 3. Dhanderi 4. Ramyan
73.	Bhattu Kalan	1. Jeora 2. Shamsukh 3. Kirara 4. Nangthala 5. Landhri 6. Kanoh 7. Kirmara 8. Ashrawan 9. Kalirawan 10. Sulikhera

		11. Sheikhpura Daroli 12. banawali 13. Chiberwal 14. Daroli 15. Chunli Klan 16. Bhodia Khera 17. Sadalpur 18. Chuli Bagrian 19. Chinder 20. Sarangpur 21. Khasa Mahajan 22. Khaakheri 23. Badopal 24. Gadil 25. Chuli Khurd
74.	Hissar	Nil
75.	?Ghirai	1. Ladwa 2. Pabra

		3. Daulatpur 4. Bhatla 5. Mehjid
76.	Tohana	1. Damkora 2. Nagla 3. Salimpuri 4. Bodhi
77.	Ratia	1. Talwara
78.	Fatehabad	1. Banawali 2. Bigher 3. Dhanger 4. Dhani Majra 5. Mohammadpur Rohi 6. Badopal 7. Dhajur Jatti 8. Jhalania 9. Palsar 10. Sehnal

		11. Alisader 12. Hizarawan Khurd
79.	Adampur	1. Ladvai 2. Sundawas 3. Kharia 4. Kohli 5. Kebrel 6. Dobni 7. Mingni Khera 8. Kirtan 9. Shahpur 10. Mallapur 11. Neoli Khurd 12. Ralwas Khurd 13. Siswala 14. Rawaslwas Kalan 15. Panihar Chok 16. Pattan 17. Tokas

		18. Kurri 19. Ludas 20. Gorchi 21. Mohbatpur 22. Mohalsara 23. Ghursal 24. Kutian Kheri 25. Bandaheri 26. Singhran 27. Dewa
	Sirsa District	
80.	Darba Kalan	1. Gillan Khera 2. Boadiwali 3. Jandwal 4. Mangala 5. Titukhera 6. Madho Singhana 7. Liwalwali 8. Modia Khera

81.	Ellenabad	1. Rania 2. Sultanpuria 3. Kariwala 4. Bani 5. Mithi Surera 6. Khari Surera 7. Mamera 8. Mangalia 9. Kharia 10. Ottu 11. Maujdeen
82.	Sirsa	1. Baidwala 2. Sikanderpur 3. Baruwali 4. Bharo Khan 5. Bajekan 6. Kanganpur
83.	Rori	1. Dadu 2. Dharampura

		3. Anandgarh 4. Lakkarwali 5. Daultpur 6. Jhorar Rohi 7. Bhiwan 8. Subakhera 9. Sukhchain 10. Jhiri 11. Panjmala 12. Risalia Khera 13. Banwala 14. Rhaishergarh 15. Bhuna 16. Kharia 17. Mena Khera 18. keherwala 19. Rampura Bishoian 20. Nohiyanwali 21. Odhan

		22. Chowanwali 23. Chekan
84.	Dabwali	1. Ganga 2. Jandwala Bisholan 3. Gobinghar 4. Rajpura 5. Assakherea 6. Tejakhera 7. Asskhera 8. Sukher Khera 9. Ahmedpur Darewala 10. Godika 11. Malikpura 12. Mathdadu 13. Khokhar 14. Naurang 15. Chormar Shera 16. Jalanana
	Maehenderarh	

	Distritct	
85.	Bawal	1. Bawal 2. Gujriwas 3. Pithanwas 4. Naichana 5. Bhandore 6. Daliaki 7. Benipur 8. Pathuhera 9. Rassiwas 10. Dalu Singh
86.	Rewari	1. Majra Gurdas 2. Sangwari 3. Budla 4. Balwas Ahir 5. Bhudpur 6. Pandniwas 7. Turkiawas

		8. Gokalpur
87.	Jatusana	1. Uchat 2. Bhagot 3. Dhanunda 4. Jharli 5. Mori 6. Bhoka 7. Aulant 8. Motla-Khurd 9. Lisan 10. Bas-dada 11. Kulana
88.	Mahendragarh	1. Pota 2. Notana 3. Bhandor 4. Bhalkhi 5. Nimbi 6. Chajjawas 7. Khoroli

89.	Ateli	1. Salarpur 2. Kalwari 3. Dublana 4. Kamania 5. Chapra Bibipur 6. Kharana 7. Kharani 8. Faizlipur
90.	Narnaul	1. Kultajpur 2. Hassanpur 3. Merli 4. Dhlera 5. Magot Binja 6. Panchnota 7. Mosnut 8. Thanwas